gradeup

Prep Smart. Score Better.

मासिक करंट अफेयर्स यूपीएससी और पीसीएस परीक्षाओं के लिए

सितम्बर 2019

www.gradeup.co

दैनिक सामयिकी यूपीएससी आईएएस की तैयारी के लिये

02.09.2019

1. **<u>सार्वजनिक क्षेत्र के दस बैंकों का चार संस्थाओं में विलय किया जाएगा।</u>**

- वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के दस बैंकों का चार संस्थाओं में विलय करने सहित बैंकिंग सुधार उपायों की घोषणा की है।
- इससे वर्ष 2017 में देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 27 (एस.बी.आई. और बी.एम.बी. के विलय के बाद 21) से घटकर 12 हो जाएगी।

सम्बंधित जानकारी

- विलय के प्रस्ताव की घोषणा वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले वैकल्पिक तंत्र नामक एक मंत्री स्तरीय पैनल के माध्यम से की गई थी।
- वर्ष 1998 में नरसिम्हा समिति ने सरकार से बैंकों का त्रि-स्तरीय संरचना में विलय करने की सिफारिश की थी-
- शीर्ष पर अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के साथ तीन बड़े बैंक
- आठ से दस राष्ट्रीय बैंक
- बड़ी संख्या में क्षेत्रीय और स्थानीय बैंक
- वर्ष 2014 में पी. जे. नायक समिति ने सरकार को राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों का विलय या निजीकरण करने का सुझाव भी दिया था।
- आर्थिक सर्वेक्षण यह इंगित करता है कि उभरते और मौजूदा उद्योगों दोनों को ऋण प्रदान करने में बैंकों की निरंतर विफलता के परिणामस्वरूप राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि में रूकावट आई है।

बैंक विलय का हालिया इतिहास

- पिछले वर्ष, सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा (बी.ओ.बी.) के साथ विजया बैंक और देना बैंक के विलय को मंजूरी प्रदान की थी जो 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी हो गई है।
- वर्ष 2017 में, भारतीय स्टेट बैंक में उसकी पांच सहयोगी बैंको और भारतीय महिला बैंक का विलय किया गया था।

बैंक विलय की प्रक्रिया

- विलय हेतु संबंधित बैंकों द्वारा केंद्रीय सहकारी समिति पंजीयक के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया जाता है।
- विलय की योजना पर विचार के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट और संबंधित सूचना के साथ आवेदन की एक प्रति आर.बी.आई. को भी भेजी जाती है।
- तब आर.बी.आई. जमाकर्ताओं के हितों के संबंध में योजना की जांच करता है और सी.आर.सी.एस. को अपना निर्णय बताता है।

विलय के कारण

- सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंको को नुकसान से बचाने के लिए विलय किया जाता है, जिससे ग्राहकों और वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित रखा जा सके।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंक की अनुपस्थिति में- विश्व के शीर्ष 50 सबसे बड़े बैंकों की सूची में केवल एक बैंक, वर्तमान परिदृश्य में हमारे द्वारा साझा की गई वैश्विक क्षमता को कम करके दर्शाता है।
- बड़े बैंक भी बेसल III मानदंडों का पालन करने में सक्षम होंगे।
- प्रौद्योगिक तालमेल: एक विशेष टोकरी में सभी विलय किए गए बैंक सामान्य कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (सी.बी.एस.) प्लेटफ़ॉर्म को तकनीकी रूप से समन्वित करते हैं।
- आत्मनिर्भरता: बड़े बैंकों में राज्य के खजाने पर भरोसा करने के बजाय बाजार से संसाधन जुटाने की बेहतर क्षमता है।

- ट्विन बैलेंस शीट संकट के आधार पर ऋण देने की समस्या की जाँच बड़े बैंकों के गठन से की जा सकती है।
- विभिन्न विभागों वाले बड़े बैंकों में विफलता की संभावना कम होती है क्यों कि यह संभावना नहीं है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र एक ही समय में संकट का सामना करेंगे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

2. **<u>तमिलनाडु के डिंडीगुल ताले और कंदांगी साड़ी को जी.आई. टैग प्रदान किया गया है।</u>**

- चेन्नई में डिंडीगुल ताला और कंदांगी साड़ी को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत (जी.आई.) टैग प्रदान किया गया है।

डिंडीगुल ताले

- ये अपनी बेहतर गुणवत्ता और मजबूती के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, यहां तक कि इस शहर को लॉक सिटी भी कहा जाता है।
- सरकारी संस्थान जैसे जेल, गोदाम, अस्पताल और यहां तक कि मंदिर भी अन्य मशीन-निर्मित तालों के स्थान पर इन तालों का उपयोग करते हैं।

कंदांगी साड़ी

- ये शिवगंगा जिले के पूरे कराईकुडी तालुके में बनाईं जाती हैं।
- इनकी प्रमुख विशेषता दूसरे रंग का बड़ा बार्डर होती है और कुछ साड़ियों में साड़ी के दो-तिहाई हिस्से तक बॉर्डर होता है, सामान्यत: साड़ी की लंबाई लगभग 10 मीटर से 5.60 मीटर तक होती है।

संबंधित जानकारी

जी.आई. टैग

- भारत में जी.आई. टैग को भौगोलिक उत्पाद संकेतक (पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम), 1999 द्वारा शासित किया जाता है।
- इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेड मार्क के महानियंत्रक द्वारा प्रशासित किया जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –कला एवं संस्कृति

स्रोत- पी.आई.बी.

3. **<u>नार-पार-तापी नदी लिंकिंग परियोजना</u>**

- महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों के लिए 52 टी.एम.सी. फीट पानी सुनिश्चित करने हेतु नार-पार-तापी नदी लिंकिग परियोजना को मंजूरी प्रदान की है।
- प्रस्तावित पार-तापी-नर्मदा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच संघर्ष का एक प्रमुख कारण बनने के लिए तैयार है।

संबंधित जानकारी

नार-पार-तापी लिंकिंग परियोजना

- नार-पार-तापी लिंकिंग परियोजना, जो एक लिफ्ट सिंचाई योजना, सुरंगों और नहरों का एक संयोजन है, यह मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों के लिए 52 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टी.एम.सी. फीट) पानी सुनिश्चित करेगी।
- जुलाई, 2019 में राज्य मंत्रिमंडल ने मराठवाड़ा और मुंबई शहर के इलाकों में पानी की कमी को कम करने के लिए नार-पार-तापी और दमनगंगा-पिंजल नदी लिंकिंग परियोजनाओं को पूरा करने हेतु अपनी मंजूरी प्रदान की थी।
- गुजरात के साथ पानी के बंटवारे को लेकर तकनीकी विवादों के कारण परियोजनाएं वर्षों से लटकी रही हैं।
- यह परियोजनाएँ नर्मदा नहर की मियागम शाखा के कमांड क्षेत्र को पोषित करने हेतु महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में नदियों के अधिशेष जल के हस्तांतरण की परिकल्पना करती हैं।
- यह नर्मदा बांध में पानी बचाएगी, जो सौराष्ट्र और कच्छ में ले जाया जाएगा।

नोट:

- नदी इंटरलिंकिंग परियोजना जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प के अंतर्गत काम करती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –भूगोल

स्रोत- लाइव मिंट

4. **डब्ल्यू.एच.ओ. अफ्रीका क्षेत्रीय समिति का 69वां सत्र**

- ब्रेज़ाविले में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अफ्रीका क्षेत्रीय समिति के 69वें सत्र ने महाद्वीप की अत्यंत अनिवार्य स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक्ताओं पर बहुत अधिक ध्यान देने में मदद की है।
- डब्ल्यू.एच.ओ. के अफ्रीकी क्षेत्र के अंतर्गत सभी 47 सदस्य राज्यों में स्वास्थ्य सुरक्षा जोखिमों का खतरा है।
- केवल 29 देशों ने जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को कम करने के लिए स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय अनुकूलन योजना को विकसित और कार्यान्वित किया है।
- इस ढांचे का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अफ्रीकी देशों में 80 प्रतिशत लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे

स्रोत- डाउन टू अर्थ

5. **टेक-सक्षम**

- केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री ने टेक सक्षम लॉन्च किया है।
- यह एम.एस.एम.ई. मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ के मध्य एक सहभागिता परियोजना है।
- यह तीन वर्ष लंबी व्यापक परियोजना होगी।
- अपने पहले चरण में, यह परियोजना उन क्षेत्रों में एम.एस.एम.ई. पर ध्यान केंद्रित करेगी जो श्रम-गहन हैं और तकनीक-अपनाने के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति रखते हैं।
- यह परियोजना एम.एस.एम.ई. द्वारा उनके विकास में आने वाले तकनीकी अंतराल को संबोधित करने के लिए प्रौद्योगिकी की बड़ी कंपनियों को एक साथ लाएगी।
- इस परियोजना का उद्देश्य एम.एस.एम.ई. के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने के अंतर को भरना है जिससे कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके, देश के निर्यात में उनके योगदान को बढ़ाया जा सके और लागत क्षमता का लाभ उठाया जा सके।
- यह मंच एम.एस.एम.ई. को कई नीतिगत सिफारिशों, ज्ञान सत्रों, दूसरों के मध्य पहलों को शुरू करने के माध्यम से चुनौतियों से उबरने में मदद करेगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

6. **बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी**

- पाकिस्तान ने गजनवी नामक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।

संबंधित जानकारी

गजनवी मिसाइल

- यह एक सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे राष्ट्रीय विकास परिसर द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
- इस मिसाइल की मारक क्षमता 290 से 320 कि.मी. के बीच है।
- इसका पहला संस्करण वर्ष 2004 से पाकिस्तान सेना की रणनीतिक कमान के साथ सेवारत है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- टी.ओ.आई.

7. **तूफान डोरियन, बहामास में गंभीर बाढ़ का कारण है**

- कैरिबियाई द्वीपों के बहामास में आने के लिए सबसे शक्तिशाली तूफान ने इमारतों से छतों को उखाड़ दिया है और गंभीर बाढ़ का कारण बना है।
- तूफान डोरियन, एक पांचवीं श्रेणी का तूफान है, जिसकी सफ्तार 295 किलोमीटर/घंटा तक की हवाओं की रही है।
- मौसम विज्ञानियों द्वारा एक तूफान की ताकत को मापने के लिए "सैफिर-सिम्पसन विंड स्केल" का उपयोग किया गया है।
- यह तूफान की निरंतर हवा की गति के आधार पर 1 से 5 रेटिंग का पैमाना है।
- जीवन और हानि के महत्वपूर्ण नुकसान के लिए उनकी क्षमता के आधार पर इन्हें रंटिंग प्रदान की जाती है, श्रेणी 3 और इससे ऊपर की श्रेणी के तूफानों को प्रमुख तूफान माना जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –भूगोल

स्रोत- ए.आई.आर.

8. **<u>केंद्र सरकार ने ऑनलाइन राष्ट्रीय प्रयोगशाला निर्देशिका शुरू की है।</u>**

- केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने राष्ट्रीय प्रयोगशाला निर्देशिका का शुभारंभ किया है।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय प्रयोगशाला निर्देशिका

- यह भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बनाया गया एक ऑनलाइन मंच है।
- यह उद्योगों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और अन्य हितधारकों की सभी परीक्षण आवश्यकताओं के लिए एक-स्टॉप-शॉप है, जिन्हें अपने परीक्षण सुविधाओं को प्रत्यायित/ प्रमाणित /मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता है।
- यह निर्देशिका अनुसंधान और विकास के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक उत्पादों या परीक्षण के अनुरूप मूल्यांकन के लिए लाभान्वित होगी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

9. **<u>लाइफलाइन एक्सप्रेस: विश्व की पहली अस्पताल ट्रेन</u>**

- भारतीय रेलवे ने इंपैक्ट इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी में छत्रपति शिवा जी टर्मिनस से लाइफलाइन एक्सप्रेस- पहियों पर विश्व का पहला अस्पताल शुरू किया है।
- यह विश्व की पहली सात-कोच वाली अस्पताल ट्रेन है, जिसे भारतीय रेलवे द्वारा उन ग्रामीण आबादी की चिकित्सा और शल्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा के लिए दान किया गया है जो अस्पताल तक नहीं पहुँच सकते हैं।

टॉपिक- पी.सी.एस. परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण

स्रोत- द हिंदू

10. **<u>स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड</u>**

- दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) को किफायती ऋण और ब्याज आर्थिक सहायता पहुँच (PAiSA) के लिए अपने पोर्टल हेतु प्रतिष्ठित स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

संबंधित जानकारी

स्कॉच अवार्ड

- इसे वर्ष 2003 में स्थापित किया गया था और देश में एक स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
- यह डिजिटल, वित्तीय और सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रयासों को मान्यता प्रदान करता है।

पैसा पोर्टल

- यह वर्ष 2018 में शुरू किया गया एक केंद्रीकृत आई.टी. प्लेटफॉर्म है।
- यह मिशन के अंतर्गत ब्याज आर्थिक सहायता की आपूर्ति को सरल और सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा।
- यह मासिक आधार पर बैंकों से ब्याज आर्थिक सहायता दावों के प्रसंस्करण, भुगतान, निगरानी और ट्रैकिंग के लिए इंड टू इंड ऑनलाइन समाधान की पेशकश करता है।

डी.ए.वाई.एन.यू.एल.एम. मिशन

- यह आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत है।
- इसका उद्देश्य लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक शहरी गरीब परिवारों की पहुंच को सक्षम करके उनकी गरीबी और भेद्यता को कम करना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –महत्वपूर्ण पुरस्कार

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

11. **<u>आंध्र प्रदेश में भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग का उद्घाटन किया गया है।</u>**

- उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश में देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया है।
- कृष्णापत्तनम बंदरगाह और ओबुलावरीपल्ली के बीच 112 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन परियोजना का निर्माण बंदरगाह से खनिजों और औद्योगिक सामानों के सुगम परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।
- परियोजना के भाग के रूप में सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग का निर्माण किया गया है जो 6.6 कि.मी. लंबी है।

टॉपिक- पी.सी.एस. परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण

स्रोत- ए.आई.आर.

03.09.2019

1. **<u>समुद्रायन परियोजना</u>**

- समुद्रायन, दुर्लभ खनिजों के लिए गहरे समुद्र में खनन हेतु पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की परीक्षण परियोजना का एक हिस्सा है।
- यह परियोजना "डीप ओशियन मिशन" का हिस्सा है जिसे सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्रालय से अंतिम मंजूरी का इंतजार है।
- इस परियोजना में गहरे पानी के भीतर अध्ययन करने के लिए लगभग 6000 मीटर की गहराई तक तीन व्यक्तियों के साथ एक पनडुब्बी वाहन भेजने का प्रस्ताव है।
- इस परियोजना का संचालन राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किया जा रहा है।

संबंधित जानकारी

डीप ओशियन मिशन

- यह केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत पांच वर्ष का मिशन है जिसके 31 अक्टूबर, 2019 से शुरू होने का अनुमान है।
- समुद्र तल से बहुधात्विक नॉड्यूलों के अन्वेषण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण द्वारा भारत को मध्य हिंद महासागर बेसिन में 75,000 वर्ग कि.मी. का एक स्थल आवंटित किया गया है।
- मिशन के प्रमुख क्षेत्र हैं:

1. महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाएं
2. पानी के नीचे के वाहन
3. पानी के नीचे रोबोटिक्स से संबंधित तकनीकें
4. गहन समुद्री खनन: बहुधात्विक नॉड्यूलों का उपयोग करना

बहुधात्विक नॉड्यूल

- इन्हें आलू के आकार के मैंगनीज नॉड्यूल्स के रूप में भी जाना जाता है, ये बड़े छिद्रित नॉड्यूल

होते हैं, जो गहरे समुद्र में दुनिया के महासागरों के समुद्र तल में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।

- मैंगनीज और लोहे के अतिरिक्त इसमें निकेल, तांबा, कोबाल्ट, सीसा, मॉलिब्डेनम, कैडमियम, वैनेडियम, टाइटेनियम हैं, जिनमें से निकल, कोबाल्ट और तांबा शामिल हैं।
- यह परिकल्पित किया गया है कि इस बड़े रिजर्व की वसूली का 10% अगले 100 वर्षों के लिए भारत की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा कर सकता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –भूगोल

स्रोत- ए.आई.आर.

2. **<u>'बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम हेतु आई.टी. मंत्रालय ने गूगल के साथ ससाझेदारी की है।</u>**

- 'बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के संचालन हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई.टी. मंत्रालय (एम.ई.आई.टी.वाई) के साथ साझेदारी हेतु आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

- यह कार्यक्रम इंजीनियरिंग छात्रों के लिए बाज़ार-आधारित, प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा जो प्रमुख सामाजिक समस्याओं को संबोधित करता है।
- कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, देश भर के इंजीनियरिंग छात्रों को स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट शहरों और बुनियादी ढांचे, महिला सुरक्षा, स्मार्ट गतिशीलता और परिवहन, पर्यावरण, पहुंच और विकलांगता और डिजिटल साक्षरता जैसे क्षेत्रों में अपने विचारों और समाधान पेश करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

3. **<u>भारत ने वर्ष 2022 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा है।</u>**

- भारत ने इंटरपोल को प्रस्ताव दिया है कि वर्ष 2022 में राष्ट्र के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में संगठन की महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा।
- इंटरपोल की 88वीं महासभा का आयोजन इस वर्ष के अंत में सैंटियागो, चिली में किया जाएगा।

इंटरपोल महासभा क्या है?

- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन या इंटरपोल, 194-सदस्यीय अंतर सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय फ्रांस के ल्योन में स्थित है।
- यह 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में गठित हुआ था और 1956 में स्वयं को इंटरपोल के नाम से संबोधित करने लगा था।
- भारत 1949 में इस संगठन में शामिल हुआ था और सबसे पुराने सदस्यों में से एक है।
- यह विभिन्न देशों के पुलिस बलों को अपराधों और अपराधियों पर डेटा साझा करने और उपयोग करने में सक्षम बनाता है और "तकनीकी और परिचालन समर्थनों की एक श्रृंखला" प्रदान करता है।

महासभा

- महासभा, इंटरपोल का सर्वोच्च शासी निकाय है और इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- महासभा का आयोजन प्रतिवर्ष गतिविधियों और नीतियों पर मतदान करने के लिए लगभग चार दिनों तक चलने वाले सत्र के रूप में किया जाता है।

- महासभा, इंटरपोल कार्यकारी समिति के सदस्यों का भी चुनाव करती है, यह एक शासी निकाय है जो "विधानसभा के सत्रों के बीच मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करता है"।

विधानसभा प्रस्ताव

- महासभा के निर्णय, प्रस्तावों का रूप लेते हैं।
- प्रत्येक सदस्य देश के पास एक मत होता है। विषय-वस्तु के आधार पर निर्णय या तो सामान्य या दो-तिहाई बहुमत से किए जाते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –अंतर्राष्ट्रीय संगठन

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

4. **आठ अमेरिका निर्मित अपाचे ए.एच.-64 ई. हमलावर हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है।**

- आठ संयुक्त राज्य अमेरिका निर्मित अपाचे ए.एच.-64 ई. हमलावर हेलीकॉप्टरों को पठानकोट वायु सेना स्टेशन पर भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया है।
- अपाचे बेड़े के शामिल होने से बड़ी सटीकता के साथ घातक गोलाबारी में वृद्धि होगी और यह वायु सेना की लड़ाकू क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा।
- ए.एच.-64 ई. अपाचे, विश्व के सबसे उन्नत बहु-भूमिका लड़ाकू हेलीकाप्टरों में से एक है।
- भारतीय वायुसेना ने 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए सितंबर, 2015 में अमेरिकी सरकार और बोइंग लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –रक्षा

स्रोत- ए.आई.आर.

5. **विश्व निर्वाचन निकाय संघ की चौथी महासभा**

- भारतीय चुनाव आयोग, बैंगलोर में विश्व निर्वाचन निकाय संघ (ए.-डब्ल्यू.ई.बी.) की चौथी महासभा की मेजबानी करेगा।
- भारत, वर्ष 2019-2021 के कार्यकाल के लिए ए.-डब्ल्यू.ई.बी. के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेगा।

संबंधित जानकारी

विश्व निर्वाचन निकाय संघ

- यह पूरे विश्व में चुनाव प्रबंधन निकायों (ई.एम.बी.) का सबसे बड़ा संघ है जो वर्ष 2013 में स्थापित किया गया था।
- ए.-डब्ल्यू.ई.बी. का स्थायी सचिवालय दक्षिण कोरिया के सियोल में स्थित है।
- इसकी स्थापना पूरे विश्व में स्थायी लोकतंत्र प्राप्त करने वाले अपने सदस्यों के बीच एक साझा दृष्टिकोण के साथ की गई थी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नैंस

स्रोत- ए.आई.आर.

6. **बिहार, कैमूर में एक अन्य बाघ रिजर्व स्थापित करने की योजना बना रहा है।**

- हाल ही में, बिहार सरकार ने वाल्मीकि बाघ रिज़र्व (वी.टी.आर.) के बाद राज्य के दूसरे बाघ रिजर्व के लिए संभावित स्थल के रूप में कैमूर में वनों की पहचान की है।
- बिहार वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, कैमूर के वन 1,134 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिसमें कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का 986 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल हैं।
- बिहार में कैमूर जिले में सबसे अधिक हरा क्षेत्र है जो लगभग 34 प्रतिशत है।
- क्षेत्रफल के संदर्भ में कैमूर के जंगल राज्य में सबसे बड़े हैं।
- कैमूर के जंगल झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जंगलों से जुड़े हुए हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3–पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

7. **<u>प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है।</u>**

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वच्छ भारत अभियान में उनके काम के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया जाएगा।
- यह पुरस्कार बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका स्वामित्व माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स के पास है।
- यह वार्षिक पुरस्कार नेताओं और व्यक्तियों को सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को प्राप्त करने के उनके प्रयासों हेतु प्रदान किया जाता है।

सम्बंधित जानकारी

- स्वच्छ भारत अभियान, 2 अक्टूबर, 2014 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी पहलों में से एक है।
- स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2019 तक भारत को "खुले में शौच मुक्त" बनाना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2–सरकारी नीतियां

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

8. **<u>भारत का पहला कचरा कैफे</u>**

- भारत का पहला "कचरा (गारबेज) कैफे" शीघ्र ही उत्तरी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में खोला जाएगा जो कि स्वछता रैंकिंग में देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर है।
- यह पहल, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम द्वारा शुरू की गई है।
- इसका उद्देश्य शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाना है।
- इस अनूठे कैफे में गरीब लोगों और कूड़ा बीनने वालों को एक किलोग्राम प्लास्टिक के बदले में मुफ्त भोजन मिलेगा, जबकि आधा किलोग्राम प्लास्टिक कैफे में लाने पर नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3–पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

04.09.2019

1. **<u>माले घोषणापत्र ने कश्मीर पर पाकिस्तान की चिंता की उपेक्षा कर दी है।</u>**

- हाल ही में, दक्षिण एशियाई वक्ताओं के चौथे शिखर सम्मेलन का मालदीव की राजधानी माले में अंतर-संसदीय संघ के महासचिव और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के वरिष्ठ सांसदों के साथ आयोजन किया गया है।
- वार्षिक शिखर सम्मेलन का संयुक्त रूप से अंतर-संसदीय संघ (आई.पी.यू.) और मालदीव संसद द्वारा आयोजन किया गया था।
- यह शिखर सम्मेलन, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रभाव बनाने पर केंद्रित है।
- इस शिखर सम्मेलन के अंत में माले घोषणापत्र को अपनाया गया था जिसमें "सर्वसम्मति से" महसूस किया गया है कि कश्मीर, भारत का एक "आंतरिक मामला" है और इस मुद्दे पर इस्लामाबाद द्वारा किए गए सभी दावों की उपेक्षा कर दी गई है।
- घोषणापत्र को भारत द्वारा पाकिस्तान के शिखर सम्मेलन के दौरान कश्मीर मुद्दे को उठाने के प्रयास को विफल करने के एक दिन बाद बाद अपनाया गया था।
- भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष और राज्य सभा के उपाध्यक्ष द्वारा किया गया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

2. **जम्मू-कश्मीर सरकार, वर्ष 2022 तक प्रत्येक घर में पाइप द्वारा पानी पहुंचाएगी।**

- जम्मू और कश्मीर सरकार, वर्ष 2022 तक राज्य के प्रत्येक घर में पाइप द्वारा पानी की आपूर्ति करने की योजना बना रही है।

संबंधित जानकारी

नल से जल योजना

- प्रत्येक घर को पाइप द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने की 'नल से जल' योजना, सरकार के जल जीवन मिशन का एक घटक होगी।
- इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर तक पाइप द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना है।
- जल शक्ति मंत्रालय, नल से जल मिशन की कार्यान्वयन संस्था है।
- वर्ष 2018 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, "600 मिलियन भारतीय अधिक से अत्यधिक पानी की कमी का सामना कर रहे हैं और प्रत्येक वर्ष लगभग दो लाख लोग सुरक्षित पानी की अपर्याप्त पहुंच के कारण मर जाते हैं।
- वर्ष 2030 तक, देश की पानी की माँग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी होने का अनुमान है, जिससे लाखों लोगों के लिए पानी की गंभीर कमी हो सकती है और अंतत: देश की जी.डी.पी. में लगभग 6% की हानि हो सकती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

3. **एक्सरसाइज: युद्ध अभ्यास 2019**

- भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास 5 सितंबर, 2019 से वाशिंगटन के निकट संयुक्त बेस लुईस मैकार्ड में शुरू किया जाएगा।
- यह भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 15वां संस्करण है।
- संयुक्त अभ्यास की मेजबानी दोनों देशों द्वारा एकांतर क्रम में की जाती है।
- अभ्यास, एक दूसरे की विशेषज्ञता और योजना के अनुभव और ऑपरेशनों के निष्पादन से सीखने हेतु एक आदर्श मंच है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –रक्षा

स्रोत- टी.ओ.आई.

4. **वैष्णो देवी तीर्थ स्थान, स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों की सूची में शीर्ष स्थान पर है।**

- माता वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों के ऊपर स्थित है, जिसे देश का 'सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान' नाम दिया गया है।

संबंधित जानकारी

स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान

- स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक पहल है।
- यह एक विशेष स्वच्छता पहल है, जो देश में चुनिंदा प्रतिष्ठित विरासत, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर केंद्रित है।
- केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों की रैंकिंग जारी की गई थी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –कला एवं संस्कृति

स्रोत- इंडिया टुडे

5. **ए.यू.एम.एक्स.: पहला आसियान-अमेरिका समुद्री युद्धाभ्यास**

- क्षेत्रीय ब्लॉक- दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन (आसियान) और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच पहला आसियान-अमेरिका समुद्री युद्धाभ्यास (ए.यू.एम.एक्स.) थाईलैंड में सत्ताहिप नौसेना बेस पर आयोजित किया गया था।
- यह एक नौसैना युद्धाभ्यास है, जिसका अमेरिका और थाईलैंड की नौसेनाओं द्वारा सह-नेतृत्व किया जाता है।

- इसमें आसियान के सभी 10 सदस्यों (थाईलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर और वियतनाम) और अमेरिका की नौसेनाओं की भाग लेंगी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –रक्षा

स्रोत- लाइवमिंट

6. **<u>नुआखाई: ओडिशा का सबसे बड़ा फसल महोत्सव</u>**

- नुआखाई महोत्सव, किसानों द्वारा नई फसल के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार है।
- नुआखाई त्योहार की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई थी जहां स्वामी या ऋषि पञ्चजन्य के बारे में बात करते थे।
- उनमें से एक प्रलम्बन यज्ञ था, जिसका अर्थ नई फसलों को काटना और उन्हें देवी माँ को अर्पित करना है, इसी का अनुसरध नुआखाई महोत्सव में किया जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –कला एवं संस्कृति

स्रोत- लाइवमिंट

7. **<u>आई.आई.टी. दिल्ली, साझाकृत अनुसंधान ढांचा सुविधा साथी की स्थापना करेगी।</u>**

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) ने आई.आई.टी. दिल्ली को एक साझाकृत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ढांचा सुविधा बनाने के लिए चुना है, जिसका नाम परिष्कृत विश्लेषणात्मक एवं प्रौद्योगिकी सहायता संस्थान (SATHI) है।
- यह केंद्र आई.आई.टी. दिल्ली के सोनीपत परिसर (हरियाणा) में स्थापित किया जाएगा।
- यह केंद्र शिक्षा, स्टार्ट-अप, विनिर्माण इकाइयों, उद्योगों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के लिए सुलभ होगा।
- इसका उद्देश्य उद्योग, स्टार्ट-अप और अकादमियों की मांगों को पूरा करने के लिए एक छत के नीचे व्यवसायिक रूप से प्रबंधित सेवाएं प्रदान करना है।
- साथी के अंतर्गत शोधकर्ताओं को न्यूनतम रूकने के समय के साथ पूरे दिन सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 – अर्थशास्त्र (ढांचा)

स्रोत- डाउन टू अर्थ

8. **<u>रीप्लान परियोजना (प्रकृति में प्लास्टिक को कम करना)</u>**

- खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने रीप्लान परियोजना (प्रकृति में प्लास्टिक को कम करना) का शुभारंभ किया है, जो स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है।
- इस परियोजना में बेकार प्लास्टिक को इकट्ठा किया जाता है, साफ किया जाता है, काटा जाता है, पीटा जाता है और कोमल बनाया जाता है।
- उसके बाद, इसे कागज़ के कच्चे माल अर्थात कपास के छिलके के गूदे को 80% (गूदे) और 20% (प्लास्टिक कचरे) के अनुपात में मिलाया जाता है।
- खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने वाराणसी में सेवापुरी में एक तेराकोट्टा ग्राइंडर लॉन्च किया है।
- यह तेराकोट्टा ग्राइंडर, मिट्टी के बर्तन बनाने में फिर से उपयोग करने के लिए खराब और टूटे हुए बर्तनों को पीस देगा।

संबंधित जानकारी

के.वी.आई.सी.

- यह संसद के अधिनियम, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है।
- यह भारत में खादी और ग्रामोद्योग के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष संगठन है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

9. **<u>कृषि अपशिष्ट से प्राप्त लिग्निन उपयोगी नैनोकंपोसाइट्स बनाने में मदद करता है।</u>**

- हाल ही में, मोहाली स्थित नवाचार एवं प्रायोगिक जैव प्रसंस्करण केंद्र (सी.आई.ए.बी.) में शोधकर्ताओं ने एक लिग्निन-आधारित नैनोकम्पोसाइट विकसित किया है जिसका संभवतः वाणिज्यिक महत्व हो सकता है।
- माइक्रोबियल परीक्षण के परिणाम इंगित करते हैं कि लंबे समय में, लिग्निन-आधारित नैनो सामग्रियां कोटिंग और पैकेजिंग सामग्री में एक योजक के रूप में कार्य कर सकती हैं।

संबंधित जानकारी

लिग्निन

- लिग्निन एक जटिल कार्बनिक बहुलक है, जिसमें रोगाणुरोधी गुणों के साथ पॉलीफीनोल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
- यह लगभग सभी सूखे पौधों में पाया जाता है जिसमें फसल के अवशेष और पेड़ों की लकड़ी की छाल शामिल हैं।
- लिग्निन, मुख्य रूप से कोशिका भित्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से लकड़ी और छाल में पाया जाता है क्यों कि वे कठोरता प्रदान करते हैं और आसानी से सड़ते नहीं हैं।
- प्रत्येक वर्ष फसल के बाद के कृषि-बायोमास और कागज और लुगदी उद्योगों में लिग्निन की प्रचुर मात्रा उत्पन्न होती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीकी

स्रोत- द हिंदू बिजनेस लाइन

10. **<u>भारत, वैश्विक एड्स, टी.बी. एवं मलेरिया कोष (जी.एफ.टी.ए.एम.) में 22 मिलियन अमरीकी डालर का योगदान देगा।</u>**

- भारत ने 6वें पुनःपूर्ति चक्र (2020-22) वैश्विक एड्स, टी.बी. एवं मलेरिया कोष (जी.एफ.टी.ए.एम.) में 22 मिलियन अमरीकी डालर का योगदान देने की घोषणा की है।
- वैश्विक कोष एड्स, टी.बी. और मलेरिया के अंत में तेजी लाने हेतु एक साझेदारी है।
- वैश्विक कोष 100 से अधिक देशों में स्थानीय विशेषज्ञों द्वारा संचालित कार्यक्रमों में मदद करने के लिए प्रतिवर्ष 4 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक धन जुटाता और निवेश करता है।
- भारत ने एच.आई.वी./ एड्स, टी.बी. और मलेरिया को कम करने से संबंधित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु वैश्विक कोष से 2.0 बिलियन अमरीकी डालर प्राप्त किए हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत- द हिंदू बिजनेस लाइन

05.09.2019

1. **<u>भूमि पतन तटस्थता परिवर्तनकारी परियोजनाएं एवं कार्यक्रम</u>**

- पार्टियों के 14वें सम्मेलन के दौरान, ग्लोबल मैकेनिज्म ग्रुप ने एल.डी.एन. पर तकनीकी दिशानिर्देश जारी करने हेतु एक स्थल कार्यक्रम आयोजित किया था।

भूमि पतन तटस्थता (एल.डी.एन.)

- संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण निपटान सम्मेलन, एल.डी.एन. को "एक ऐसे राज्य के रूप में परिभाषित करता है जहां पारिस्थितिकी प्रणाली के कार्यों और सेवाओं का समर्थन करने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने और स्थायी करने के लिए या निर्दिष्ट अस्थायी और स्थानिक पैमानों और पारिस्थितिक प्रणाली के भीतर बढ़ाने हेतु आवश्यक भूमि संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता है"।
- एल.डी.एन. पर पहली बार निर्णय यू.एन.सी.सी.डी. 2015 के सी.ओ.पी. 13 में लिया गया था।

- इसका लक्ष्य भूमि संसाधन आधार को बनाए रखना या बढ़ाना है, दूसरे शब्दों में, भूमि संसाधनों से संबंधित प्राकृतिक पूंजी के भंडार और उनसे संचालित होने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं हैं।
- एल.डी.एन. के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाओं के सतत वितरण को बनाए रखना या सुधारना
2. खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के क्रम में उत्पादकता को बनाए रखना या सुधारना
3. भूमि की निर्भरता और भूमि पर निर्भर आबादी में वृद्धि करना
4. अन्य सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों के साथ तालमेल बनाना और
5. भूमि के उत्तरदायी और समावेशी शासन को सुदृढ़ करना

- सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के संदर्भ में एल.डी.एन. का अनुसरण किया जा रहा है, जो सतत उपभोग और उत्पादन के माध्यम सहित ग्रह के पतन की रक्षा कर रहा है, अपने प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन पर तत्काल कार्रवाई करने का प्रयास करता है।

संबंधित जानकारी

वैश्विक तंत्र (जी.एम.)

- इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र मरूस्थलीकरण निपटान सम्मेलन के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत की गई थी।
- यह सम्मेलन का कार्यान्वन करने और मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे को संबोधित करने हेतु वित्तीय संसाधनों के संग्रहण में देशों की सहायता करने में मदद करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 – पर्यावरण

स्रोत- पी.आई.बी.

2. **<u>सरकार अधिक ऊँचाई पर बाघों के लिए एक मास्टर प्लान विकसित कर रही है।</u>**

- हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने अधिक ऊंचाई वाले पारिस्थितिक तंत्रों में बाघों के निवास स्थानों की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है जो सरकार की अधिक ऊंचाई पर बाघों के लिए एक मास्टर प्लान विकसित करने में मदद करती हैं।
- यह रिपोर्ट, वैश्विक बाघ फोरम (जी.टी.एफ.) द्वारा तैयार की गई है, स्थानीय समुदायों के लिए लाभप्रद पोर्टफोलियो के साथ एक अधिक ऊंचाई वाले बाघ मास्टर प्लान के लिए कार्य रणनीति प्रदान करती है और विकास में बाघ संरक्षण की केंद्रीयता को सुनिश्चित करती है।

संबंधित जानकारी

वैश्विक बाघ फोरम

- यह एक अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय निकाय है, जो विशेष रूप से जंगल में बाघों के संरक्षण के लिए काम कर रहा है।
- इसकी स्थापना बाघ, उसके शिकार और उसके आवास को बचाने हेतु एक विश्वव्यापी अभियान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- इसमें जैव विविधता संरक्षण के लिए शामिल देशों में एक कानूनी ढांचे को बढ़ावा देने और बाघों के निवास स्थान के संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को बढ़ाने और समीपवर्ती देशों में उनके अंतर मार्ग को सुविधाजनक बनाने की योजना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण एवं जैवविविधता

स्रोत- द हिंदू

3. **<u>गुलमर्ग रक्षा परियोजना</u>**

- हाल ही में, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने जम्मू और कश्मीर में एक हवाई रक्षा और हथियार परियोजना हेतु अपनी मंजूरी प्रदान की है, जिसमें गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य की 1.18 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाएगा।

- यह परियोजना गुलमर्ग अभयारण्य के बाहर 12.35 हेक्टेयर वन भूमि को भी कवर करेगी।
- जम्मू-कश्मीर में प्रस्तावित परियोजना में हेलीपैड निर्माण के साथ वायु रक्षा और हथियार की स्थापना शामिल है और अभयारण्य क्षेत्र में केवल रडार प्रणाली स्थापित की जाएगी।

संबंधित जानकारी

गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य

- यह पश्चिमी हिमालय में पीरपंजाल रेंज में स्थित है।
- यह क्षेत्र अपने प्रसिद्ध घास के मैदानों, पहाड़ी चट्टानों, घने बर्च जंगलों और पक्षी दर्शकों के लिए सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है।
- यह अभयारण्य अत्यधिक लुप्तप्राय कस्तूरी मृग (मॉस्कस क्राइसोगेटर) का निवास स्थान है।

टॉपिक-जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

4. **<u>टास्क फोर्स ने ऑनलाइन ऋण बिक्री प्लेटफार्म की सिफारिश की है।</u>**

- आर.बी.आई. ने टी.एन. मनोहरन की अध्यक्षता में कॉर्पोरेट ऋण के लिए एक द्वितीयक बाजार के विकास पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया है।
- कॉर्पोरेट ऋणों के लिए एक द्वितीयक बाजार के विकास के लिए गठित टास्क फोर्स ने नीलामी के संचालन के लिए एक ऑनलाइन ऋण बिक्री प्लेटफार्म की सिफारिश की है।

अन्य सिफारिशें

- टास्क फोर्स ने प्रतिभागियों के एक स्व-विनियामक निकाय की स्थापना की सिफारिश की है जो कॉर्पोरेट ऋणों की माध्यमिक बिक्री हेतु एक प्लेटफार्म के निर्माण पर काम करेगा।
- टास्क फोर्स का गठन सेबी, इरडा और पी.एफ.आर.डी.ए. के विनियमों को भी संशोधित करने हेतु किया गया था, जिससे कि म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंड जैसी गैर-बैंकिंग संस्थाओं की भागीदारी को सक्षम किया जा सके।
- टास्क फोर्स ने द्वितीयक बाजार ऋणों की नीलामी/ बिक्री प्रक्रिया के संचालन हेतु एक ऑनलाइन ऋण बिक्री प्लेटफार्म स्थापित करने का सुझाव दिया है।
- इसने खरीददारों और विक्रेताओं के बीच सूचना विषमता को दूर करने के लिए एक ऋण अनुबंध रजिस्ट्री बनाने की भी सिफारिश की है।
- द्वितीयक बाजार, वह बाजार है जहां निवेशक प्रतिभूतियों को खरीदते और बेचते हैं, जो पहले से ही उनके पास हैं जिसे शेयर बाजार के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –अर्थशास्त्र

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

5. **<u>क्षुद्रग्रह संघात विक्षेपण मूल्यांकन मिशन पर नासा, ई.एस.ए. का संयुक्त प्रयास</u>**

- नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष संस्था (ई.एस.ए.) की टीमें क्षुद्रग्रह संघात विक्षेपण मूल्यांकन मिशन की प्रगति पर चर्चा करने हेतु अगले सप्ताह रोम में बैठक करेंगी।
- यह एक अंतरिक्ष यान को उसकी सतह में दुर्घटनाग्रस्त करके क्षुद्रग्रह को हटाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक संयुक्त अनुसंधान मिशन है।

संबंधित जानकारी

क्षुद्रग्रह प्रभाव विक्षेपण मूल्यांकन

- इस परियोजना का उद्देश्य पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच दो डिडीमोस क्षुद्रग्रहों में से एक की कक्षा को विक्षेपित करना है, एक पर्यवेक्षक क्राफ्ट, जमीन आधारित पर्यवेक्षक द्वारा प्रबंधन करने की तुलना में टक्कर के प्रभाव को अधिक प्रभाशीलता के साथ माप सकता है।

- डिडिमोस, पृथ्वी के निकट स्थित एक क्षुद्रग्रह प्रणाली है, जिसका मुख्य पिंड माप 780 मीटर है और छोटा निकाय "चंद्रमा" लगभग 160 मीटर व्यास का है।
- नासा कोलाइडर, डबल क्षुद्रग्रह संघात परीक्षण (डी.ए.आर.टी.) प्रदान करेगा।
- इसे 2021 की गर्मियों में लॉन्च किया जाना चाहिए और दोनो डिडिमोस क्षुद्रग्रहों में से छोटे में लगभग 14,764 मील प्रति घंटा की चाल से टक्कर कराई जाएगी।
- एक इतालवी क्यूबसैट, लिसिया क्यूब, इसके बाद के टक्कर के क्षण का अध्ययन करेगा, ई.एस.ए. लक्षित क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए अक्टूबर, 2024 में एक हेरा जांच शुरू करेगा, जिसमें प्रभाव क्रेटर, द्रव्यमान और एक रडार जांच शामिल है (पहली बार एक क्षुद्रग्रह पर)।
- हेरा को पहुँचने में लगभग दो वर्ष का समय लगेगा।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीकी

स्रोत- टी.ओ.आई.

6. **<u>सरकार, 2 अक्टूबर से एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने जा रही है।</u>**

- केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को एकल-उपयोग प्लास्टिक वाली सभी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने का निर्णय लिया है।
- यह कदम “श्रमदान” थीम के अंतर्गत एकल-उपयोग प्लास्टिक (एस.यू.पी.) के खिलाफ एक महत्वाकांक्षी ड्राइव का हिस्सा है, जिसके लिए मंत्रालयों और विभागों हेतु एक विस्तृत योजना पर काम किया गया है।
- प्रस्तावों में से हैं:

1. एस.यू.पी. पर संपूर्ण प्रतिबंध
2. पुनर्चक्रीय और गैर-पुनर्चक्रनीय प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने और अलग करने हेतु सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकाय
3. प्लास्टिक कचरे का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों में सड़क निर्माण हेतु किया जाएगा।
4. सीमेंट विनिर्माता, ईंधन के रूप में प्लास्टिक का उपयोग करेंगे
5. कपड़ा मंत्रालय, जूट बैग के उत्पादन को बढ़ावा देगा
6. सभी ग्राम सभाओं को वर्ष 2022 तक प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

- पहल के हिस्से के रूप में, 5 लाख सरपंच और स्वच्छग्राही (स्वच्छता स्वयंसेवक) प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत पत्र प्राप्त करेंगे।

संबंधित जानकारी

एकल-उपयोग प्लास्टिक

- एकल-उपयोग प्लास्टिक (एस.यू.पी.) वे होती हैं जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फेंक दिया जाता है।
- सर्वव्यापी प्लास्टिक की थैलियों के अतिरिक्त, एस.यू.पी. में पानी और सुगंधित/ वातित पेय की बोतलें, टेकअवे खाद्य कंटेनर, डिस्पोजेबल कटलरी, स्ट्रा और स्टिरर, प्रसंस्कृत खाद्य पैकेट और रैपर, कपास की स्टिक आदि शामिल हैं।
- इनमें से, कटा हुआ उत्पाद जैसे कटलरी, प्लेटें और कप पर्यावरण के लिए सबसे घातक हैं।

टॉपिक-जी. एस. पेपर 3 –सरकारी नीतियां एवं कार्यक्रम

स्रोत- टी.ओ.आई.

06.09.2019

1. **<u>भारत ने सुदूर पूर्व रूस को $1 बिलियन की ऋण सीमा प्रदान की है।</u>**

- भारत ने रूस के संसाधन संपन्न सुदूर पूर्व के लिए "अभूतपूर्व" $ 1 बिलियन की ऋण सीमा प्रदान करने की घोषणा की है।
- सुदूर पूर्व में जलवायु बेहद चुनौतीपूर्ण है। सर्दियां लगभग नौ महीने तक रहती हैं, बर्फ लगभग पूरे वर्ष जमीन को ढके रहती है।

- यह घोषणा भारत के सुदूर पूर्व की नीति के अधिनियम हेतु एक उड़ान बिंदु साबित होगी।
- हाल ही में, भारत ने रूस में आयोजित ई.ई.एफ. (पूर्वी आर्थिक मंच)-2019 में 5 बिलियन डॉलर के लगभग 50 समझौतों का समापन किया है।

संबंधित जानकारी

ऋण सीमा

- यह एक अनुदान नहीं है लेकिन विकासशील देशों को रियायती ब्याज दरों पर प्रदान किया गया एक 'सॉफ्ट लोन' है, जिसे उधार लेने वाली सरकार को चुकाना पड़ता है।
- एल.ओ.सी., भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने में भी मदद करता है क्यों कि अनुबंध के मूल्य का 75% भारत से प्राप्त होना चाहिए।
- एल.ओ.सी. के अंतर्गत परियोजनाएं विभिन्न क्षेत्रों (कृषि, आधारभूत संरचना, दूरसंचार, रेलवे, ट्रांसमिशन/ पावर, नवीकरणीय ऊर्जा) में फैली हुई हैं।
- विभिन्न देशों में एल.ओ.सी. परियोजनाओं का वास्तविक कार्यान्वयन प्रचलित राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों, उधार लेने वाली सरकारों द्वारा वैधानिक मंजूरी, उपलब्ध भूमि और अन्य अवसंरचनात्मक समर्थन जैसे स्थानीय कारकों पर निर्भर करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

2. **<u>विश्व यात्रा, पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत 34वें स्थान पर है।</u>**

- विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यू.ई.एफ.) ने यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (टी.टी.सी.आई.) रिपोर्ट 2019 जारी की है।
- सूचकांक ने वर्ष 2019 में भारत को 34वें स्थान पर रखा है। वर्ष 2018 में भारत 40वें स्थान पर था।
- स्पेन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, उसके बाद फ्रांस, जर्मनी और जापान है और संयुक्त राज्य अमेरिका ने शीर्ष पांच में यू.के. को प्रतिस्थापित किया है।
- सूचकांक में कहा गया है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन सबसे बड़ी यात्रा एवं पर्यटन अर्थव्यवस्था है और विश्व स्तर पर 13वीं सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था है।

यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक

- यह सूचकांक, विश्व आर्थिक मंच द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है जो 140 अर्थव्यवस्थाओं को स्थान प्रदान करता है।
- देशों को क्रमशः चार उप-सूचियों में स्थान प्रदान किया जाता है:

  (a) पर्यावरण को सक्षम बनाना

  (b) यात्रा एवं पर्यटन नीति और सक्षमता स्थिति

  (c) प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन

  (d) बुनियादी ढांचे

विश्व आर्थिक मंच

- इसे 1971 में गैर-लाभकारी फाउंडेशन के रूप में स्थापित किया गया था।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
- डब्ल्यू.ई.एफ. का उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडों को आकार देने के लिए व्यापारिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और समाज के अन्य नेताओं को शामिल करके दुनिया की स्थिति में सुधार करना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –महत्वपूर्ण सूचकांक

स्रोत- टी.ओ.आई.

3. **<u>वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2019</u>**

- इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अपना वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2019 जारी किया है।

वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक

- यह सूचकांक दुनिया भर के स्थानों का आकलन करता है जो सबसे अच्छी या सबसे खराब रहने की स्थिति प्रदान करता हैं।
- प्रत्येक शहर का मूल्यांकन पाँच व्यापक श्रेणियों में 30 गुणात्मक और मात्रात्मक कारकों के आधार पर किया जाता है:

1. स्थिरता
2. स्वास्थ्य देखभाल
3. संस्कृति और पर्यावरण
4. शिक्षा
5. बुनियादी ढाँचा

- पहली बार, सूचकांक ने लिवेबिलिटी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को इंगित किया है।
- स्कोर 1-100 के पैमाने पर संकलित किए जाते हैं। शहर के प्रत्येक कारक को स्वीकार्य, सहनीय, असुविधाजनक, अवांछनीय या असहनीय के रूप में मूल्यांकित किया जाता है।
- 1-100 तक के स्कोर प्रदान करने हेतु कारकों के आधार पर स्कोरों को संकलित और भारित किया जाता है, जहाँ 1 को असहनीय माना जाता है और 100 को आदर्श माना जाता है।

सूचकांक की मुख्य विशेषताएं

- वियना ने सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है इसके बाद मेलबर्न, सिडनी, ओसाका और कैलगरी का स्थान है।
- नई दिल्ली को खराब वायु गुणवत्ता के कारण 118वां स्थान (छह स्थान की गिरावट) जब कि मुंबई को 119वाँ स्थान प्रदान किया गया था।
- सबसे कम रहने योग्य शहर कराची, त्रिपोली, ढाका, लागोस हैं और सबसे नीचे दमिश्क (सीरिया) है।
- ब्रिक्स देशों में, रियो डी जनेरियो (ब्राजील) 89वें स्थान पर, मास्को (रूस) 68वें स्थान पर, बीजिंग (चीन) 76वें स्थान पर है।
- दुनिया के सबसे कम रहने योग्य शहर दमिश्क (सीरिया), लागोस (नाइजीरिया) और ढाका (बांग्लादेश) थे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –महत्वपूर्ण सूचकांक

स्रोत- द हिंदू

4. **<u>28वाँ इंडो-थाई कॉरपैट</u>**

- भारतीय नौसेना (आई.एन.) और रॉयल थाई नौसेना (आर.टी.एन.) के बीच भारत-थाईलैंड समन्वित गश्त (इंडो-थाई कॉरपैट) के 28वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है।
- इंडो-थाई कॉरपैट का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (यू.एन.सी.एल.ओ.एस. 1982) के प्रभावी कार्यान्वन को सुनिश्चित करना है।

संबंधित जानकारी

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (यू.एन.सी.एल.ओ.एस.)

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 1982 में जमैका की मोटेंगो खाड़ी में अपनाया और हस्ताक्षरित किया गया था।
- इसने अप्रैल 1958 के चार जिनेवा सम्मेलनों को प्रतिस्थापित किया है, जो क्रमशः प्रादेशिक समुद्र और समीपस्थ क्षेत्र, महाद्वीपीय जलसीमा, उच्च समुद्र, मछली पकड़ने और उच्च समुद्रों पर जीवित संसाधनों के संरक्षण से संबंध रखते थे।

सम्मेलन की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- तटीय राज्य अपने क्षेत्रीय समुद्र पर संप्रभुता का प्रयोग करते हैं जिसका उन्हें 12 समुद्री मील से कम सीमा तक की चौड़ाई स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है।
- तटीय राज्यों के पास प्राकृतिक संसाधनों और कुछ आर्थिक गतिविधियों के संबंध में 200-समुद्री मील विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ई.ई.जेड.) में संप्रभु अधिकार हैं, और समुद्री विज्ञान अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं।

- अन्य सभी राज्यों को ई.ई.जेड. में नेविगेशन और उड़ान के साथ ही पनडुब्बी केबल और पाइपलाइन बिछाने की स्वतंत्रता प्राप्त है।
- तटीय राज्यों के पास खोज और दोहन के लिए महाद्वीपीय जलसीमा (समुद्र तल का राष्ट्रीय क्षेत्र) पर संप्रभु अधिकार हैं और जलसीमा का तट से कम से कम 200 समुद्री मील तक विस्तार किया जा सकता है और निर्दिष्ट परिस्थितियों में और अधिक विस्तार भी किया जा सकता है।
- तटीय राज्य, 200 मील से अधिक अपनी जलसीमा के किसी भी हिस्से के संसाधनों के दोहन से प्राप्त राजस्व के अंतरराष्ट्रीय समुदाय के हिस्से को साझा कर सकते हैं।
- स्थलसीमा राज्यों को समुद्र के दोनो ओर तक पहुंचने का अधिकार है और पारगमन राज्यों के क्षेत्र के माध्यम से पारगमन की स्वतंत्रता का आनंद लें सकते हैं।

नोट:

- विवादों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या मध्यस्थता के अंतर्गत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- ट्रिब्यूनल के पास गहरे समुद्र तल में खनन विवादों पर अनन्य अधिकार क्षेत्र है।
- सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर तीन नए संस्थान बनाए हैं:

  (a) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण

  (b) अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण

  (c) महाद्वीपीय जलसीमा की सीमाओं पर आयोग

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

5. **भारतीय और पाकिस्तानी सेनाएं, रूस में सैन्य युद्धाभ्यास का हिस्सा बनेंगी।**

- TSENTR 2019 युद्धाभ्यास, बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास की वार्षिक श्रृंखला का हिस्सा है जो रूसी सशस्त्र बलों के वार्षिक प्रशिक्षण चक्र का हिस्सा है।
- यह युद्धाभ्यास श्रृंखला चार मुख्य रूसी परिचालन रणनीतिक कमानों के माध्यम से चलती है।
- इस वर्ष का TSENTR 2019 युद्धाभ्यास, रूस के केंद्रीय सैन्य आयोग द्वारा आयोजित किया जाएगा।
- मेजबान रूस के अतिरिक्त, चीन, भारत, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सैन्य दल भी इस मेगा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
- इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली सेनाओं की ड्रिलों को विकसित करना और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के उन्मूलन के खिलाफ लड़ाई में उनका अभ्यास करना है, जिससे रणनीतिक मध्य एशियाई क्षेत्र में सैन्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- TSENTR 2019 युद्धाभ्यास में दो मॉड्यूल शामिल होंगे:

1. पहले मॉड्यूल में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, रिपेलिंग हवाई हमले, टोही ऑपरेशन और रक्षात्मक उपाय शामिल होंगे।
2. दूसरा मॉड्यूल आक्रामक अभियानों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –रक्षा

स्रोत- पी.आई.बी.

6. **स्वर्ण भंडार में भारत शीर्ष 10 देशों में से एक है।**

- विश्व स्वर्ण परिषद की नवीनतम रिलीज़ के अनुसार, भारत को 618.2 टन के कुल स्वर्ण भंडारण के साथ देशों की सूची में 10वां स्थान प्रदान किया गया है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका को 8133.5 टन के स्वर्ण भंडारण के साथ पहला स्थान प्रदान किया गया है, इसके बाद जर्मनी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.), इटली, फ्रांस, रूस और चीन को स्थान प्रदान किया गया है।

संबंधित जानकारी

देशीय स्वर्ण परिषद

- पिछले वर्ष सरकार ने आभूषणों के निर्यात में सहायता हेतु देशीय स्वर्ण परिषद की स्थापना की थी।
- इससे देश में आभूषण-निर्माण की वास्तविक क्षमता का दोहन करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में भी मदद मिलेगी।
- यह परिषद भारत के सभी ज्वैलर्स का प्रतिनिधित्व करेगी, जो निर्वाचक मंडल होंगे।
- वे विभिन्न रूचिकर समूह बनाएंगे और उन लोगों का चुनाव करेंगे जो परिषद में बैठेंगे।

विश्व स्वर्ण परिषद

- यह स्वर्ण उद्योग के लिए बाजार विकास संगठन है। यह दुनिया के प्रमुख स्वर्ण उत्पादकों का संघ है।
- यह 1987 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में स्थित है।
- डब्ल्यू.सी.जी., स्वर्ण आरक्षित डेटा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी (आई.एफ.एस.) पर आधारित होते हैं, जो सोने के साथ ही केंद्रीय बैंकों की रिपोर्ट की गई खरीद और बिक्री को उनके अंतर्राष्ट्रीय भंडार के प्रतिशत के रूप में ट्रैक करते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

7. **आई.टी. उत्कृष्टता पुरस्कार, 2019**

- ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ओ.एस.डी.एम.ए.) ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपनी सतर्क नवाचार संकल्पना हेतु आई.टी. उत्कृष्टता पुरस्कार, 2019 जीता है।
- पुरस्कार के लिए "SATARK" (सिस्टम फॉर असेसमेंट, ट्रैकिंग एंड अलर्टिंग डिजास्टर रिस्क इन्फर्मेशन बेस्ड ऑन डॉयनमिक रिस्क नॉलेज) को चुना गया है।

संबंधित जानकारी

सतर्क

- राज्य में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं और लू, बिजली कड़कना, कृषि जोखिम, बाढ़, सुनामी, भूकंप, चक्रवात या तूफान, सड़क दुर्घटना और सर्पदंश जैसी विभिन्न आपदाओं और खतरों के लिए वास्तविक समय की सूचना, सावधानी और चेतावनी की जानकारी प्रदान करने हेतु सतर्क एप्लीकेशन विकसित किया गया है।
- यह उड़िया साथ-साथ अंग्रेजी दोनो भाषाओं में एक चेतावनी संकेत प्रदान करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –आपदा प्रबंधन

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

8. **प्रो. विस्पी बालापोरिया: एशियाई सोसाइटी की पहली महिला अध्यक्ष हैं।**

- हाल ही में, प्रो. विस्पी बालापुरिया को 215 वर्षों के अस्तित्व में मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।

संबंधित जानकारी

एशियाटिक सोसाइटी

- एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1804 में साहित्यिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के रूप में हुई थी, जिसकी स्थापना एक स्कॉटिश औपनिवेशिक प्रशासक सर जेम्स मैकिनटोश ने की थी।
- यह एक शिक्ष सोसाइटी है जिसकी गतिविधियों में ऐतिहासिक शोध करना, इतिहासकारों को पुरस्कृत करना और स्नातकोत्तर अध्ययन का एक संस्थान चलाना शामिल है।
- सोसाइटी के पुस्तकालय में 1 लाख से अधिक पुस्तकें हैं, जिनमें दुर्लभ पांडुलिपियां शामिल हैं, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा योगदान दी गई हैं और इसके साथ ही उदार दान भी देती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –इतिहास (महत्वपूर्ण संगठन)

स्रोत- लाइवमिंट

9. **दादाभाई नौरोजी: 194वीं जयंती**

- 4 सितंबर, 2019 को दादाभाई नौरोजी, "ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया" की 194वीं जयंती थी, जो देश में राष्ट्रीय चेतना फैलाने वाले प्रारंभिक नेताओं में से थे।
- इनका जन्म 1825 में नवसारी में, वर्तमान गुजरात में हुआ था। नौरोजी विभिन्न रूचियों के साथ एक प्रखर विद्वान थे।
- नौरोजी का स्थायी बौद्धिक योगदान 'अपवाह सिद्धांत' की व्याख्या करने पर था।
- वह अपने शुरुआती चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ निकटता से जुड़े थे और ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य के रूप में कार्य किया था।

इंग्लैंड में शुरुआती काम

- वर्ष 1859 में, उनका पहला आंदोलन भारतीय सिविल सेवा (वर्तमान में आई.ए.एस.) भर्ती से संबंधित था।
- इस अवधि के दौरान, नौरोजी ने इंग्लैंड में आयरिश नेताओं के साथ मिलकर काम किया था, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सामान्य कारण पाए थे।
- वर्ष 1865 और 1866 में, नौरोजी ने क्रमशः लंदन इंडियन सोसायटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को स्थापित करने में मदद की थी।
- ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के सचिव के रूप में, नौरोजी ने धन इकट्ठा करने और राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत की यात्रा की थी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता

- वर्ष 1885 में, नौरोजी बॉम्बे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने, उन्हें गवर्नर लॉर्ड रेये द्वारा बॉम्बे विधान परिषद के लिए नामित किया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाने में मदद की थी।
- वे 1886, 1893 और 1906 में तीन बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –भारतीय इतिहास

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

10. **जर्मनी, वर्ष 2023 तक ग्लाइफोसेट को चरणबद्ध तरीके से हटाएगा।**

- जर्मनी ने वर्ष 2023 के अंत तक ग्लाइफोसेट, एक रासायनिक और अंकित कार्सिनोजेन को चरणबद्ध तरीके से हटाने का निर्णय लिया है।
- यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि पारिस्थितिकी प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कीटों की जनसंख्या और खाद्य फसलों के परागण का सफाया नहीं किया जा रहा है।
- वर्ष 2023 में, रसायन के लिए यूरोपीय संघ की मंजूरी समाप्त हो जाएगी।
- हाल ही में, ऑस्ट्रिया रासायनों के सभी उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है।

संबंधित जानकारी

- कृषि, वानिकी, शहरी और घर अनुप्रयोगों में ग्लाइफोसेट का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- इसका उपयोग सुरक्षा चिंताओं के कारण बहुत बहसों से घिरा हुआ है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन की अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्था (आई.ए.आर.सी.) ने ग्लाइफोसेट को मनुष्यों के लिए "संभवतः" कार्सिनोजेनिक घोषित किया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीकी

स्रोत- डाउन टू अर्थ

09.09.2019

1. **<u>डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019</u>**

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2019 जारी की गई है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- यह रिपोर्ट बढ़ती हुई पारस्परिक वैश्विक अर्थव्यवस्था से होने वाले बड़े संभावित लाभ को रेखांकित करती है लेकिन ऐसे कई लोगो तक संपत्ति की संभावनाएं फैलाने के लिए ठोस वैश्विक प्रयासों का आहवान करती है जो वर्तमान में इससे बहुत कम लाभ उठा रहे हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और चीन के ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकियों से संबंधित सभी पेटेंटों के 75 प्रतिशत हेतु, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आई.ओ.टी.) पर किए गए वैश्विक खर्च के 50 प्रतिशत और पब्लिक क्लाउड गणना हेतु विश्व बाजार के 75 प्रतिशत से अधिक हेतु जिम्मेदार हैं।
- भारत ने वर्ष 2017 में वैश्विक स्तर पर नौवीं सबसे अधिक ई-कॉमर्स बिक्री की है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में 15% का योगदान था।
- इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि विकासशील देशों के लिए प्रभावी आर्थिक स्वामित्व और अपने क्षेत्रों में उत्पन्न आंकड़ों पर नियंत्रण रखने का एकमात्र तरीका अनिवार्य डेटा स्थानीयकरण पर जोर देना था।

संबंधित जानकारी

डेटा स्थानीयकरण

- डेटा स्थानीयकरण कानून, उन नियमों को इंगित करता है जो यह आदेशित करते हैं कि एक राष्ट्र के नागरिकों पर डेटा को किस प्रकार एकत्रित, प्रसंस्कृत और संग्रहीत किया जाता है।
- स्थानीयकरण यह शासनादेश देता है कि उपभोक्ताओं के बारे में महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करने वाली कंपनियों को उस डेटा को अवश्य ही देश की सीमाओं के भीतर संग्रहीत और संसाधित करना चाहिए।

डेटा स्थानीयकरण पर भारत का रुख

- वर्तमान में, भारत में डेटा स्थानीयकरण पर एकमात्र अनिवार्य नियम, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान प्रणाली हेतु है।
- इसका दूसरा भाग, मसौदा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2018 है, जिसमें सीमा-पार डेटा स्थानांतरण पर विशिष्ट आवश्यकताएं हैं।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन

- यह 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा है।
- इसका गठन विशेष रूप से व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से निपटने वाले विकासशील देशों की समस्याओं के समाधान हेतु किया गया था।

यू.एन.सी.टी.ए.डी. द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट

- सूचना एवं अर्थव्यवस्था रिपोर्ट
- विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट
- व्यापार एवं विकास रिपोर्ट
- विश्व निवेश रिपोर्ट
- न्यूनतम विकसित देशों की रिपोर्ट
- प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट
- माल एवं विकास रिपोर्ट

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –अर्थशास्त्र (महत्वपूर्ण रिपोर्ट)

स्रोत- इकानॉमिक टाइम्स

2. **<u>सरकार ने राष्ट्रीय बुनियादी (इन्फ्रा) पाइपलाइन का प्रारूप तैयार करने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया है।</u>**

- सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक 100 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय बुनियादी

पाइपलाइन का प्रारूप तैयार करने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया है।

- इसकी अध्यक्षता आर्थिक मामलों के सचिव करेंगे।

टास्क फोर्स के शासनादेश

- तकनीकी रूप से संभावित और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान करना जिन्हें चालू वित्त वर्ष में शुरू किया जा सकता है।
- टासक फोर्स वार्षिक अवसंरचना निवेश लागतों का अनुमान लगाएगा और वित्त पोषण के उपयुक्त स्रोतों की पहचान करने हेतु मंत्रालयों का मार्गदर्शन करेगा।
- यह परियोजनाओं की निगरानी के लिए उपाय भी सुझाएगा जिससे कि लागत और समय की अधिकता कम हो।
- शेष 5 वर्षों में से प्रत्येक के लिए पाइपलाइन में शामिल की जाने वाली परियोजनाओं को सूचीबद्ध करने पर काम करना

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय बुनियादी पाइपलाइन

- इसमें 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाएं शामिल होंगी।
- यह भारत निवेश ग्रिड और राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष के माध्यम से निजी निवेश की आवश्यकता वाली परियोजनाओं के पाइपलाइन के विपणन को भी सक्षम बनाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –ढांचा

स्रोत- द हिंदू

3. **<u>डब्ल्यू.एच.ओ. दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र वर्ष 2023 तक खसरा, रूबेला को खत्म करने की योजना बना रहे हैं।</u>**

- हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्ल्यू.एच.ओ.) के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के सदस्य देशों ने वर्ष 2023 तक बच्चों में होने वाली अत्यिधक संक्रामक जानलेवा बीमारियों: खसरा और रूबेला को खत्म करने का संकल्प लिया है, इसे समाप्त करने की समय सीमा पहले वर्ष 2020 थी।
- बीमारियों को खत्म करने का संकल्प दिल्ली में दक्षिण-पूर्व एशिया के डब्ल्यू.एच.ओ. क्षेत्रीय समिति के 72वें सत्र में अपनाया गया था।

संबंधित जानकारी

खसरा और रूबेला

- दोनों ही संक्रामक विषाणुजनित बीमारियां हैं जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर खांसी और छींक के माध्यम से फैलती है।
- खसरा, रूबेला विषाणु के कारण होता है जब कि रूबेला, रूबेला विषाणु के कारण होता है।
- खसरा और रुबेला दोनों को एम.एम.आर. (खसरा, कण्ठमाला और रूबेला) वैक्सीन की दो खुराक के साथ पूरी तरह से रोका जा सकता है।

उन्मूलन प्रयास

- भारत ने वर्ष 2017 में विश्व का सबसे बड़ा खसरा-रूबेला (एम.आर.) अभियान शुरू किया था।
- इसमें 9 महीने से 15 वर्ष के बीच की आयु के 410 मिलियन बच्चों और किशोरों के टीकाकरण का लक्ष्य रख गया है।
- ये मिशन इन्द्रधनुष के अंतर्गत भी आते हैं, जिसे 2014 में लॉन्च किया गया था।
- इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2020 तक उन सभी बच्चों को शामिल करना है जिनका टीका संक्रामक बीमारियों के लिए या तो टीकाकरण नहीं हुआ है या आशिंक रूप से टीकारकण हुआ है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) दक्षिण-पूर्व एशिया

- इसके 11 सदस्य देश- बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान,

डी.पी.आर. कोरिया, म्यांमार, मालदीव और तिमोर-लेस्ते हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –स्वास्थ्य एवं सामाजिक मुद्दे

स्रोत- ए.आई.आर.

4. **<u>स्लीनेक्स 2019</u>**

- यह भारत और श्रीलंका के मध्य द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास है।
- यह द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेनाओं को अभ्यास करने और अपनी क्षमता में सुधार करने और हिंद महासागर क्षेत्र (आई.ओ.आर.) में समुद्री सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाने में सक्षम बनाएगा।

नोट:

- मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –रक्षा

स्रोत- डी.डी. न्यूज

5. **<u>राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम</u>**

- प्रधानमंत्री ने मथुरा में पैर और मुंह के रोग और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम

- पैर और मुंह के रोग और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है।
- इसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक टीकाकरण के साथ पैर और मुंह के रोग और ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करना और वर्ष 2030 तक इसका संभावित उन्मूलन करना है।

पैर और मुंह रोग (एफ.एम.डी.)

- यह पशुओं की एक गंभीर, अत्यधिक संक्रामक विषाणुजनित बीमारी है जिसका एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव है।
- यह बीमारी मवेशियों, सूअर, भेड़, बकरियों और अन्य विभाजित खुर वाले जुगाली करने वाले पशुओं को प्रभावित करती है।
- यह बीमारी तब फैल सकती है जब संक्रमित जानवर विषाणु को अतिसंवेदनशील जानवरों के संपर्क में लाते हैं।

ब्रूसिलोसिस

- यह जीवाणु संबंधी वंश ब्रुसेला के कारण होने वाला एक जूनोटिक संक्रमण है।
- यह जीवाणु जानवरों से मनुष्यों में संक्रमित खाद्य उत्पादों, संक्रमित जानवर के सीधे संपर्क या साँस लेने में ऐरोसॉल के अंदर जाने के माध्यम से प्रवेश कर सकता हैं।
- इस बीमारी को लहरदार बुखार, माल्टा बुखार और भूमध्य बुखार के रूप में भी जाना जाता है।
- ब्रुसेलोसिस के मामले में, पशु के पूरे जीवन चक्र के दौरान दूध का उत्पादन 30% कम हो जाता है और पशुओं में बांझपन का कारण बनता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

6. **<u>भारत ने भूमि निम्नीकरण को पुन: बहाल करने के लक्ष्य को बढ़ाया है।</u>**

- प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि भारत, वर्ष 2030 तक भूमि निम्नीकरण को पुन: बहाल करने के लक्ष्य को इक्कीस मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर छब्बीस मिलियन हेक्टेयर कर देगा।

संबंधित जानकारी

- भारत, ग्रेटर नोएडा में सी.ओ.पी.14 के लिए एक वैश्विक सभा की मेजबानी कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र मरूस्थलीकरण निपटान सम्मेलन (यू.एन.सी.सी.डी.)

- इसे 1994 में स्थापित किया गया था और यह एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ता है।

- यह विशेष रूप से शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों को संबोधित करता है, जिसे शुष्क भूमि के रूप में जाना जाता है, यह कुछ सबसे अधिक लुप्तप्राय पारिस्थितिक तंत्र और लोगों का निवास स्थान है।
- सी.ओ.पी. 14 के लिए मुख्य एजेंडा संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के दृष्टिकोण के साथ लोगों और पारिस्थितिक तंत्र के लिए सकारात्मक उपलब्धियों में तेजी लाने के दौरान भूमि क्षरण और इसके परिणामों को विपरीत कर रहा है।
- जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान के साथ मिलकर काम करने वाले भूमि क्षरण से वर्ष 2050 तक 700 मिलियन लोग पलायन कर सकते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- ए.आई.आर.

7. **<u>बेटी बचाओ बेटी पढाओ</u>**

- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने उन जिलों और राज्यों को सम्मानित किया है जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढाओं योजना को सफलतापूर्वक लागू करके जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार किया है।
- हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार करने हेतु सम्मानित किया गया है।
- इसके अतिरिक्त जन्म के समय बेहतर लिंग अनुपात हेतु 9 जिलों को भी सम्मानित किया गया है, ये जिले: अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी कामेंग, हरियाणा का महेंद्रगढ़ और भिवानी, उत्तराखंड का उधम सिंह नगर, तमिलनाडु का नामक्कल और महाराष्ट्र का जलगाँव जिला है।
- इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंग अनुपात में भी 13 अंकों की वृद्धि हुई है जो वर्ष 2014-15 में 918 से वर्ष 2018-19 में बढ़कर 931 हो गया है।

संबंधित जानकारी

बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं योजना

- यह 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था।
- इसका उद्देश्य गिरते हुए बाल लिंगानुपात इमेज (सी.एस.आर.) के मुद्दे को संबोधित करना है और यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक राष्ट्रीय पहल है।
- बाल लिंगानुपात को 0-6 वर्ष के आयु वर्ग में प्रति 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –महिला सशक्तीकरण

स्रोत- पी.आई.बी.

8. **<u>लैंप ऑफ पीस ऑफ सैंट फ्रांसिस</u>**

- हाल ही में, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस को शांति और सौहार्द स्थापित करने की दिशा में उनके योगदान हेतु वेटिकन द्वारा लैम्प ऑफ पीस ऑफ संट फ्रांसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

संबंधित जानकारी

लैम्प ऑफ़ पीस ऑफ़ संट फ्रांसिस अवार्ड

- यह पुरस्कार लोगों के मध्य शांति और संवाद को बढ़ावा देने के लिए एक व्यक्ति द्वारा किए गए प्रतिष्ठित कार्य की पहचान है।
- द लैंप ऑफ़ पीस पुरस्कार, पहली बार वर्ष 1981 में पोलिश व्यापारी संघ नेता लेच वाल्सा को दिया गया था।
- दलाई लामा, मिखाइल गोर्बाचेव और एंजेला मॉर्केल कुछ अन्य प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्हें पहले यह पुरस्कार प्रदान किया गया था।

नोट:

- प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस को ग्रामीण बैंक की स्थापना और सूक्ष्मऋण और सूक्ष्मवित्त की अग्रणी अवधारणाओं के लिए नोबेल शांति पुरस्कार (2008) से सम्मानित किया गया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –कला एवं संस्कृति

स्रोत- ए.आई.आर.

9. **<u>मुंबई में पहला 'मेक इन इंडिया' मेट्रो कोच</u>**

- प्रधानमंत्री ने मुंबई में पहला 'मेक इन इंडिया' मेट्रो कोच लॉन्च किया है।
- इस कोच का निर्माण भारत अर्थ मूवर्स (बी.ई.एम.एल.) ने अपने बेंगलुरु संयंत्र में किया था।

टॉपिक- पी.सी.एस. हेतु महत्वपूर्ण

स्रोत- हिंदुस्तान टाइम्स

10. **<u>रोहित शर्मा ने गैंडों के संरक्षण हेतु "रोहित4राइनोस" नामक एक अभियान शुरू किया है।</u>**

- भारतीय क्रिकेट टीम के उप-कप्तान रोहित शर्मा एक सींग वाले, ग्रेटर वन-हॉर्न गैंडे या भारतीय गैंडे के संरक्षण की आवश्यक्ताओं हेतु जागरूकता पैदा करने में मदद करने जा रहे हैं।
- रोहित शर्मा ने विश्व गैंडा दिवस (22 सितंबर को) पर डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. इंडिया और एनीमल प्लैनेट की साझेदारी में रोहित4राइनो अभियान की शुरुआत की है, जिसमें रोहित ने "लुप्तप्राय" प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपना काम करने का संकल्प लिया है।
- रोहित शर्मा वर्ष 2018 में गैंडा संरक्षण के लिए डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. इंडिया में ब्रांड एंबेसडर के रूप में शामिल हुए थे।

टॉपिक- जी.एस.-3- पर्यावरण

स्रोत- हिंदुस्तान टाइम्स

10.09.2019

1. **<u>प्रत्येक तीन वर्ष में आर्थिक जनगणना का आयोजन किया जाएगा।</u>**

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई.) ने कहा है कि अब प्रत्येक तीन वर्ष में आर्थिक जनगणना आयोजित की जाएगी।

संबंधित जानकारी

आर्थिक जनगणना

- यह देश की भौगोलिक सीमा के भीतर स्थित सभी आर्थिक प्रतिष्ठानों की संपूर्ण गणना है।
- यह देश के सभी प्रतिष्ठानों के विभिन्न परिचालन और संरचनात्मक चर पर विभिन्न जानकारी प्रदान करती है।
- यह जनगणना भौगोलिक प्रसार और आर्थिक गतिविधियों, स्वामित्व प्रारूपों, देश के सभी आर्थिक प्रतिष्ठानों में संलग्न व्यक्तियों के समूहों को भी मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
- इसके पहले 1980, 1990, 1998, 2005 में आर्थिक जनणना आयोजित की गई थी।
- छठीं जनगणना, वर्ष 2013 में आयोजित की गई थी।

सातवीं आर्थिक जनगणना:

- सातवीं आर्थिक जनगणना का आयोजन वर्ष 2019 में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- एम.ओ.एस.पी.आई. ने सातवीं आर्थिक जनगणना के लिए कार्यान्वयन संस्था के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विशेष प्रायोजन वाहन, सामान्य सेवा केंद्र ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है।
- आंकड़ों के संग्रह अधिनियम 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान के डोर टू डोर सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- सरकार ने रोजगार डेटा में सुधार करने के तरीके और उपाय सुझाने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में मई, 2017 को रोजगार डेटा में सुधार करने हेतु एक टास्क फोर्स की नियुक्ति की थी।
- टास्क फोर्स ने अगस्त, 2017 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में विभिन्न सिफारिशें की हैं।
- कार्यान्वयन सातवीं आर्थिक जनगणना के साथ शुरू होकर प्रत्येक 3 वर्ष में आर्थिक जनगणना का कार्य कर सकता है।
- यह प्रतिष्ठानों की विभिन्न आर्थिक विशेषताओं पर निरंतर रूप से अधिक जानकारी प्रदान करने में मदद करता है और इसकी तुलना जी.एस.टी.एन., ई.पी.एफ.ओ., एम.सी.ए. आदि में मौजूदा डेटाबेस से की जा सकती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- टी.ओ.आई.

2. **<u>राष्ट्रीय जीनोमिक ग्रिड</u>**

- सरकार ने भारत के कैंसर रोगियों के जीनोमिक डेटा का अध्ययन करने के लिए एक राष्ट्रीय जीनोमिक ग्रिड स्थापित करने की घोषणा की है।
- गठित की जाने वाली ग्रिड, मद्रास के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित राष्ट्रीय कैंसर ऊतक बायोबैंक के अनुरूप होगी।
- इस ग्रिड के चार भाग होंगे जो कि देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में विभाजित होंगे।
- इस ग्रिड का उद्देश्य कैंसर को प्रभावित करने वाले आनुवांशिक कारकों का अध्यन करने हेतु कैंसर के रोगियों के नमूने एकत्र करना और भारतीय आबादी के लिए सही उपचार के साधनों की पहचान करना है।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय कैंसर ऊतक बायोबैंक

- यह एक अत्याधुनिक गैर-लाभकारी समुदाय-आधारित ऊतक बायोबैंक है, जो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और चेन्नई के मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की एक संयुक्त पहल है।
- यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ घनिष्ठ सहयोग में काम करता है

नोट:

- सरकार प्रत्येक 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मिशन पर लगी हुई थी, जो 1/1400 के वर्तमान अनुपात की तुलना में वर्ष 2022 तक डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा निर्धारित मानक अनुपात है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

3. **<u>मोतीहारी-अमलेखगंज सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन</u>**

- प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली संयुक्त रूप से मोतिहारी-अमलेखगंज सीमापार पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे।

संबंधित जानकारी

मोतिहारी-अमलेखगंज पाइप लाइन

- यह भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम पाइपलाइन है और पहला दक्षिण एशियाई तेल पाइपलाइन गलियारा है।
- यह पाइपलाइन नेपाल को पेट्रोलियम उत्पादों की सुगम, लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।
- यह बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक 69 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, जिसका निर्माण भारत द्वारा किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –ढांचा

स्रोत- ए.आई.आर.

4. **उत्तर पूर्वी परिषद का 68वां पूर्ण सत्र**

- उत्तर पूर्वी परिषद (एन.ई.सी.) का 68वां पूर्ण सत्र गुवाहाटी में आयोजित किया गया था।

संबंधित जानकारी

उत्तर पूर्वी परिषद

- यह उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 के अंतर्गत गठित एक संवैधानिक सलाहकार निकाय है।
- उत्तर पूर्वी परिषद, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु नोडल संस्था है।
- यह अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा आठ राज्यों से मिलकर बना है।
- सिक्किम को परिषद में वर्ष 2002 में जोड़ा गया था।
- परिषद का मुख्यालय, शिलांग में स्थित है और यह परिषद भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

5. **भारत में एक दशक में 31% घास के मैदानों की कमी हुई है।**

- भारत में एक दशक में चरागाह क्षेत्र के 31 प्रतिशत या 65 मिलियन हेक्टेयर (एम.एच.ए.) हिस्से की कमी हुई है, यह चल रहे पार्टियों के सम्मेलन (सी.ओ.पी.) में केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र मरूस्थलीकरण निपटान सम्मेलन को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों में प्रदर्शित होती है।
- घास के मैदान के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल वर्ष 2005 और 2015 के बीच 18 एम.एच.ए. से घटकर 3 एम.एच.ए. हो गया है।
- राजस्थान में अरावली श्रृंखला में घास के मैदान गंभीर पतन से गुजर रहे हैं। अन्य राज्य जहां भूमि गंभीर रूप से नष्ट हो गई है, उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
- चराई की भूमि के नुकसान हेतु दो प्रकार के कारकों- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- अत्यधिक चराई, खराब प्रबंधन और वनों की कटाई प्रत्यक्ष कारक हैं और बढ़ती आबादी के दबाव से होने वाले अतिक्रमण, परिवर्तन और अवंटन के माध्यम से चारागाहों को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करना अप्रत्यक्ष कारक हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, देश ने समान अवधि के दौरान अपनी समान भूमि का लगभग 19 प्रतिशत हिस्सा खो दिया है।
- सामान्य भूमि के अंतर्गत वर्ष 2005 से 2015 के बीच क्षेत्रफल लगभग 5 एम.एच.ए. से घटकर 73.02 एम.एच.ए. हो गया है।

संबंधित जानकारी

- सामान्य भूमि में चरागाह, कुछ वन भूमि, तालाब, नदियाँ और अन्य क्षेत्र शामिल हैं, जिससे कि एक ग्रामीण समुदाय के सभी सदस्य उस तक पहुँच सके और उपयोग कर सकें।
- वे ग्रामीण समुदायों को भोजन, पानी, चारा, जलाऊ लकड़ी और आजीविका प्रदान करते हैं, जब कि भूजल रिचार्ज करने और भूमि के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- डाउन टू अर्थ

6. **नई दिल्ली ने एस.सी.ओ. सदस्य राज्यों के लिए सैन्य चिकित्सा पर पहले सम्मेलन की मेजबानी की है।**

- हाल ही में, शंघाई सहयोग संगठन (एस.सी.ओ.) के सदस्य राज्यों हेतु सैन्य चिकित्सा पर पहले सम्मेलन का नई दिल्ली में आयोजन किया गया था।

65TH BPSC
TEST SERIES 2019
CHECK HERE

- यह सम्मेलन, वर्ष 2017 में एस.सी.ओ. सदस्य-राज्य बनने के बाद एस.सी.ओ. रक्षा सहयोग योजना 2019-2020 के अंतर्गत भारत द्वारा आयोजित पहला सैन्य सह-संचालन कार्यक्रम होगा।
- इस सम्मेलन का आयोजन मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ (एच.क्यू.आई.डी.एस.) के तत्वावधान में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया जाएगा, जिसका उद्देश्य सैन्य चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, क्षमताओं का निर्माण करना और सामान्य चुनौतियों से पार पाना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –रक्षा

स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

7. **<u>जैवउत्प्रेरक, प्रवाह स्त्राव को कम करता है।</u>**

- केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.-सी.एल.आर.आई.), चेन्नई के शोधकर्ताओं ने एमाइलेज-आधारित जैवउत्प्रेरक विकसित किया है, जो चमड़े को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से संसाधित करने में मदद करता है।
- इस प्रक्रिया में किसी रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है जो रासायनिक ऑक्सीजन की मांग को लगभग 35% कम करने में मदद करता है जब कि कुल ठोस प्रवाह भार 50% से अधिक कम हो जाता है।
- यह प्री-टैनिंग चरण में त्वचा को संसाधित करने में लगने वाले समय में भारी कटौती करने में मदद करेगा क्यों कि प्री-टैनिंग, प्रक्रिया प्रसंस्करण के दौरान कुल प्रदूषण का 60-70% उत्पन्न करता है।
- क्रोमियम का उपयोग सह-संबंध के माध्यम से कोलेजन की स्थिरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है।
- इससे पर्यावरण में क्रोमियम का निर्वहन होता है।

सम्बंधित जानकारी

रासायन ऑक्सीजन मांग

- इसे सभी कार्बनिक कार्बनों को पूरी तरह से CO2 और H2 में ऑक्सीकृत करने हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है।
- यह पानी में बैक्टीरिया की कार्रवाई के परिणामस्वरूप शरीर द्वारा खपत करने वाली ऑक्सीजन की मात्रा निर्धारित करने की एक विधि है।

नोट:

- जैवउत्प्रेरक, एक एंजाइम या एक प्रोटीन है जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता या उत्प्रेरित करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीकी

स्रोत- द हिंदू

11.09.2019

1. **<u>संजय मित्रा: जम्मू-कश्मीर के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन की देखरेख करने हेतु पैनल का गठन किया गया है।</u>**

- केंद्र ने जम्मू-कश्मीर के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन की देखरेख करने हेतु पूर्व रक्षा सचिव संजय मित्रा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया है।

समिति के संदर्भ में जानकारी

- यह समिति दो उत्तराधिकारी केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जम्मू और कश्मीर की परिसंपत्तियों और देनदारियों के वितरण पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो इस वर्ष 31 अक्टूबर से अस्तित्व में आएंगे।
- समिति के अन्य सदस्य सेवानिवृत्त आई.ए.एस. अधिकारी अरुण गोयल और सेवानिवृत्त भारतीय नागरिक लेखा सेवा अधिकारी गिरिराज प्रसाद गुप्ता हैं।

संबंधित जानकारी

- 5 अगस्त, 2019 को केंद्र ने जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत प्रदान किए गए विशेष दर्जे को समाप्त करने और राज्य का दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन करने की घोषणा की थी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –भारतीय संविधान

स्रोत- ए.आई.आर.

2. **<u>यू.एन.एच.आर.सी. ने भारत को जम्मू-कश्मीर में तालाबंदी खत्म करने के लिए कहा है।</u>**

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 42वें सत्र में, संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने भारत से कश्मीर में तालाबंदी को समाप्त करने और बुनियादी संचार सेवाओं को बहाल करने का आग्रह किया है।
- मिशेल बेचेलेट, संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने भारत से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि असम में राष्ट्रीय नागरिक सत्यापन रजिस्टर में लोग राज्यविहीन न हो जाएं।
- यू.एन.एच.आर.सी. के 42वें सत्र का आयोजन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के यूरोपीय मुख्यालय में किया गया था।

संबंधित जानकारी

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद

- यह एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है और 2006 में स्थापित किया गया था।
- इसका मिशन पूरे विश्व में मानवाधिकारों का संवर्धन और संरक्षण करने के साथ-साथ कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना है।
- इसमें 5 समूहों से एक क्षेत्रीय समूह के आधार पर 47 सदस्य चुने गए हैं।
- सदस्यों को अधिकतम दो क्रमागत कार्यकाल के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है।
- मानवाधिकारों के मुद्दों पर बहस करने और बहुमत द्वारा गैर-बाध्यकारी प्रस्तावों और सिफारिशों को पारित करने के लिए वर्ष में लगभग तीन बार सदस्यों की बैठक होती हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –अंतर्राष्ट्रीय संगठन

स्रोत- ए.आई.आर.

3. **<u>सी.एच.सी. फार्म मशीनरी: किसानों के लिए एक बहुभाषी मोबाइल ऐप</u>**

- कृषि राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में फसल अवशेष प्रबंधन पर एक सम्मेलन के दौरान एक बहुभाषी मोबाइल ऐप "सी.एच.सी. फार्म मशीनरी" लॉन्च किया है।

ऐप के संदर्भ में जानकारी

- यह किसानों को 50 कि.मी. के दायरे में स्थित सी.एच.सी. की कस्टम हायरिंग सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करेगा।
- यह ऐप किसानों को उनके क्षेत्र में कस्टम हायरिंग सेवा केंद्रों से जोड़ता है।

संबंधित जानकारी

कस्टम हायरिंग केंद्र

- कृषि उपकरणों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर (सी.एच.सी.) की स्थापना 100 एन.आई.सी.आर.ए. (राष्ट्रीय जलवायु तन्यक कृषि नवाचार) में की गई है, जो किसानों को श्रम की कमी से निपटने और कृषि कार्यों की दक्षता में सुधार करने के लिए सफलतापूर्वक सशक्त बनाती है।
- ग्राम सभा द्वारा नामित किसानों की एक समिति कस्टम हायरिंग केंद्रो का प्रबंधन करती है।
- 100 सी.एच.सी. में 25 से अधिक विभिन्न प्रकार की कृषि मशीनरी का भंडारण किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

65TH BPSC
TEST SERIES 2019
CHECK HERE

4. **<u>अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता पर सम्मेलन "ANGAN" का नई दिल्ली में आयोजन किया गया है।</u>**

- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हरित किफायती नवीन आवास द्वारा प्रकृति संवर्धन (ANGAN), निर्माण क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता पर केंद्रित है, जिसका दिल्ली में आयोजन किया गया है।
- यह सम्मेलन भारतीय जर्मनी प्रौद्योगिकी सहयोग के अंतर्गत जी.आई.जेड. के साथ ऊर्जा मंत्रालय के तत्वावधान में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी.ई.ई.) द्वारा आयोजित किया गया था।
- उन्होंने ऊर्जा-कुशल इमारतों के डिजाइन और निर्माण के क्षेत्र में वैकल्पिक विकल्पों और प्रौद्योगिकियों पर चर्चा की है।
- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बेहतर संसाधन दक्षता के लिए संगठनों, निरंतरता और फीडबैक के मध्य अंतर-निर्भरता पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –ऊर्जा

स्रोत- इकोनॉमिक टाइम्स

5. **<u>आयोडीन युक्त नमक के आवृत्त क्षेत्र के संदर्भ में तमिलनाडु सबसे नीचे है।</u>**

- आयोडीन युक्त नमक के आवृत्त क्षेत्र को मापने के लिए एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, देश में नमक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद तमिलनाडु में आयोडीन युक्त नमक की सबसे कम खपत है।
- यह सर्वेक्षण एम्स, दिल्ली और भारतीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण गठबंधन के सहयोग से न्यूट्रीशन इंटरनेशनल द्वारा आयोजित किया गया था।
- यह सर्वेक्षण घरों से नमक के नमूनों में आयोडीन की मात्रा का परीक्षण करता है, जिससे कि भारत में 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोडीन युक्त नमक के आवृत्त क्षेत्र का अनुमान लगाया जा सके।

सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं

- घरेलू कवरेज का राष्ट्रीय औसत 3% है अर्थात 76.3% भारतीय घरों में पर्याप्त रूप से आयोडीन युक्त नमक का सेवन किया जाता है, जो कि ऐसा नमक है जिसमें 15 पार्ट प्रति मिलियन आयोडीन है।
- पांच सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य तमिलनाडु (9%), आंध्र प्रदेश (63.9%), राजस्थान (65.5%), ओडिशा (65.8%) और झारखंड (68.8%) थे।
- गुजरात देश में 71% नमक का उत्पादन करता है, इसके बाद राजस्थान 17% और तमिलनाडु 11% नमक का उत्पादन करता है।
- शेष देश में लगभग 1% नमक का उत्पादन होता है।
- 36 राज्यों में से 13 राज्यों ने पहले ही सार्वभौमिक नमक आयोडाइजेशन हासिल कर लिया है।

संबंधित जानकारी

आयोडीन

- मनुष्य के इष्टतम मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आयोडीन एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है।
- आयोडीन की कमी के परिणामस्वरूप विकलांगता और विकारों की एक श्रृंखला हो सकती है जैसे कि घेंघा, हाइपोथायरायडिज्म, बौनापन, गर्भपात, मृतजन्म, मानसिक मंदता और साइकोमोटर विकार हैं।
- आयोडीन की कमी वाले क्षेत्रों में पैदा होने वाले बच्चों में, आयोडीन की पर्याप्त मात्रा वाले क्षेत्रों में पैदा होने वालों की तुलना में 5 आई.क्यू. अंक कम हो सकते हैं।

- भारत ने 1992 में प्रत्यक्ष मानव उपभोग के लिए आयोडीन के साथ नमक के उत्पादन को अनिवार्य कर दिया था, जो कि 2000 में समाप्त हो गया था और फिर 2005 में पुन: स्थापित किया गया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस (महत्वपूर्ण रिपोर्ट)

स्रोत- द हिंदू

6. **विश्व ऊर्जा सम्मेलन, अबूधाबी में शुरू होने वाला है।**

- 24वां विश्व ऊर्जा सम्मेलन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के संरक्षण में अबूधाबी में शुरू होनेव वाला है।
- चार दिवसीय विश्व ऊर्जा सम्मेलन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा हितधारकों को एक साथ लाना है, जिसमें सरकारें, निजी और राज्य निगम, अकादमी और मीडिया शामिल हैं।
- इस विश्व ऊर्जा सम्मेलन की थीम, समृद्धि के लिए ऊर्जा है जो देश के महत्वाकांक्षी और गतिशील ऊर्जा संक्रमण का भी प्रतिनिधित्व करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3– ऊर्जा

स्रोत- ए.आई.आर.

7. **केरल, महिलाओं के लिए भारत का पहला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा।**

- केरल, कोझिकोड में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) के अनुरूप, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र (आई.डब्ल्यू.टी.सी.) स्थापित करेगा।
- आई.डब्ल्यू.टी.सी. का पहला चरण, जेंडर पार्क के "विज़न 2020" के अंतर्गत निष्पादित किया जा रहा है, जिसे 2021 तक पूरा किया जाना है।
- आई.डब्ल्यू.टी.सी., महिला उद्यमियों को आगे आने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने, अधिक आर्थिक लाभ का आनंद लेने और बाजार के अवसरों का दोहन करने के लिए उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में उन्हें सक्षम करेगा।
- इसका विशेष जोर आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं, हाशिए पर रहने वाले समूहों, विकलांग महिलाओं और किन्नरों को सहारा देने और उन्हें आगे लाने और उनकी उद्यमिता क्षमताओं का पोषण करने में मदद करने हेतु सबसे आगे होगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2– सरकारी नीतियां

स्रोत- ई.टी.

8. **वर्ष 2050 तक मलेरिया का उन्मूलन: लैंसेट रिपोर्ट**

- हाल ही में, मलेरिया उन्मूलन पर लैंसेट आयोग की एक रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि शीघ्र से शीघ्र वर्ष 2050 की शुरुआत तक मलेरिया का उन्मूलन संभव है।

वैश्विक मलेरिया रूझान

- वर्ष 2000 के बाद से, वैश्विक मलेरिया की घटनाओं और मृत्यु दर में क्रमशः 36% और 60% की कमी आई है।
- वर्तमान में, दुनिया के आधे से अधिक देश मलेरिया मुक्त हैं।
- हालांकि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के 55 देशों में मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं।
- नाइजीरिया और लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, वैश्विक मामलों के 36% हेतु जिम्मेदार हैं।
- विश्लेषण से संकेत मिलता है कि सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय रुझान, मलेरिया हस्तक्षेप के बेहतर कवरेज के साथ मिलकर सुधार दर्शा रहे हैं, जो इंगित करता है कि शीघ्र से शीघ्र वर्ष 2050 की शुरुआत तक मलेरिया के उन्मूलन में मदद करेंगे।
- वर्ष 2050 तक उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, रिपोर्ट में मलेरिया मामलों में गिरावट को तेज करने के 3 तरीकों की पहचान की गई है:

1. दुनिया को मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार करना चाहिए।
2. दुनिया को उन्मूलन के लिए जैविक चुनौतियों को दूर करने के लिए नए नए उपकरणों का विकास और कार्यानवन करना होगा।
3. मलेरिया-स्थानिक देशों और दाताओं को आवश्यक वित्तीय निवेश प्रदान करना चाहिए।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –स्वास्थ्य

स्रोत- द हिंदू

12.09.2019

1. **<u>प्रधानमंत्री मोदी ने रांची में किसान मानधन योजना शुरू की है।</u>**

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में किसान मानधन योजना और ख़ुदरा व्यापारी दुकानदार स्वरोजगार पेंशन योजना का शुभारंभ किया है।

संबंधित जानकारी

किसान मानधन योजना

- यह योजना 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में किसानों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी योजना है और 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उन्हें 3000 रूपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
- किसानों को पेंशन निधि में प्रति माह 55 रूपए से 200 रूपए तक का योगदान देना होगा, यह उनके सेवानिवृत्त होने की तारीख अथवा 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर उनकी आयु पर निर्भर करता है।
- केंद्र सरकार भी पेंशन निधि में समान धनराशि का समान योगदान प्रदान करेगी।
- पति/ पत्नी भी पेंशन निधि में अलग से योगदान करके 3000 रूपए प्रति माह तक की मासिक पेंशन प्राप्त कर सकने के पात्र हैं।
- एल.आई.सी., पेंशन निधि की प्रबंधक होगी और पेंशन भुगतान हेतु जिम्मेदार होगी।
- लाभार्थी 5 वर्षों के नियमित योगदान के बाद स्वेच्छा से योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –सरकारी योजना

स्रोत- पी.आई.बी.

2. **<u>सूखा (ड्राउट) टूलबॉक्स</u>**

- संयुक्त राष्ट्र मरूस्थलीकरण निपटान सम्मेलन (यू.एन.सी.सी.डी.) ने ग्रेटर नोएडा में सी.ओ.पी.14 के 10वें दिन एक 'सूखा (ड्राउट) टूलबॉक्स' का शुभारंभ किया है।
- यह एक प्रकार का ज्ञान कोष है, जिसका उपयोग भारत सहित कमजोर देशों द्वारा किया जा सकता है, जिससे कि सूखे के जोखिम को कम किया जा सके, सूखे के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहा जा सके और प्रभावी रूप से इसकी प्रतिक्रिया दी जा सके।
- सूखा (ड्राउट) टूलबॉक्स एक ऑनलाइन वेब प्लेटफ़ॉर्म है जो हितधारकों को सूखे के प्रति व्यक्तियों और पारिस्थितिकी के संवर्धन और तन्यता के उद्देश्य के साथ सूखे की तैयारियों पर कार्रवाई का समर्थन करने के लिए केस स्टडी करने और अन्य संसाधनों तक आसान पहुंच प्रदान करता है।
- इस टूल को सूखे की तैयारी के तीन स्तंभों के अनुरूप वर्गीकृत किया गया है:
- निर्णय निर्माताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी और पूर्वानुमान उपकरण
- हॉटस्पॉट की पहचान करने हेतु भेद्यता मूल्यांकन उपकरण
- प्रमुख "नीति" और "तकनीकी" उपायों के साथ जोखिम शमन उपकरण
- अधिकांश देशों में सूखा घोषित करने की वर्तमान प्रक्रिया बहुत जटिल है, इस उपकरण की मदद से देश अपने क्षेत्रों में सूखा भेद्यता का आसानी से आकलन और मूल्यांकन कर सकते हैं।

संबंधित जानकारी

भारत में सूखा घोषणा

- सूखे को सामान्यत: एक विस्तारित अवधि में सामान्यत: एक या अधिक मौसमों में पानी/ वर्षा में कमी के रूप में माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पानी की कमी हो जाती है जो वनस्पति, जानवरों और/ या लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
- भारत में सूखे की कोई एक, कानूनी रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है।
- भारत सरकार ने सूखे के प्रबंधन के संबंध में दो महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रकाशित किए हैं।
- पहला कदम दो अनिवार्य संकेतकों की जांच करना है, ये दो संकेतक- वर्षा विचलन और शुष्क अवधि है।
- यह विचलन की सीमा पर निर्भर करता है और या तो यहां शुष्क अवधि है या नहीं है, मैनुअल विभिन्न स्थितियों को निर्दिष्ट करता है जो या तो सूखा ट्रिगर माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है।
- अगला कदम चार प्रभावी संकेतकों पर ध्यान देना है, ये संकेतक कृषि, सुदूर संवेदन पर आधारित वनस्पति सूचकांक, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान हैं।
- प्रत्येक प्रभाव पर विभिन्न सूचकांकों के आधार पर पहुँचा जाता है।
- सूखे की तीव्रता: राज्य, सूखे के आकलन और आपदा की तीव्रता के लिए चार प्रकार के प्रभावी संकेतकों (प्रत्येक से एक) में से किन्ही तीन पर विचार कर सकते हैं और एक निर्णय ले सकते हैं।
- यदि सभी तीन चुने गए संकेतक "गंभीर" श्रेणी में हैं तो यह गंभीर सूखे की मात्रा है और यदि तीन में से दो चुने हुए प्रभाव संकेतक "सामान्य" 'या "गंभीर" श्रेणी में हैं तो यह सामान्य सूखे की मात्रा है।
- तीसरा चरण तब आता है जब दोनों पिछले ट्रिगर निर्धारित हो चुके हों। इस घटना में, "राज्य, सूखे का अंतिम निर्धारण करने के लिए जमीन के लिए नमूना सर्वेक्षण आयोजित करते हैं।"
- क्षेत्र सत्यापन अभ्यास का निर्धारण 'सामान्य' या 'मध्यम' के रूप में सूखे की तीव्रता का निर्धारण करने हेतु अंतिम आधार होगा।
- एक बार सूखा निर्धारित होने के बाद, राज्य सरकार को भौगोलिक सीमा को निर्दिष्ट करती हुई एक अधिसूचना जारी करना आवश्यक होता है।
- अधिसूचना छह महीने के लिए तब तक वैध होती है जब तक कि पुन: अधिसूचित नहीं किया जाता है।

नोट:

- सतत विकास लक्ष्य-15 प्राप्त करने में सूखा एक बड़ी बाधा है।
- एस.डी.जी.-15 स्थलीय पारिस्थितिकी के स्थायी उपयोग की रक्षा, पुनर्स्थापना और संवर्धन स्थायी रूप से वनों, मरूस्थलीकरण निपटान और पड़ाव का प्रबंधन करता है और भूमि पतन और पड़ाव जैव विविधता हानि को रोकता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- पी.आई.बी.

3. <u>**भारत का सबसे ऊँचा वायु यातायात नियंत्रण टॉवर**</u>

- इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत के सबसे लंबे वायु यातायात नियंत्रण टॉवर का उद्घाटन किया गया है।
- यह कुशल, सुचारू और निर्बाध वायु यातायात प्रबंधन के लिए सम्पन्न सेवाओं और प्रणालियों को सुनिश्चित करेगा।

संबंधित जानकारी

उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गईं डिजिटल पहलें

डिजिस्काई

- यह शासन से संबंधित गतिविधियों के संपूर्ण सरगम को विनियमित करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है और रिमोट द्वारा संचालित विमान प्रणाली (आर.पी.ए.एस.)/ मानवरहित विमान वाहन (यू.ए.वी.)/ ड्रोन के संचालन को चालू किया गया है।
- ड्रोन संचालन में सुरक्षा और मजबूती सुनिश्चित करते हुए, यह ड्रोन प्रौद्योगिकियों के संवर्धन में भी मदद करेगा।

डिजियात्रा

- डिजियात्रा पहल को बैंगलोर और हैदराबाद हवाई अड्डों पर एक परीक्षण के आधार पर शुरू किया गया है।
- यह पहल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए बायोमेट्रिक तकनीकों का उपयोग करते हुए सहज और परेशानी मुक्त यात्री यात्रा की परिकल्पना करती है, कतार में प्रतीक्षा समय को कम किया जाएगा क्यों कि यात्री उन्नत सुरक्षा समाधानों का उपयोग करके टहल कर ई-गेट्स के माध्यम से जा सकते हैं।
- यह चौकियों पर अतिरिक्तताओं को कम करेगा और संसाधन उपयोग को बढ़ाएगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

4. **<u>श्रीविल्लिपुत्तर 'पलकोवा' को जी.आई. टैग प्रदान किया जाएगा।</u>**

- प्रसिद्ध श्रीविल्लिपुत्तरपल्कोवा, जो गाय के दूध और चीनी से बनी मिठाई है, इसे चेन्नई में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत (जी.आई.) टैग प्रदान किया जाएगा।
- पल्कोवा का उत्पादन, विरूधुनगर जिले के श्रीविल्लिपुत्तर और उसके आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है।

संबंधित जानकारी

भौगोलिक संकेतक (जी.आई.)

- यह उन उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेतक है, जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उसमें ऐसे गुण या प्रतिष्ठा होती है जो उसके मूल के कारण होती है।
- जी.आई. के रूप में कार्य करने के लिए किसी चिन्ह को किसी दिए गए स्थान पर उत्पन्न होने वाले विशिष्ट उत्पाद की पहचान करनी चाहिए।
- भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के सदस्य के रूप में भौगोलिक उत्पाद संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 को अधिनियमित किया है और यह 15 सितंबर, 2003 से प्रभावी हो गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –कला एवं संस्कृति

स्रोत- द हिंदू

5. **<u>डी.आर.डी.ओ. ने सफलतापूर्वक मानव-पोर्टेबल टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।</u>**

- डी.आर.डी.ओ. ने स्वदेशी रूप से विकसित कम वजन वाली, फॉयर एंड फॉरगेट मानव-पोर्टेबल टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल की तीसरी श्रृंखला का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है।
- मिसाइल को मानव-पोर्टेबल ट्राइपॉड लांचर से लॉन्च किया गया था।

संबंधित जानकारी

मानव-पोर्टेबल टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल

- यह एक भारतीय तीसरी पीढ़ी की फॉयर एंड फॉरगेट टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है।
- यह मिसाइल भारत के नाग ए.टी.जी.एम. से उत्पन्न की गई है।
- वर्तमान में, यह डी.आर.डी.ओ. में भारतीय रक्षा अनुबंधकर्ता वी.ई.एम. प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में है।
- इसमें उच्च-विस्फोटक एंटी-टैंक वारहेड और इसकी परिचालन रेंज- 2.5 कि.मी. है।

- इस मिसाइल में उन्नत हवाई जहाज के साथ-साथ अत्याधुनिक अवरक्त इमेजिंग सीकर को शामिल किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –रक्षा

स्रोत- द हिंदू

6. **<u>यदि एन.सी.एस.टी. योजना को स्वीकार किया जाता है तो लद्दाख को स्वायत्त आदिवासी परिषद मिल सकती है।</u>**

- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान की पांचवीं/ छठी अनुसूची के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को शामिल करने की सिफारिश की है।
- यह लद्दाख क्षेत्र में आदिवासी लोगों की पोषित आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा।
- लद्दाख क्षेत्र में कुल जनजातीय आबादी 97 प्रतिशत से अधिक है।
- इस क्षेत्र बलती, बेदा, बॉट, बोटो, ब्रोक्पा, ड्रोकपा, डार्ड, शिन, चांगपा, गर्रा, मोन, पुरीग्पा नामक आदिवासी जनजातियां बसी हुई हैं।

संबंधित जानकारी

छठी अनुसूची

- अनुच्छेद 244 के अनुसार संविधान की छठी अनुसूची में चार पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान शामिल हैं।
- राज्यपाल को क्षेत्रों को बढ़ाने या घटाने या स्वायत्त जिलों के नाम बदलने का अधिकार प्राप्त है।
- जब कि संघ की कार्यकारी शक्तियों को अनुसूचित क्षेत्रों में पांचवी अनुसूची में उनके प्रशासन के संबंध में विस्तारित किया गया हैं, छठी अनुसूची के क्षेत्र राज्य के कार्यकारी अधिकार के अंतर्गत बने हुए हैं।
- संसद या राज्य विधानसभाओं के अधिनियम स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होते हैं।
- परिषदों को व्यापक नागरिक और आपराधिक न्यायिक शक्तियों के साथ संपन्न किया गया है, उदाहरण: ग्राम न्यायालय आदि की स्थापना करना।
- हालांकि इन परिषदों का क्षेत्राधिकार, संबंधित उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन है।
- संविधान की छठी अनुसूची में 4 राज्यों में 10 स्वायत्त जिला परिषद शामिल हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

- यह आयोग अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और संविधान (89वाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A सम्मिलित करके स्थापित किया गया था।
- यह आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन पूर्णकालिक सदस्य (एक महिला सदस्य सहित) से मिलकर बना है।
- आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले तीन वर्ष तक है।
- इस संशोधन के द्वारा, पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को दो अलग-अलग आयोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था-

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एन.सी.एस.सी.) और
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.), जो कि 19 फरवरी, 2004 से प्रभावी है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

7. **<u>संभावित रूप से रहने योग्य सुपर-पृथ्वी पर पानी की खोजा गया है!</u>**

- संभावित रूप से रहने योग्य सुपर-पृथ्वी "K2-18b" के वायुमंडल में वैज्ञानिकों द्वारा पानी का पता लगाया गया है।
- इस एक्सोप्लैनेट का नाम K2-18b है, यह पृथ्वी के आकार का दोगुना और द्रव्यमान का आठ गुना है।
- K2-18b, एक दूरस्थ सुपर-पृथ्वी है और पहली बार इसके वायुमंडल और तापमान में जल वाष्प की खोज की गई है, जो संभावित रूप से जीवन का समर्थन करता है।

K2-18b

- एक्सोप्लेनेट, पृथ्वी के आकार का दोगुना और द्रव्यमान का आठ गुना है और इसलिए इसे सुपर-पृथ्वी के रूप में जाना जाता है।
- सुपर-पृथ्वी, एक्सोप्लैनेट है जो पृथ्वी से बड़ी हैं लेकिन नेपच्यून से छोटी हैं।
- एक्सोप्लैनेट, एक लाल बौने तारे, K2-18 की परिक्रमा करता है और पृथ्वी से 110 प्रकाश-वर्ष दूर है, जो सिंह तारमंडल में है।
- अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि K2-18b अपने तारे से उतना ही विकिरण प्राप्त करता है जितना पृथ्वी, सूर्य से प्राप्त करती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत-द हिंदू

8. **<u>क्रायोड्रैकॉनबोरीस, सबसे बड़ा उड़ने वाला जानवर, एक विमान के आकार का सरीसृप था।</u>**

- हाल ही में, पैलिओंटोलॉजिस्ट ने एक नई प्रजाति की पहचान की है, जिसका नाम क्रायोड्राकॉनबोरिया है जो सबसे बड़े उड़ने वाले जानवरों में से एक हो सकता है।

संबंधित जानकारी

क्रायोड्राकॉन बोरियास

- क्रायोड्राकॉन को कोल्ड ड्रैगन के रूप में भी जाना जाता है जो 77 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रेटेशियस अवधि के दौरान रहता था, जो अब कनाडा है।
- इसमें एक एकल प्रजाति, क्रायोड्राकोनेबोरस शामिल है, जो डायनासोर पार्क संरचना (अल्बर्टा, कनाडा में) से बरामद की गई है।
- इसके पंखों की चौड़ाई 10 मीटर से अधिक है, ऐसा माना जाता है कि यह डायनासोर के सिर के ऊपर से उड़ता था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –कला एवं संस्कृति

स्रोत- द हिंदू

13.09.2019

1. **<u>वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान एवं विकास केंद्र</u>**

- हाल ही में, भारत एक नए सदस्य के रूप में वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध (ए.एम.आर.) अनुसंधान एवं विकास केंद्र (आर. एंड डी.) में शामिल हुआ है।

संबंधित जानकारी

वैश्विक ए.एम.आर. आर. एंड डी. केंद्र

- इसे वर्ष 2017 में जी20 नेतृत्वकर्ताओं के आवाह्न के बाद मई, 2018 में विश्व स्वास्थ्य असेंबली के 71वें सत्र के हाशिए पर लॉन्च किया गया था।
- यह 16 देशों, यूरोपीय आयोग, दो परोपकारी फाउंडेशन और चार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (पर्यवेक्षकों के रूप में) की वैश्विक साझेदारी है।
- वैश्विक ए.एम.आर. आर. एंड डी. केंद्र, ए.एम.आर आर. एंड डी. में लाभ और क्रॉस क्षेत्रीय सहयोग हेतु अंतरों, ओवरलैप और संभावनाओं की पहचान के माध्यम से ए.एम.आर आर. एंड डी. के लिए संसाधनों के आवंटन पर वैश्विक प्राथमिकता सेटिंग और साक्ष्य-आधारित निर्णय निर्माण का समर्थन करता है।
- इसका सचिवालय, बर्लिन में स्थापित है।

- इसे जर्मन संघीय शिक्षा एवं अनुसंधान (बी.एम.बी.एफ.) मंत्रालय और संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय (बी.एम.जी.) से अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है।

नोट:

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध, दवा के प्रभावों का प्रतिरोध करने के लिए एक सूक्ष्मजीव की क्षमता है जो एक बार सफलतापूर्वक सूक्ष्मजीव का इलाज कर सकता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

2. **<u>भारत ने चीन में यूरेशियाई आर्थिक मंच को छोड़ दिया है।</u>**

- भारत ने 'यूरेशियाई आर्थिक संघ' (ई.ए.ई.यू.) की बैठक को छोड़ दिया है, जिसे चीन में एस.सी.ओ. द्वारा आयोजित किया गया था।
- भारत वर्ष 2017 से शंघाई सहयोग संगठन (एस.सी.ओ.) का सदस्य रहा है।

छोड़ने के कारण

- यूरेशियाई आर्थिक मंच का पूरा कार्यक्रम पहले से चीन के 'क्षेत्र एवं सड़क पहल' द्वारा सूचित था।
- क्षेत्र एवं सड़क पहल, चीन द्वारा अनावरण की गई एक बुनियादी ढांचा परियोजना है जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने की योजना बना रही है।
- 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा', बी.आर.आई. का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पाक अधिकृत कश्मीर (पी.ओ.के.) से होकर गुजरता है।
- इसलिए, भारत ने बी.आर.आई. का कड़ा विरोध किया है, क्यों कि कोई भी देश एक ऐसी परियोजना को स्वीकार नहीं कर सकता है जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर उसकी मूल चिंताओं की अनदेखी करती है।
- इस कारण भारत ने एस.सी.ओ. के यूरेशियाई आर्थिक मंच को छोड़ दिया था क्यों कि पूरा कार्यक्रम बी.आर.आई. द्वारा पहले से सूचित है।

संबंधित जानकारी

यूरेशियाई आर्थिक संघ

- यह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन है, यह 1 जनवरी, 2015 को अस्तित्व में आया था।
- यूरेशियाई आर्थिक संघ के सदस्य राज्य हैं:
  1. आर्मेनिया गणराज्य
  2. बेलारूस गणराज्य
  3. कजाखस्तान गणराज्य
  4. किर्गिज़ गणराज्य
  5. रूसी संघ

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –अंतर्राष्ट्रीय संगठन

स्रोत- लाइवमिंट

3. **<u>मैत्री 2019: भारत-थाईलैंड संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास</u>**

- भारत और थाईलैंड का मेघालय में एक संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास मैत्री-2019 आयोजित किया जाएगा।

संबंधित जानकारी

मैत्री युद्धाभ्यास

- यह एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो वर्ष 2006 से थाईलैंड और भारत में एकांतर रूप से आयोजित किया जा रहा है।
- वैश्विक आतंकवाद के बदलते पहलुओं की पृष्ठभूमि में दोनों राष्ट्रों के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में यह युद्धाभ्यास महत्वपूर्ण है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –रक्षा

स्रोत- पी.आई.बी.

4. **<u>हिम विजय युद्धाभ्यास</u>**

- भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश और असम में अपने नवगठित एकीकृत युद्ध समूहों (आई.बी.जी.) के साथ हिम विजय नामक एक प्रमुख युद्धाभ्यास आयोजित करना निर्धारित किया है।
- भारतीय सेना, इस युद्धाभ्यास में एकीकृत युद्ध समूहों के साथ शामिल होगी।
- भारतीय वायु सेना भी कर्मियों और उपकरणों के रणनीतिक एयरलिफ्ट हेतु इस युद्धाभ्यास का हिस्सा होगी।
- इस प्रकार के युद्धाभ्यास का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य इसका परीक्षण करना है कि पूर्वी कमान के अंतर्गत आने वाली माउंटेन स्ट्राइक सैन्य दल विभिन्न इलाकों में ऑपरेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।

माउंटेन स्ट्राइक सैन्य दल

- माउंटेन स्ट्राइक सैन्य दल, पहाड़ों में ऑपरेशन करने हेतु भारत की पहली समर्पित स्ट्राइक कोर है।
- यह भारत की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विवादास्पद सीमा के पूर्वी छोर पर केंद्रित है।
- उनका उपयोग किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में किया जा सकता है जिसका अर्थ है सभी उत्तरी सीमाओं में इनका प्रयोग किया जा सकता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –रक्षा

स्रोत- पी.आई.बी.

5. **<u>इस वर्ष के अंत तक राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड का संचालन किया जाएगा?</u>**

- राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (नैटग्रिड) परियोजना, सोशल मीडिया अकाउंट्स को रिकॉर्डों के विशाल डेटाबेस से लिंक करती है, जो आव्रजन प्रविष्टि और निकास, बैंकिंग और टेलीफोन विवरण से संबंधित है।
- नैटग्रिड के पास स्वयं का डेटाबेस नहीं होगा बल्कि इसमें सॉफ्टवेयर से जुड़ा एक संयुक्त डेटाबेस होगा।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (नैटग्रिड)

- यह एक केंद्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य एक एकीकृत खुफिया ग्रिड है जो भारत सरकार के कई विभागों और मंत्रालयों के डेटाबेस को जोड़ेगा।
- यह आतंकवादियों की पहचान करने, पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने में मदद करता है और पूर्व-कार्रवाई आतंकी भूखंडों की मदद करेगा।
- यह 22 सरकारी संस्थाओं के बीच खुफिया जानकारी साझा करने और प्रसारित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा, यह सरकारी संस्थाएं निमन हैं:
- इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (R & AW), केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), वित्तीय खुफिया इकाई (FIU), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI), प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.), नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (NCB), केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क खुफिया महानिदेशालय (DGCEI) हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –रक्षा

स्रोत- द हिंदू

6. **<u>आर.बी.आई. पैनल ने एन.एच.बी. के अंतर्गत नए मध्यस्थ का सुझाव दिया है।</u>**

- आर.बी.आई. पैनल, जिसे हाउसिंग फाइनेंस प्रतिभूतिकरण की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने और बाजार को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए उपाय सुझाने का काम सौंपा गया था, इस पैनल ने सिफारिश की है कि राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक (एन.एच.बी.) के अंतर्गत एक मध्यस्थ स्थापित किया जाएगा, जिसमें सरकार का 51% स्वामित्व होगा।
- हर्षवर्धन की अध्यक्षता में मई, 2019 में स्थापित की गई 6 सदस्यीय समिति ने अपनी आर.बी.आई. को अपनी रिपोर्ट सौंपी है।

- बंधक प्रतिभूतिकरण में ऋणों की पूलिंग और उन्हें एक विशेष उद्देश्य वाहन (एस.पी.वी.) को बेचना शामिल है, जो तब प्रतिभूतियों को जारी करता है, जिसे निकासी प्रमाण पत्र (पी.टी.सी.) कहा जाता है।
- पी.टी.सी. को ऋण पूल द्वारा समर्थित किया जाएगा।
- प्रतिभूतिकरण, ऋणदाताओं की बैलेंस शीट पर अनकदी ऋणों को व्यापार योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने हेतु एक तंत्र है।
- समिति ने यह भी कहा है कि आर.बी.आई. को ऋण उत्पत्ति, ऋण सेवा, ऋण प्रलेखन और प्रतिभूतिकरण के लिए पात्र ऋणों के लिए मानक विकसित करना चाहिए, जिसमें डेटा संग्रह और एकत्रीकरण के लिए मानकीकृत प्रारूप शामिल हैं।
- इसने प्रत्यक्ष असाइनमेंट हस्तांतरण और पी.टी.सी. से संबंधित हस्तांतरण हेतु विनियामक दिशानिर्देशों के साथ-साथ बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों और परिसंपत्ति-समर्थित प्रतिभूतियों के लिए भी अलग-अलग दिशानिर्देश सुझाए हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3- भारतीय अर्थव्यवस्था

स्रोत- लाइवमिंट

7. **<u>हरियाणा के मुख्यमंत्री ने छोटे व्यापारियों के लिए बीमा योजनाओं की शुरुआत की है।</u>**

- हरियाणा के मुख्यमंत्री, मनोहर लाल ने राज्य में पंजीकृत छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए दो बीमा योजनाएं शुरू कीं हैं, जिनके नाम **मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजि दुर्घटना बीमा योजना** और **मुख्यमंत्री व्यापारिक क्षतिपूर्ति बीमा योजना** हैं।
- मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजि दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा और मुख्यमंत्री व्यापारिक क्षतिपूर्ति बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- हरियाणा उत्पाद एवं सेवा कर (एच.जी.एस.टी.) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारियों को इन योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- सरकारी योजनाएं

स्रोत- इकानॉमिक टाइम्स

8. **<u>देश में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एम.आई.सी. और ए.आई.सी.टी.ई. की पहलें</u>**

- केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने देश में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एम.आई.सी. और ए.आई.सी.टी.ई. की कई पहलें लांच की हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा शुरू की गई पहलों का विवरण

आई.आई.सी. 2.0 का शुभारंभ

- इस नवाचार इकाई ने शिक्षा में नवाचार और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों में संस्थानों की नवाचार परिषद (आई.आई.सी.) के एक मजबूत नेटवर्क की स्थापना करने की कल्पना की है।

स्मार्ट इंडिया हैकथॉन -2020:

- स्मार्ट इंडिया हैकथॉन या एस.आई.एच., एम.एच.आर.डी. की नवाचार इकाई (एम.आई.सी.) और ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम और राष्ट्रव्यापी पहल है।
- यह छात्रों को हमारे दैनिक जीवन में आने वाली कुछ समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है और इस प्रकार उत्पाद नवाचार की संस्कृति को विकसित करने और समस्याओं को हल करने की मानसिकता का निर्माण करता है।

65TH BPSC
TEST SERIES 2019
CHECK HERE

- हैकथॉन (एस.आई.एच.), एम.एच.आर.डी. की नवाचार इकाई के सबसे सफल मुख्य कार्यक्रमों में से एक है।

ए.आर.आई.आई.ए. 2020

- अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट (ARIIA), एच.आर.डी. मंत्रालय की एक पहल है।
- यह सुव्यवस्थित रूप से अपने छात्रों और संकायों के मध्य "नवाचार एवं उद्यमिता विकास" के संवर्धन से संबंधित संकेतकों के आधार पर सभी प्रमुख शैक्षिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान करता है।

प्रोत्साहन मुद्रा योजना

- प्रोत्साहन मुद्रा, छात्रों और शिक्षकों को प्रतिदिन या पुरस्कार के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली कार्रवाई के लिए पुरस्कार प्रदान करने हेतु रियल टाइम पुरस्कार इंजन है।

ए.आई.सी.टी.ई. – विश्वकर्मा पुरस्कार 2019

- युवा छात्रों और संस्थानों को अपने विशिष्ट डोमेन में अपने प्रदर्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करने हेतु ए.आई.सी.टी.ई. ने वर्ष 2017 से विश्वकर्मा पुरस्कार की शुरुआत की थी।
- विश्वकर्मा पुरस्कार 2019 की थीम "गाँव की आय कैसे बढ़ाएं" है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2–गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

16.09.2019

1. **<u>न्यायमूर्ति पी. लक्ष्मण रेड्डी को आंध्र प्रदेश के पहले लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।</u>**

- वर्ष 2014 में प्रदेश के विभाजन के बाद पूर्व आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. लक्ष्मण रेड्डी ने राज्य के पहले लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है।

<u>संबंधित जानकारी</u>

<u>लोकपाल और लोकायुक्त के संदर्भ में जानकारी</u>

- लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ने संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना हेतु प्रावधान प्रदान किए हैं।
- ये संस्थान बिना किसी संवैधानिक दर्जे के संवैधानिक निकाय हैं।
- वे एक "लोकपाल" का कार्य करते हैं और कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों और संबंधित मामलों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं।
- वर्ष 1971 में लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम के माध्यम से लोकायुक्त की संस्था शुरू करने वाला पहला राज्य, महाराष्ट्र था।

नियुक्ति

- लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त, राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
- जब कि नियुक्त करते समय अधिकांश राज्यों में राज्यपाल निम्न से परामर्श करते हैं:
- राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
- राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता

नोट:

- पिनाकी चंद्र घोष, भारत के पहले लोकपाल हैं, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

2. **<u>केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर पोर्टल</u>**

- हाल ही में, दूरसंचार मंत्री ने एक पोर्टल का अनावरण किया है जहां एक उपयोगकर्ता फोन खो जाने या चोरी हो जाने की शिकायत दर्ज कर सकता है।
- यह परियोजना महाराष्ट्र में परीक्षण आधार पर शुरू की गई है और बाद में इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।

- इसका उद्देश्य आई.एम.ई.आई. नंबर को ब्लॉक करके खोए/ चोरी हुए फोन के पुनर्विक्रय को कम करना है।

केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर के संदर्भ में जानकारी:

- यह अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (आई.एम.ई.आई.) का एक डेटाबेस है, जो 15 एक अंकीय संख्या है, जो प्रत्येक मोबाइल डिवाइस की विशिष्ट पहचान करती है।
- केंद्रीय पहचान रजिस्टर की अवधारणा की जी.एस.एम. संघ (जी.एस.एम.ए.) द्वारा वकालत की जाती है।
- दूरसंचार पहचान रजिस्टर विभाग, आई.एम.ई.आई. नंबरों का एक डेटाबेस होगा जिसमें तीन सूचियाँ- व्हाइट, ग्रे और ब्लैक शामिल होंगी।
- व्हाइट लिस्ट में शामिल आई.एम.ई.आई. नंबर वाले मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति होगी।
- ब्लैकलिस्ट में वे नंबर शामिल होंगे जिनके खोने अथवा चोरी होने की सूचना दर्ज कराई गई है, उन्हें नेटवर्क एक्सेस की अनुमति नहीं प्राप्त होगी।
- ग्रे लिस्ट में वे नंबर शामिल होंगे जिन्होंने मानकों की पुष्टि नहीं की है लेकिन निगरानी के अंतर्गत उन्हें कनेक्ट कराने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

3. **<u>सी.ओ.पी.14: भूमि पतन का मुकाबला करने हेतु दिल्ली घोषणापत्र को अपनाया गया है।</u>**

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र मरूस्थलीकरण निपटान सम्मेलन का पार्टियों का सम्मेलन 14 (सी.ओ.पी. 14) भारत के ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुआ है।
- यह वर्ष 2030 तक भूमि पतन उदासीनता (एल.डी.एन.) और दिल्ली घोषणापत्र को अपनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के साथ समाप्त हुआ है।
- दिल्ली घोषणापत्र, भूमि पतन उदासीनता (एल.डी.एन.) को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, इस पर प्रत्येक देश द्वारा की जाने वाली वैश्विक कार्रवाई का एक विवरण है।
- सम्मेलन के समापन पर भूमि बहाली के प्रति व्यक्तियों के पहले दृष्टिकोण के साथ उठाए गए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ 12 सूत्रीय दिल्ली घोषणापत्र पत्र पर पार्टियों द्वारा सहमति जताई गई है।

दिल्ली घोषणापत्र सी.ओ.पी. 14 (महत्वपूर्ण बिंदु)

- स्थानीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर भूमि क्षरण को रोकने के लिए परियोजनाओं को बढ़ावा देना
- सूखे और क्षरण को रोकने और बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने हेतु परियोजनाओं को बढ़ावा देना
- सूखे को रोकने की योजना बनाना जिससे कि भूमि क्षरण को रोका जा सके
- सभी हितधारकों के साथ मिलकर प्रौद्योगिकी और निवेश को बढ़ावा देकर हरित रोजगार का सृजन करना
- पेरिस समझौते को आगे बढ़ाते हुए भूमि क्षरण को रोकने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है
- सभी देशों की ओर से संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र बहाली (2021-2030) कार्यक्रम को लागू करना
- अफ्रीकी देशों द्वारा भूमि क्षरण को रोकने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –पर्यावरण

स्रोत- ए.आई.आर.

4. **<u>बांस विज्ञान: आदिवासी उद्यम को बढ़ावा देने हेतु सबसे बड़ा जनजातीय आंदोलन</u>**

- हाल ही में, ट्राइफेड और केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने टी.आई.सी.डी. (मरूस्थलीकरण से निपटने हेतु ट्राइफेड की पहल) को "द 4पी.1000 पहल: बांस विज्ञान के माध्यम से जपजातीय परिप्रेक्ष्य" के अंतर्गत लॉन्च किया गया है।
- बांस विज्ञान, मरूस्थलीकरण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने हेतु एक अभियान है जिसमें भारत के आदिवासी समुदाय को शामिल किया जाएगा क्यों कि वे क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं।

संबंधित जानकारी

4पी.1000 के संदर्भ में जानकारी

- ट्राइफेड के अनुसार, बांस विज्ञान के माध्यम से आदिवासी परिप्रेक्ष्य के साथ 4पी.1000 पहल, मरुस्थलीकरण और क्षरण हो चुकी बंजर भूमि के पुनर्वास हेतु सबसे अच्छा समाधान है।
- 4पी.1000 पहल: अंतर्राष्ट्रीय पहल "प्रति 1000 पर 4", सी.ओ.पी. 21 में फ्रांस द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई थी।
- इसमें लीमा-पेरिस कार्रवाही योजना (एल.पी.ए.पी.) के ढांचे के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सभी स्वैच्छिक हितधारकों को सम्मिलित किया जाता है।
- पहल का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि प्रारंभिक 30-40 से.मी. कृषि मिट्टी में मिट्टी कार्बन भंडारण में 0.4% की वार्षिक वृद्धि दर होनी चाहिए, जो वायुमंडल में मानव गतिविधियों से संबंधित कार्बन डाई ऑक्साइड की सांद्रता को कम महत्वपूर्ण रूप से कम करेगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –पर्यावरण

स्रोत- डी.डी. न्यूज

5. **<u>केंद्र ने 312 सिख विदेशी नागरिकों को प्रतिकूल सूची से हटा दिया है।</u>**

- सरकार ने सिख समुदाय से संबंधित 314 विदेशी नागरिकों की प्रतिकूल सूची की समीक्षा की है और नागरिकों की संख्या घटाकर केवल दो कर दी है।
- केंद्रीय "प्रतिकूल सूची" को गृह मंत्रालय द्वारा विनियमित किया जाता है।
- यह निर्णय, सिक्ख विदेशी नागरिकों के नाम रखने वाली प्रतिकूल सूची अथवा ब्लैक लिस्ट की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई समीक्षा के बाद लिया गया है।

संबंधित जानकारी

प्रतिकूल सूची या ब्लैक लिस्ट के संदर्भ में जानकारी

- विभिन्न देशों और विदेशों में भारतीय दूतावासों द्वारा ब्लैकलिस्ट का विनियमन किया जाता है।
- इसमें भारतीय मूल के लोगों की सूची शामिल है, जिन्हें शरण में रखा गया है अर्थात भारत में कथित उत्पीड़न की दलील के अंतर्गत विदेशों में इसे दूसरे देश में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का अधिकार दिया गया है।
- जो लोग इस सूची में हैं, उन्हें संबंधित देश में भारतीय मिशनों और पदों द्वारा वीजा सेवाओं से वंचित किया जाता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

6. **<u>राजस्थान ने एक सूचना पोर्टल लॉन्च किया है।</u>**

- राजस्थान सरकार ने एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम जन सूचना पोर्टल-2019 रखा है।
- यह आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 4(2) के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा जिससे सार्वजनिक अधिकारियों को सार्वजनिक डोमेन में जानकारी का खुलासा करने के लिए बाध्य किया जा सके।

- यह पोर्टल सरकारी अधिकारियों और विभागों के बारे में जानकारी देने का वादा करता है जो सूचना का अधिकार अधिनियम की सही भावना में जनता की स्व: प्रेरणा है।
- यह प्रारंभ में 13 विभागों से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा।

नोट:

- सूचना के अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम की धारा 4 सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण से संबंधित है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

7. **<u>केरल, महिलाओं के लिए भारत के पहले व्यापारिक केंद्र की स्थापना करने जा रहा है।</u>**

- केरल, कोझिकोड में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) के अनुरूप भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापारिक केंद्र (आई.डब्ल्यू.टी.सी.) को स्थापित करेगा।
- यह सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत राज्य के जेंडर पार्क की एक महत्वपूर्ण परियोजना है।
- आई.डब्ल्यू.टी.सी. का पहला चरण जेंडर पार्क के "विज़न 2020" के अंतर्गत निष्पादित किया जा रहा है, इसे वर्ष 2021 तक पूरा किया जाना निर्धारित किया गया है।
- व्यापारिक केंद्र का उद्देश्य महिला उद्यमिता को गति प्रदान करना और लैंगिक समानता को संरक्षित करना होगा।
- यह सुविधा महिलाओं को नए व्यवसाय शुरू करने, स्थापित करने या विस्तार करने और वैश्विक स्तर पर अपने उत्पादों को प्राप्त करने के लिए घर से दूर एक सुरक्षित स्थान प्रदान करेगी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

8. **<u>पैंगोंग त्सो झील</u>**

- हाल ही में, पैंगोंग त्सो झील के पास लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के ऊष्मा का विनिमय हुआ है।

संबंधित जानकारी

पैंगोंग त्सो के संदर्भ में जानकारी

- पैंगोंग त्सो, लद्दाख हिमालय में 14,000 फुट से अधिक की ऊँचाई पर स्थित एक लंबी संकरी, गहरी, एंडोरेहिक (स्थलसीमा) झील है।
- झील भारत से चीन तक फैली हुई है।
- एक तिहाई जल निकाय, इसका 45 कि.मी. का हिस्सा भारतीय नियंत्रण में है, जब कि शेष 90 कि.मी; का हिस्सा चीनी नियंत्रण में है।
- यह एक खारे पानी की झील है जो टेथिस जियोसिंक्लाइन से बनी थी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –भूगोल

स्रोत- लाइवमिंट

9. **<u>समुद्र लक्ष्मण 2018</u>**

- यह भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के मध्य एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है।

संबंधित जानकारी

समुद्र लक्षमण युद्धाभ्यास के संदर्भ में जानकारी

- युद्धाभ्यास में एक बंदरगाह चरण शामिल होगा जिसमें पेशेवर संवाद, आधिकारिक कॉल, सामाजिक व्यस्तता, स्थानीय आबादी द्वारा यात्राएं और विभिन्न खेल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- युद्धाभ्यास का सागर चरण दोनों नौसेनाओं को अपने कौशल को और बेहतर बनाने में सक्षम बनाएगा जिससे कि सभी के लिए शांतिपूर्ण और सुरक्षित समुद्र सुनिश्चित करने के लिए नौसेनाओं के बीच अंतर-क्षमता को बढ़ाया जा सके।

मलेशिया के साथ अन्य युद्धाभ्यास

हरिमऊ शक्ति

- यह भारतीय और मलेशियाई सेनाओं के मध्य एक सैन्य युद्धाभ्यास है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 – रक्षा

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

10. **<u>अमेरिका में एम.डी.एच. मसालों को परीक्षण में साल्मोनेला जीवाणु के प्रति सकारात्मक पाया गया है।</u>**

- हाल ही में संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने एम.डी.एच. सांबर मसाले का परीक्षण किया है जो साल्मोनेला के लिए सकारात्मक पाया गया है।

संबंधित जानकारी

साल्मोनेला के संदर्भ में जानकारी

- यह जीवाणुओं का एक समूह है जिससे खाद्य-जनित बीमारी हो सकती है जिसे सालमोनेलोसिस के रूप में जाना जाता है।
- दूषित पानी या भोजन से मनुष्य सबसे अधिक बार संक्रमित होता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने साल्मोनेला को डायरिया रोगों के चार प्रमुख वैश्विक कारणों में से एक माना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत- इंडिया टुडे

17.09.2019

1. **<u>पहला मेडेन आई.एन.-आर.एस.एन.-आर.टी.एन. त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास</u>**

- पहले त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास में रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी (आर.एस.एन.), रॉयल थाईलैंड नेवी (आर.टी.एन.) और भारतीय नौसेना (आई.एन.) शामिल हैं, इस युद्धाभ्यास का आयोजन पोर्ट ब्लेयर में शुरू किया गया है।
- इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य सिंगापुर, थाईलैंड और भारत के मध्य समुद्री संबंधों को मजबूत करना है।
- इस युद्धाभ्यास ने इस क्षेत्र में समग्र समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- पहला मेडेन आई.एन.-आर.एस.एन.-आर.टी.एन. त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास, भाग लेने वाली नौसेनाओं को संबंधों को पोषित करके मजबूत करने हेतु सहयोग की भावना से मिलकर एक साथ आने का अवसर प्रदान करेगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –रक्षा

स्रोत- पी.आई.बी.

2. **<u>करण वंदना: एक नई हाइब्रिड गेहूं किस्म</u>**

- करण वंदना, गेहूं की एक नई हाइब्रिड किस्म है जो सामान्य किस्मों की तुलना में काफी अधिक उपज देती है, शीघ्र ही पूरे देश में इसके लॉन्च होने की संभावना है।

संबंधित जानकारी

करण वंदना

- इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के अंतर्गत भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान (आई.आई.डब्ल्यू.बी.आर.) द्वारा विकसित किया गया है।
- इसे डी.बी.डब्ल्यू.-187 के रूप में भी जाना जाता है जो पीली जंग (येलो रस्ट) और व्हाइट ब्लास्ट रोगों के प्रति प्रतिरोधी हैं।

पीली जंग (येलो रस्ट)

- येलो रस्ट, एक कवक रोग है जो पत्तियों पर पाउडर के रूप में पीली धारियों के रूप में दिखाई देती है।
- ये पीली धारियाँ प्रकाश संश्लेषण में बाधा डालती हैं और पौधे की वृद्धि को रोकती हैं।
- पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर के निचले इलाकों जैसे गेहूं उगाने वाले सभी राज्य इस बीमारी के प्रति अतिसंवेदनशील हैं।

व्हाइट ब्लास्ट

- यह भी एक कवक रोग है।
- यह वास्तविक अनाज की परिपक्वता को रोकता है जो प्रजनन को प्रभावित करता है जिससे मेजबान कम बीज पैदा करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 – कृषि

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

3. **अमराबाद टाइगर रिजर्व के जंगल में अब कोई यूरेनियम खनन नहीं**

- तेलंगाना राज्य विधानसभा ने राज्य के नल्लामाला वन क्षेत्र में स्थित अमराबाद टाइगर रिजर्व में प्रस्तावित यूरेनियम खनन के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था।

संबंधित जानकारी

- 22 मई, 2019 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अमराबाद टाइगर रिजर्व के 83 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में यूरेनियम का सर्वेक्षण और अन्वेषण करने हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की थी।
- चेंचू जनजाति, जो तेलंगाना के महबूबनगर और नलगोंडा जिले में फैले अमराबाद के जंगलों में रहते हैं, वे भी इस यूरेनियम अन्वेषण से प्रभावित हुए हैं।

अमराबाद टाइगर रिजर्व

- यह महबूबनगर और नलगोंडा जिलों में 2,800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, यह देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है।
- इसके पहले, यह नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का हिस्सा था लेकिन विभाजन के बाद, रिजर्व के उत्तरी भाग को तेलंगाना राज्य में निहित किया गया था और इसका नाम बदलकर अमराबाद टाइगर रिजर्व रख दिया गया था।

भारत की स्थिति

- आंध्र प्रदेश राज्य, भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है।
- आंध्र प्रदेश के कडापा जिले में स्थित तुम्मालापल्ले गांव को दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार के रूप में माना जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

4. **प्रकाश जावड़ेकर ने 'जलदूत' जल संरक्षण पहल को हरी झंडी दिखाई है।**

- केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुणे, महाराष्ट्र में जल संरक्षण के संदेश को फैलाने हेतु 'जलदूत' नामक एक वाहन को हरी झंडी दिखाई है।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पुणे स्थित क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो द्वारा आयोजित एक यात्रा प्रदर्शनी अगले दो महीनों में महाराष्ट्र के आठ जिलों का दौरा करेगी।
- यह लोगो तक जल संरक्षण का संदेश पहुँचाएगी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –सरकारी नीतियां

स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

5. **सरकार ने इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एस.आई.एम.एस.) की शुरूआत की है।**

- सरकार ने प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप के लिए उत्पादकों और आयातकों सहित विभिन्न हितधारकों को स्टील आयात के बारे में अग्रिम जानकारी प्रदान करने हेतु एक इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एस.आई.एम.एस.) की शुरूआत की है।
- यह प्रणाली अमेरिकी इस्पात आयात निगरानी एवं विश्लेषण प्रणाली (एस.आई.एम.ए.) के प्रारूप पर इस्पात मंत्रालय के साथ परामर्श करके विकसित की गई है।
- निर्दिष्ट इस्पात उत्पादों के आयातक आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाले एस.आई.एम.एस. के वेब पोर्टल पर अग्रिम रूप से पंजीकरण करेंगे।

- आयातक, आयात खेप के आगमन की अपेक्षित तिथि के 60वें दिन से पहले और 15वें दिन के बाद पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- प्रदान की गई स्वचालित पंजीकरण संख्या 75 दिनों के लिए वैध रहेगी।
- एस.आई.एम.एस. पर आयातकों द्वारा प्रदान की जाने वाली इस्पात आयात की जानकारी की निगरानी इस्पात मंत्रालय द्वारा की जाएगी।
- एस.आई.एम.एस. को निर्धारित पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके स्वचालित पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए आयातकों को 8-अंकीय एच.एस. कोड में 284 इस्पात शुल्क पंक्तियों के आयात हेतु एक ऑनलाइन प्रणाली में अग्रिम सूचना प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 – सरकारी नीतियां

स्रोत- लाइवमिंट

6. **ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रहा है।**

- देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे से दूर स्थापित किया जाएगा।
- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जी.एन.आई.डी.ए.) ने पुष्टि की कि केंद्र को 372 करोड़ रुपये की लागत से भूमि आवंटित की गई थी।
- यह विश्वविद्यालय शासन, आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराध और फोरेंसिक विज्ञान पर स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा।
- देश में अभी तक पुलिस हेतु एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है हालांकि राजस्थान, गुजरात और झारखंड जैसे राज्यों में समर्पित पुलिस विश्वविद्यालय हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 – सरकारी नीतियां

स्रोत- टाइम्स ऑफ इंडिया

7. **राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान एवं विकास केंद्र खोला गया है।**

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान (आई.आई.एससी.) में राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान एवं विकास केंद्र का उद्घाटन किया है।
- आई.आई.एससी. के नेतृत्व में केंद्र को स्वच्छ कोयला अनुसंधान एवं विकास पर एक राष्ट्रीय संघ के रूप में स्थापित किया गया है।
- नए केंद्र का उद्देश्य कई महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास की चुनौतियों का सामना करना है, जो सामग्री और प्रणाली दोनो के स्तर पर सुपरक्रिटिकल ऊर्जा संयंत्र प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों के विकास की दिशा में है।
- मंत्री ने कुलीन शोधकर्ताओं के ज्ञान नेटवर्क के माध्यम से ऊर्जा अनुसंधान के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम का संचालन करने हेतु आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अंत:विषय ऊर्जा अनुसंधान केंद्र (आई.सी.ई.आर.) का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया है।
- ऊर्जा की मांग को संबोधित करते हुए मानवजनित उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों का विकास आवश्यक है।
- इन लक्ष्यों को उच्च दक्षता वाले उन्नत अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल भाप ऊर्जा संयंत्र के साथ-साथ सुपरक्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड संयंत्र की ओर स्थानांतरण के साथ-साथ नई दहन और गैसीकरण प्रौद्योगिकियों की खोज के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 – विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत- डाउन टू अर्थ

8. **जम्मू एवं कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम**

- नेशनल कांफ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत हिरासत में लिया गया है।

संबंधित जानकारी

जम्मू एवं कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम

- जम्मू एवं कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पी.एस.ए.) को 8 अप्रैल, 1978 को जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल की स्वीकृति मिल गई थी।
- इसे "ड्रैकोनियन (सख्त)" कानून के रूप में भी जाना जाता है।
- यह कानून सरकार को 16 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए "राज्य की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के मामले में" गिरफ्तार करने की अनुमति प्रदान करता है।
- अगस्त, 2018 में राज्य के बाहर भी पी.एस.ए. के अंतर्गत व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति देने हेतु अधिनियम में संशोधन किया गया था।
- इस अधिनियम के अंतर्गत हिरासत आदेश संभागीय आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए जा सकते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

9. **<u>यांक (Yank') ': जैवभौतिकी में एक नया शब्द है।</u>**

- जीवविज्ञानी और जैवचिकित्सक इंजीनियरों ने यांक (Yank) शब्द को समय के साथ बलों में परिवर्तन के रूप में परिभाषित करने का प्रस्ताव रखा है।
- समय के साथ बलों में बदलाव के लिए प्रस्तावित नया शब्द इस प्रकार है कि वैज्ञानिक मांसपेशियों के व्यवहार का बेहतर अध्ययन कर सकें।
- इसका उद्देश्य उस चीज की मात्रा निर्धारित करना है जो हमारी मांसपेशियों और तंत्रिकाएं महसूस कर सकती हैं और उसके प्रति प्रतिक्रिया दे सकती हैं।
- यह स्पस्टिसिटी को समझने में मददगार हो सकता है, जो मल्टीपल स्केलेरोसिस, रीढ़ की हड्डी में चोट, स्ट्रोक और मस्तिष्क पक्षाघात में एक सामान्य मांसपेशीय हानि होती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीकी

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

18.09.2019

1. **<u>निर्विक योजना: नई निर्यात ऋण बीमा योजना</u>**

- निर्यात ऋण गारंटी निगम (ई.सी.जी.सी.) के माध्यम से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक नई निर्यात ऋण बीमा योजना (ई.सी.आई.एस.) शुरू की है, जिसे निर्विक कहा जाता है।

निर्विक

- बढ़ा हुआ बीमा कवर यह सुनिश्चित करेगा कि निर्यातकों के लिए विदेशी और रुपया निर्यात ऋण की ब्याज दर क्रमशः 4% और 8% से नीचे रहेगी।
- यह विशेष रूप से एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को पूंजी और जोखिम अनुकूलन के कारण इष्टतम मूल्य के साथ निर्यात ऋण उधार की मात्रा को बढ़ाने हेतु बैंकों को उत्प्रेरित करेगा।
- इस बीमा कवर में प्री और पोस्ट-शिपमेंट ऋण दोनों शामिल होंगे।
- 80 करोड़ रूपए से अधिक की सीमा का ऋण लेने वाले रत्न, आभूषण और हीरा (जी.जेडी.) क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए अधिक हानि अनुपात के कारण इस श्रेणी के गैर-जी.जे.डी. क्षेत्र के उधारकर्ताओं की तुलना में उच्च प्रीमियम दर होगी।

- ई.सी.आई.एस. के अंतर्गत, मूलधन और ब्याज दोनों के लिए बीमा कवर प्रतिशत को वर्तमान औसत 60% से बढ़ाकर 90% कर दिया गया है।
- दावों के त्वरित निपटान के कारण पूंजीगत राहत, न्यून प्रावधान अनिवार्यताएं और तरलता के कारण बीमा कवर से ऋण की लागत में कमी आने की उम्मीद है।
- यह निर्यात क्षेत्र के लिए समय पर और पर्याप्त कार्यशील पूंजी सुनिश्चित करेगा।

निर्यात ऋण गारंटी निगम

- यह पूर्णतय: सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है जिसे 1957 में ऋण बीमा सेवाएं प्रदान करके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था।
- यह बैंकों को निर्यात ऋण बीमा प्रदान करता है जिससे कि बैंकों को निर्यातक उधारकर्ता के दिवालियापन अथवा दीर्घकालिक डिफॉल्ट के जोखिम के कारण निर्यातक को प्री और पोस्ट शिपमेंट चरण में दिए गए निर्यात ऋण के कारण होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –भारतीय अर्थव्यवस्था

स्रोत- पी.आई.बी.

2. **<u>टाइलोफोराबालाकृष्णनन्नी और टाइलोफोरानेग्लेक्टा: पश्चिमी घाट में पौधों की नई प्रजातियां हैं।</u>**

- शोधकर्ताओं के एक दल ने पश्चिमी घाट के शोला जंगलों से पौधों की दो नई प्रजातियों की खोज करने की सूचना दी है, जो कि अस्लेपिआडासे या मिल्कवीड परिवार से संबंधित हैं।

टाइलोफोराबालाकृष्णनन्नी

- यह एक अव्यवस्थित बेल है, जिसकी खोज वायनाड के थोलायिरम शोला में की गई है।
- इस पौधे के फूल लाल-गुलाबी रंग के होते हैं और यह प्रजाति तटीय पौधे टाइलोफोराफ्लेक्सुओसा के समान होती है।

टाइलोफोरानेग्लेक्टा

- इसे भी शोला वन से खोजा गया है।
- इस प्रजाति के फूल एक बैंगनी रंगत के साथ सफेद रंग के होते हैं।
- इसकी पत्तियाँ मोटी और कड़ी होती हैं।

शोला वन

- ये उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन होते हैं जो केवल अधिक ऊंचाई पर घास के मैदानों द्वारा पृथक की गई घाटियों में पाए जाते हैं।
- ये केवल कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों पर पाए जाते हैं।

टॉपिक- जी.एस पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

3. **<u>ओडिशा सरकार ने पैराक्वात शाकनाशी पर प्रतिबंध लगा दिया है।</u>**

- ओडिशा सरकार ने पैराक्वात शाकनाशी पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे पिछले दो वर्षों में लगभग 170 लोगों की मृत्यु हो गई थी।
- डॉक्टरों के अनुसार, इस जड़ी बूटी में कोई विषहर औषधि नहीं है, जिसके उपभोक्ता गुर्दे, यकृत और फेफड़ों की समस्याओं की शिकायत करते हैं।

पैराक्वात के संदर्भ में जानकारी

- इसे स्विट्जरलैंड सहित 32 देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है, जहां शाकनाशी उत्पादक कंपनी सिजेन्टा स्थित है।
- पैराक्वात, 99 कीटनाशकों की सूची में भी शामिल हैं और शाकनाशी कार्यकर्ता कविता कुरूगांती ने उच्चतम न्यायालय से वर्तमान में चल रहे मामले में इसे प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया है।
- भारत में अब तक केवल केरल ने ही इस शाकनाशी पर प्रतिबंध लगाया है।
- पैराक्वात को रॉटरडैम सम्मेलन की पूर्व सूचित अनुज्ञा (पी.आई.सी.) में सूचीबद्ध किया जाना शेष है, जो 1998 में हानिकारक रसायनों के

आयात/ निर्यात पर हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।

रॉटरडैम सम्मेलन

- रॉटरडैम सम्मेलन (औपचारिक रूप से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ निश्चित हानिकारक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित अनुज्ञा प्रक्रिया पर रॉटरडैम सम्मेलन) एक बहुपक्षीय संधि है।
- इसका उद्देश्य हानिकारक रसायनों के आयात के संबंध में साझा जिम्मेदारियों को बढ़ावा देना है।
- यह सम्मेलन हानिकारक रसायनों के निर्यातकों को उचित लेबलिंग का उपयोग करने हेतु सूचना और बुलावों के खुले हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए कहता है, इसमें इनके सुरक्षित रख-रखाव पर दिशा-निर्देश शामिल हैं और खरीददारों को किसी भी ज्ञात प्रतिबंध या निषेध के बारे में सूचित करता है।
- भारत भी सम्मेलन की एक पार्टी है, इसमें 161 पार्टियां शामिल हैं।
- यदि पी.आई.सी. में कोई एक रासायन दर्ज है तो निर्यातक देश को आयात करने से पहले आयात करने वाले देश की पूर्व सहमति लेनी होगी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- डाउन टू अर्थ

4. **<u>संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने भारतीय सेना के दिग्गज अभिजीत गुहा को होदीदाह मिशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है।</u>**

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यमन के होदीदाह में संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) अभिजीत गुहा को नियुक्त किया है।

संबंधित जानकारी

संयुक्त राष्ट्र होदीदाह मिशन

- यह यमन सरकार और हौथी मिलिशिया के बीच 13 दिसंबर, 2018 को स्टॉकहोम में पहुंचे युद्धविराम समझौते के कार्यान्वयन का समर्थन करने हेतु एक विशेष राजनीतिक मिशन है।
- यह होदीदाह के शहर और बंदरगाह के साथ ही सालिफ और रस इस्सा के बंदरगाहों को भी को शामिल करेगा।
- यह युद्धविराम के अनुपालन की निगरानी करेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए पार्टियों के साथ काम करेगा कि यमनी कानून के अनुरूप स्थानीय सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षा आश्वस्त की जा रही है।
- इस मिशन का नेतृत्व पुनर्विन्यास समन्वय आयोग के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
- पुनर्विन्यास समन्वय आयोग, यमनी युद्धरत दलों के सुरक्षा बलों को उनके समझौते के अनुसार पुन: तैनात करने हेतु जिम्मेदार है।

होदीदाह समझौता

- हौथिस और सरकारी बल दिसंबर, 2018 में महत्वपूर्ण मानवीय सहायता की अनुमति देने के लिए हुदैयदाह बंदरगाह से हटने हेतु सहमत हुए थे।
- हुदैयदाह बंदरगाह, यमन की दो-तिहाई आबादी के लिए प्रमुख जीवन रेखा है।
- इसके बंद होने का यमन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –अंतर्राष्ट्रीय संबंध

स्रोत- पी.आई.बी.

5. **<u>वास्तुकला की ट्यूडर शैली</u>**

- हाल ही में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रह में नए बहाल किए गए जयकार बंगले का उद्घाटन किया है।
- यह बंगला वास्तुकला की ट्यूडर शैली का बेहतरीन उदाहरण है।

संबंधित जानकारी

ट्यूडर वास्तुकला शैली

- ट्यूडर वास्तुकला, वास्तुकला की एक शैली है जो 1485 और 1558 के बीच इंग्लैंड में विकसित हुई थी।
- यह एक संक्रमणकालीन शैली थी, जो पुनर्जागरण वास्तुकला के तत्वों का एक गोथिक शैली के साथ मिश्रण है, जो अधिकांशतः इंग्लैंड में पाई जाती है जिसे लंबवत गोथिक कहते हैं क्यों कि यह ऊर्ध्वाधर रेखाओं पर जोर देती था।
- ट्यूडर वास्तुकला इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड सहित ब्रिटिश द्वीपों के अन्य हिस्सों में पाई गई थी।
- ट्यूडर शैली की विशेषताओं में 'ब्लैक एंड व्हाइट' निर्माण था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –कला एवं संस्कृति

स्रोत- लाइवमिंट

6. **एक नया इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट "ओउमुआमुआ"**

- अक्टूबर 2017 में, हवाई स्थित हेलकाला वेधशाला ने सौर प्रणाली से गुजरने वाली एक अजीब, अंतरिक्ष यान के आकार की वस्तु को देखा है।
- बाद में इसे ओउमुआमुआ नाम दिया गया है, यह अटकलों का विषय बन गया है कि क्या यह वास्तव में एक एलियन अंतरिक्ष यान था, लेकिन अंततः वैज्ञानिकों द्वारा इसे एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट घोषित किया गया था जो सौर मंडल का इस प्रकार का पहला ज्ञात आगंतुक है।

संबंधित जानकारी

- क्रीमिया में मारगो वेधशाला ने एक धूमकेतु देखा है, खगोलविदों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति सौर मंडल के बाहर होने का अनुमान है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है।
- नासा की विमान संचालक प्रयोगशाला (जे.पी.एल.) के अनुसार, धूमकेतु को C/ 2019 Q4 (बोरिसोव) के रूप में नामित किया गया है।
- धूमकेतु की प्रारंभिक खोजों के बाद, जे.पी.एल. की स्काउट प्रणाली ने स्वचालित रूप से ऑब्जेक्ट को इंटरस्टेलर के रूप में चिह्नित किया।
- धूमकेतु का वर्तमान वेग लगभग 150,000 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो कि बहुत अधिक है, जो उस दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करने वाली वस्तुओं के विशिष्ट वेगों से काफी अधिक है।
- उच्च वेग न केवल यह इंगित करता है कि वस्तु की उत्पत्ति हमारे सौर मंडल के बाहर से हुई है बल्कि यह भी इंगित करता है कि यह बाहर किनल जाएगा और इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में वापस जाएगा।
- धूमकेतु, सूर्य से 420 मिलियन कि.मी. दूर स्थित है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत- टी.ओ.आई.

7. **सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के नौसेनाओं के मध्य त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास "सिटमैक्स" है।**

- सिंगापुर, भारत और थाईलैंड की नौसेनाओं ने पोर्ट ब्लेयर में अपना पहला संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास 'सिटमैक्स-2019' लांच किया है।
- इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य समुद्री संबंधों को मजबूत करना और समग्र समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3- रक्षा

स्रोत- द हिंदू

8. **आई.ए.एफ. ने सुखोई -30 एम.के.आई. से हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।**

- भारत ने ओडिशा के तट से दूर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण किया है।

- इस मिसाइल को एस.यू.-30 एम.के.आई. से उपयोगकर्ता परीक्षण के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था।
- सुखोई एस.यू.-30एम.के.आई., भारतीय वायु सेना (आई.ए.एफ.) के लिए रूस के सुखोई द्वारा विकसित एक ट्विनजेट मल्टीरोल एयर सुपीरियर फाइटर है।

संबंधित जानकारी

अस्त्र

- यह डी.आर.डी.ओ. द्वारा विकसित एक सभी मौसम से परे दृश्य-श्रव्य श्रेणी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।
- यह भारत द्वारा विकसित पहली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।
- इसकी विशेषता टर्मिनल सक्रिय राडार होमिंग के साथ मध्य-कार्यप्रणाली जड़त्वीय मार्गदर्शन प्रदान करना है।
- यह एक एकल चरण की ठोस ईंधन वाली मिसाइल है और इसकी पेलोड क्षमता 15 किलोग्राम पारंपरिक विस्फोटक की है।
- इस मिसाइल को आई.ए.एफ. के सभी लड़ाकू विमानों के साथ जोड़ा जा सकता है, जिसमें सुखोई -30 एम.के.आई., मिराज -2000, मिग -29, जगुआर और तेजस हल्के लड़ाकू विमान (एल.सी.ए.) शामिल हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –रक्षा

स्रोत- ए.आई.आर.

19.09.2019

1. **<u>एम.आई.एस. पोर्टल: सुगम्य भारत अभियान हेतु</u>**

- विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने सुगम्य भारत अभियान (ए.आई.सी.) के हितधारकों के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) विकसित की है।
- डी.पी.ई.डब्ल्यू.डी., सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय के अतंर्गत काम करता है।

प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल

- यह पोर्टल सुगम्य भारत अभियान के प्रत्येक लक्ष्य के प्रति की जा रही प्रगति की निगरानी करने के लिए सभी नोडल मंत्रालयों और राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को एक मंच पर लाएगा।
- यह डिजिटल मंच पर सभी कार्यों के विनियमन और वास्तविक समय के आधार पर डेटा एकत्र करने में भी उपयोगी होगा।
- यह पोर्टल दिव्यांगजनों के लिए पूर्णतया सुलभ है।

संबंधित जानकारी

सुगम्य भारत अभियान (सुगम्य भारत अभियान)

- यह सार्वभौमिक सुगमता प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख राष्ट्रव्यापी अभियान है जो विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर तक पहूँच प्राप्त करने और स्वतंत्र रूप से जीने और एक समावेशी समाज में जीवन के सभी पहलुओं में पूर्णतया भागीदारी करने में सक्षम बनाएगा।
- इस अभियान का लक्ष्य निर्मित पर्यावरण, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी प्रणाली की सुगमता को बढ़ाना है।

सुगम्य भारत अभियान के घटक

इसके निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण घटक हैं:

- निर्मित पर्यावरण सुगमता
- परिवहन प्रणाली सुगमता
- सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी प्रणाली सुगमता

नोट:-

संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्ति अधिकार सम्मेलन (यू.एन.सी.आर.पी.डी.)

- भारत, संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्ति अधिकार सम्मेलन (यू.एन.सी.आर.पी.डी.) का एक हस्ताक्षरकर्ता है।

- यू.एन.सी.आर.पी.डी. का अनुच्छेद 9, सभी हस्ताक्षरकर्ता सरकारों पर एक दायित्व बनाता है कि वे विकलांग व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों के समान बराबर के अवसर तक पहुँच प्रदान करने हेतु उपयुक्त उपाय करें।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नैंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

2. **<u>मंत्रिमंडल ने ई-सिगरेट पर प्रतिबंध को मंजूरी प्रदान की है।</u>**

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए ई-सिगरेट पर प्रतिबंध को मंजूरी प्रदान की है।
- इसमें इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी प्रणाली (ई.एन.डी.एस.), हीट नॉट बर्न उत्पाद, ई-हुक्का और इसी प्रकार के उपकरणों के सभी रूप शामिल हैं।

संबंधित जानकारी

ई-सिगरेट

- इसे ई-वेपोराइज़र या इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है।
- ये बैटरी द्वारा संचालित उपकरण होते हैं जो निकोटीन युक्त घोल को गर्म करके एरोसोल का उत्पादन करते हैं, जो दहनशील सिगरेट में एक नशीला पदार्थ होता है।
- आई.सी.एम.आर. द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, ई-सिगरेट के उपयोग से मनुष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- इनमें डी.एन.ए. क्षति, कैंसरकारक, कोशिकीय, आणविक और प्रतिरक्षा विषाक्तता, श्वसन, हृदय और तंत्रिका संबंधी विकार और भ्रूण के विकास और गर्भावस्था पर प्रतिकूल प्रभाव शामिल हैं।

नोट:

- एरोसोल, वायु अथवा किसी अन्य गैस में सूक्ष्म ठोस कणों या तरल बूंदों का निलंबन है।
- एरोसोल, प्राकृतिक या मानवजनित हो सकता है।
- प्राकृतिक एरोसोल के उदाहरण कोहरा, धूल, जंगलों का रिसाव और गीजर की भाप हैं।
- मानवजनित एरोसोल के उदाहरण धुंध, कणिका तत्व वायु प्रदूषक और धुआं हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नैंस

स्रोत- द हिंदू

3. **<u>विश्व बांस दिवस (18 सितंबर)</u>**

- यह दिवस प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को विश्व बांस संगठन द्वारा बांस उद्योग के संरक्षण और संवर्धन के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु मनाया जाता है।
- इसे गरीब आदमी की लकड़ी के रूप में भी जाना जाता है और बांस, आदिवासी संस्कृतियों और सामुदायिक जीवन में सर्वव्यापी है।
- कलाकृतियों से लेकर स्थायी वास्तुकला तक बांस सबसे पसंदीदा रहा है क्योंकि यह बहुत तेजी से बढ़ता है, इसका रख-रखाव कम है और इसमें बहुमुखी क्षमता है।
- एक अधिनियम के माध्यम से सरकार ने गैर-वन भूमि पर एक पेड़ के रूप में बांस को अवर्गीकृत किया था।
- भारत, 130 से अधिक प्रजातियों के साथ चीन के बाद विश्व में बांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

संबंधित जानकारी

- वर्ष 2018 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन को मंजूरी प्रदान की गई थी। यह क्षेत्र आधारित, क्षेत्रीय रूप से विभेदित रणनीति को अपनाकर और बांस की खेती और विपणन के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बांस क्षेत्र की समग्र प्रगति के संवर्धन की परिकल्पना करता है। भविष्य के समाकलन को संबोधित करने हेतु यह मिशन बांस के उत्पादों, विशेष रूप से हस्तशिल्प

वस्तुओं के विपणन को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहा है।

- इस वर्ष के बजट में, सरकार ने समूह आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से बांस, खादी और शहद जैसे पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। यह पारंपरिक उद्योग के पुनर्उत्थान हेतु कोष योजना (स्फूर्ति) के अंतर्गत किया जाएगा, जिसका उद्देश्य ऐसे उद्योगों और कारीगरों को प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु समूहों में संगठित करना है। इसका उद्देश्य उनकी दीर्घकालिक स्थिरता, सतत रोजगार और उत्पादों की विक्रेयता में वृद्धि हेतु समर्थन प्रदान करना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- ए.आई.आर.

4. **<u>केरल को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे में शामिल किया जाएगा।</u>**

- केंद्र सरकार ने चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे को कोयंबटूर और फिर कोच्चि तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है।
- गलियारे की स्थापना, क्षेत्र में विनिर्माण उद्योगों को विकसित करने और कोच्चि-पलक्कड़ क्षेत्र को दक्षिण भारत के एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र में बदलने में योगदान देगी।
- तमिलनाडु में पलक्कड़ और सलेम में दो एकीकृत विनिर्माण समूह (आई.एम.सी.) विकसित किए जाएंगे।
- राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एन.आई.सी.डी.आई.टी.) के मानदंडों के अनुसार, आई.एम.सी. स्थापित करने के लिए लगभग 2,000 से 5,000 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी।
- हालांकि, केरल सरकार के भूमि उपलब्ध कराने में कठिनाइयों के बारे में सूचित करने के बाद केंद्र ने 1,800 एकड़ में इसे स्थापित करने की राज्य की याचिका स्वीकार कर ली है।
- राज्य और केंद्र सरकार एक साथ मिलकर समूहों का प्रबंधन करने हेतु एक विशेष प्रयोजन वाहन का निर्माण करेंगे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –ढांचा

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

5. **<u>मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन</u>**

- हिमाचल प्रदेश सरकार ने जनता की शिकायतों के त्वरित और समयबद्ध निवारण हेतु एक हेल्पलाइन नंबर "1100" (मुखिया सेवा संकल्प हेल्पलाइन) लांच किया है।
- यह हेल्पलाइन नंबर लोगों को अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने में मदद करने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करेगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पेपरलेस हो जाएगी और सरकारी कार्यालयों में भीड़ कम हो जाएगी।
- अब, हिमाचल प्रदेश देश का चौथा राज्य (उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद) बन गया है, जिसके पास ऐसी हेल्पलाइन है।
- मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन, सप्ताह में 6 दिन (सोमवार से शनिवार) सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक कार्य करेगी।
- प्रत्येक शिकायत का 7-14 दिनों की अवधि के भीतर निवारण किया जाएगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –सरकारी नीतियां

स्रोत- डेली पॉयोनियर

6. **<u>राष्ट्रीय भर्ती संस्था</u>**

- वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय भर्ती संस्था (एन.आर.ए.) के निर्माण के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की है।
- यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सी.ई.टी.) आयोजित करने के लिए स्थापित की जाएगी।

- एन.आर.ए. का उद्देश्य सरकारी विभागों के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विभिन्न समकक्ष भर्ती के साथ समूह-बी (अराजपत्रित), समूह-सी (गैर-तकनीकी) और लिपिक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को संरेखित करना है।
- यह इन सभी भर्तियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगी, जो वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग (एस.एस.सी.) और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आई.बी.पी.एस.) द्वारा आयोजित की जाती हैं।
- इसके बाद यह मुख्य परीक्षाओं का संचालन करने के लिए संबंधित भर्ती संस्थाओं को योग्य उम्मीदवारों की सूची को अग्रेषित करेगा।
- प्रस्ताव के अनुसार, इसके बाद एन.आर.ए. मुख्य भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए संबंधित भर्ती संस्थाओं को योग्य उम्मीदवारों की सूची को अग्रेषित करेगा।
- इस प्रस्ताव के पीछे मूल विचार मुख्य परीक्षा के लिए भेजने से पहले एक पात्रता परीक्षा के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

7. **<u>सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत निवासियों का निष्कासन) संशोधन विधेयक, 2019</u>**

- सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत निवासियों का निष्कासन) संशोधन विधेयक, 2019 प्रभावी हो गया है, जिसे संसद द्वारा बजट सत्र के दौरान पारित किया गया था।

संबंधित जानकारी

सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत निवासियों का निष्कासन) अधिनियम 2019

- संशोधन अधिनियम के अनुसार, सरकारी आवास से अनधिकृत निवासियों के निष्कासन से तीन दिन पहले भूसंपत्ति (एस्टेट) अधिकारी लघु कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।
- इससे सरकारी आवासीय आवासों से अनधिकृत निवासियों का निष्कासन सुचारू और त्वरित हो जाएगा।
- इस अधिनियम को सार्वजनिक परिसरों से अनधिकृत निवासियों के निष्कासन और कुछ निश्चित प्रासंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था।
- सरकार अपने कर्मचारियों, संसद सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को लाइसेंस के आधार पर उनकी सेवा के दौरान अथवा उनके कार्यकाल की अवधि तक आवासीय आवास प्रदान करती है।
- यह अनधिकृत निवासियों से इन आवासीय आवासों की पुनर्प्राप्ति को सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

8. **<u>एन.जी.टी., घड़ियाल संरक्षण हेतु उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट चाहता है।</u>**

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मध्य प्रदेश सरकार को सोन नदी के किनारे घड़ियाल आवास के संरक्षण के लिए एक कार्य योजना के अनुसार उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

संबंधित जानकारी

- भारत में मगरमच्छ की प्रजातियां- साल्टवाटर, मगर और घड़ियाल पाई जाती हैं।

घड़ियाल

- ये मछली खाने वाले मगरमच्छ होते हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी हैं।
- इन्हें आई.यू.सी.एन. द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

- ये राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य (उत्तर प्रदेश), सोन नदी अभयारण्य (मध्य प्रदेश) और उड़ीसा के सतकोसिया कण्ठ अभयारण्य में महानदी के वर्षावन बायोम में पाए जाते हैं।

मगर

- मगर मगरमच्छ, जिसे भारतीय मगरमच्छ भी कहा जाता है, यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है।
- इसे आई.यू.सी.एन. द्वारा लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- मगर, मुख्य रूप से ताजे पानी में पाई जाने वाली प्रजाति है और यह झीलों, नदियों और दलदल में पाई जाती है।

साल्टवाटर मगरमच्छ

- यह सभी जीवित सरीसृपों में सबसे बड़ा है और पूरे भारत के पूर्वी तट पर पाया जाता है।
- इसे आई.यू.सी.एन. द्वारा कम से कम चिंताजनक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

9. <u>**श्रीलंका ने दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे टॉवर का अनावरण किया है।**</u>

- श्रीलंका ने दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे टॉवर का अनावरण किया है, जिसकी लागत $ 100 मिलियन से अधिक है, जिसका 80% चीन द्वारा विवादास्पद क्षेत्र एवं सड़क पहल (बी.आर.आई.) के अंतर्गत वित्त पोषित किया गया है।
- 350 मीटर लंबा, 17 मंजिला लोटस टॉवर कोलंबो शहर के दिल में स्थित है।
- श्रीलंका और चीन ने दक्षिण एशिया में उच्चतम टीवी टॉवर बनाने के लिए चीनी सरकार की महत्वाकांक्षी क्षेत्र एवं सड़क पहल (बी.आर.आई.) के अंतर्गत वर्ष 2012 में लोटस टॉवर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

टॉपिक- पी.सी.एस. और यू.पी.एस.सी. प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

स्रोत- द हिंदू

20.09.2019

1. <u>**भारत, पूरे विश्व में प्रवासियों का शीर्ष स्रोत है: अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी स्टॉक 2019**</u>

- न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र डी.एस.ए. द्वारा जारी किए गए डेटासेट के अनुसार, भारत पूरे विश्व में प्रवासियों के मूल के प्रमुख देश के रूप में उभरकर सामने आया है, वर्ष 2019 में भारत से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 17.5 मिलियन है जो कि वर्ष 2015 में 15.9 मिलियन से काफी अधिक है।
- यू.एन. डी.एस.ए. के जनसंख्या प्रभाग द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी स्टॉक 2019 में कहा गया है कि वर्ष 2019 में दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या अनुमानित 272 मिलियन तक पहुंच गई है जो कि वर्ष 2010 की तुलना में 51 मिलियन अधिक है।
- कुल वैश्विक आबादी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का प्रतिशत वर्ष 2000 के 8% से बढ़कर 3.5% हो गया है।
- जब कि भारत, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के शीर्ष स्रोत के रूप में बना हुआ है, इसके बावजूद भारत में रहने वाले प्रवासियों की संख्या वर्ष 2015 में 24 मिलियन से थोड़ी घटकर वर्ष 2019 में अनुमानित रूप से 5.15 मिलियन थी, ये दोनो आकंड़े देश की कुल जनसंख्या का 0.4% है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश, भारत में प्रवासियों के लिए मूल का अग्रणी देश था।
- यू.एन. डी.एस.ए. जनसंख्या प्रभाग ने कहा है कि कुल अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के एक तिहाई की उत्पत्ति 10 देशों से हुई है- भारत के बाद मेक्सिको दूसरे स्थान पर है, जहां पर 12

मिलियन प्रवासी हैं, इसके बाद चीन (11 मिलियन), रूस (10 मिलियन) और सीरिया (8 मिलियन) हैं।

- यूरोपीय क्षेत्र ने 2019 में प्रवासियों की सबसे अधिक संख्या 82 मिलियन की मेजबानी की है, इसके बाद उत्तरी अमेरिका (59 मिलियन) और उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया (49 मिलियन) का स्थान है। देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैश्विक प्रवासियों (51 मिलियन) की सबसे अधिक संख्या की मेजबानी की है, जो वैश्विक आबादी का लगभग 19% है।

संबंधित जानकारी

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग (यू.एन. डी.ई.एस.ए.)

- यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक हिस्सा है और यह प्रमुख संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलनों और सम्मेलनों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी और तीसरी समितियों की सेवाओं हेतु जिम्मेदार है। ।
- यू.एन. डी.ई.एस.ए., दुनिया भर के देशों की उनकी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को पूरा करने के लक्ष्य के साथ एजेंडा निर्धारण और निर्णय लेने में सहायता करता है।
- यह सतत विकास हेतु एजेंडा 2030 और 25 सितंबर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) की बुनियाद के साथ सभी के लिए सतत विकास को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करता है।
- यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य भी है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर - भारतीय अर्थव्यवस्था

स्रोत- पी.आई.बी.

2. **<u>सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 को लागू करने के लिए जांच करने और सिफारिशें करने हेतु कंपनी कानून समिति का गठन किया है।</u>**

- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों और मुद्दों पर सरकार को जांच और सिफारिश करने हेतु एक कंपनी कानून समिति का गठन करने का निर्णय लिया है।
- समिति के संदर्भ की शर्तों में अपराधों की प्रकृति (संयोजनीय और असंयोजनीय) का विश्लेषण करना और इसकी सिफारिश प्रस्तुत करना शामिल है कि क्यों कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अनुपालन आवश्यक्ताओं का अनुकूलन करने के उपायों के साथ ही किसी भी अपराध को 'दीवानी अपकार' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और भविष्य में व्यापार को और अधिक सरल बनाने के लिए सहवर्ती उपाय किए जा सके।
- समिति से एन.सी.एल.टी. के कामकाज में सुधार करने के लिए उपायों को प्रस्तावित करने और एस.एफ.आई.ओ., आई.ई.पी.एफ.ए., एन.एफ.आर.ए. इत्यादि जैसे सांविधिक निकायों के समग्र कामकाज में किसी भी अड़चन को दूर करने की आशा की जा रही है।
- इस समिति के अध्यक्ष कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव होंगे।

टॉपिक- जी.एस.-3- भारतीय अर्थव्यवस्था

स्रोत- पी.आई.बी.

3. **<u>घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर में कमी हुई है।</u>**

- रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर

22 प्रतिशत कर दिया है, इसमें सभी प्रकार के उपकर और अधिभार शामिल हैं।

- कर में रियायत करने से मेक इन इंडिया में निवेश होगा, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अधिक राजस्व प्राप्त होगा।
- आयकर अधिनियम में एक नए प्रावधान की घोषणा की गई है जो कि वित्त वर्ष 2019-20 से प्रभावी होगा, इसके अनुसार, "1 अक्टूबर के बाद से निगमित नई घरेलू विनिर्माण कंपनियां बिना किसी प्रोत्साहन राशि के 15 प्रतिशत की दर से आयकर का भुगतान कर सकती हैं।"
- उन कंपनियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम.ए.टी.) की दर को मौजूदा 5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है, जो प्रोत्साहन राशि या छूट प्राप्त करना जारी रखती हैं।
- घरेलू कंपनियों के लिए अधिभार और उपकर सहित कर की नई प्रभावी दर 17% होगी और नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए यह दर 17.01% होगी।
- ये दरें उन कंपनियों पर लागू होंगी, जो मौजूदा छूट और प्रोत्साहनों को छोड़ चुकी हैं।
- घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर में कमी इस वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होगी, जब कि नई घरेलू कंपनियों के लिए बदलाव उन कंपनियों के लिए लागू होंगे जो 1 अक्टूबर या उसके बाद निगमित होती हैं और 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले उत्पादन शुरू कर देंगी।

टॉपिक- जी.एस.-3- भारतीय अर्थव्यवस्था

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

4. **<u>पोषण अभियान के लक्ष्य आकांक्षी हैं।</u>**

- द लैंसेट में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार, महिलाओं और बच्चों में वृद्धि का रूकना, कम वजन, जन्म के समय कम वजन और रक्ताल्पता की व्यापकता में कमी के लिए महत्वाकांक्षी पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन (एन.एन.एम.) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को वर्ष 2022 तक पूरा करने की संभावना नहीं है।
- ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी 1990-2017 अध्ययन बताता है कि भारत वृद्धि में रूकावट के अपने 25% के लक्ष्य से 6% से, कम वजन के 22.7 प्रतिशत के लक्ष्य से 4.8% से, आकाक्षी कम जन्म स्तर के 11.4 प्रतिशत के लक्ष्य से 8.9 प्रतिशत से, महिलाओं में रक्ताल्पता के स्तर 39.4 प्रतिशत के लक्ष्य से 13.8 प्रतिशत से और बच्चों में रक्ताल्पता के 44.7 प्रतिशत के लक्ष्य से 11.7 प्रतिशत से चूक जाएगा।
- यह रिपोर्ट भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य फाउंडेशन (पी.एच.एफ.आई.) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की संयुक्त पहल है।
- रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि एन.एन.एम. द्वारा वर्ष 2022 के लिए निर्धारित कुपोषण संकेतक लक्ष्य आकांक्षात्मक हैं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सुधार की दर, इस अध्ययन में देखी गई दर से बहुत अधिक है, जिसे कम अवधि में प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है।

संबंधित जानकारी

- विश्व का सबसे बड़े पोषण कार्यक्रम, पोशन अभियान है, जिससे 10 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने की उम्मीद है और इसे वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य निम्न को कम करना है:

1. वृद्धि रूकना, कम वजन और जन्म के समय कम वजन प्रत्येक को प्रति वर्ष 2% तक करना

65TH BPSC
TEST SERIES 2019
CHECK HERE

2. वर्ष 2022 तक युवा बच्चों, किशोरों और महिलाओं में से प्रत्येक में रक्ताल्पता को 3% प्रति वर्ष तक करना
3. कुपोषण के लिए एक विशेष लक्ष्य 2022 तक 25% निर्धारित किया गया है

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (2015-2016) के अनुसार, पाँच वर्ष से कम आयु के 4% बच्चे कुपोषण से प्रभावित हैं, 35.7% कम वजन, 18% बच्चे जन्म के समय कम वजन (2.5 कि.ग्रा. से कम) और 6-59 माह की आयु के 58% बच्चों को और 14-49 वर्ष की आयु की 53% महिलाएं रक्ताल्पता से प्रभावित हैं।

टॉपिक- जी.एस.-2- स्वास्थ्य मुद्दे

स्रोत- द हिंदू

5. **<u>अटलांटिक दक्षिणी ओवरटर्निंग परिसंचरण</u>**

- एक नए अध्ययन के अनुसार, अटलांटिक दक्षिणी ओवरटर्निंग परिसंचरण के कमजोर होने से यूरोप और अटलांटिक रिम के अन्य हिस्सों के लिए नाटकीय परिणाम हो सकते हैं।
- मानव गतिविधि के कारण ग्रीनहाउस वार्मिंग भारतीय महासागरों को गर्म कर रही है, इसके अटलांटिक महासागर में धाराओं की एक महत्वपूर्ण प्रणाली को बढ़ावा देने की संभावना है जो दुनिया भर में मौसम का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

संबंधित जानकारी

अटलांटिक दक्षिणी ओवरटर्निंग परिसंचरण (ए.एम.ओ.सी.)

- इसे कभी-कभी "अटलांटिक कन्वेयर बेल्ट" के रूप में जाना जाता है।
- यह पृथ्वी की सबसे बड़ी जल संचलन प्रणाली में से एक है जहाँ महासागरीय धाराएँ गर्म और खारे पानी को उष्ण कटिबंध से उत्तरी क्षेत्रों जैसे कि पश्चिमी यूरोप में ले जाती हैं और ठंडे पानी को दक्षिण की ओर भेजती हैं।
- यह पृथ्वी के चारों ओर ऊष्मा और ऊर्जा को वितरित करने में सहायक होता है, क्योंकि यह गर्म पानी ले जाती है जो वायुमंडल में ऊष्मा निकालता है और वायुमंडलीय कार्बन को अवशोषित और संग्रहीत करता है।
- हिंद महासागर में वर्षा का उच्च स्तर, अटलांटिक महासागर में वर्षा को कम करेगा और पानी में लवणता को बढ़ाएगा।
- ए.एम.ओ.सी. ने 15,000 से 17,000 साल पहले कमी को देखा था।
- इससे यूरोप में कड़ाके की सर्दियां होंगी, ऊष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र के नीचे खिसकने के कारण अफ्रीको में अधिक तूफान आएंगे अथवा सूखे सहेल होंगे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –भूगोल (समुद्री धाराएं)

स्रोत- डाउन टू अर्थ

6. **<u>इंटरनेट मौलिक अधिकार तक पहुंच: केरल उच्च न्यायालय</u>**

- केरल उच्च न्यायालय ने माना है कि इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार, शिक्षा के मौलिक अधिकार के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार का हिस्सा भी है।
- यह फैसला कोझीकोड कॉलेज की एक छात्रा द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंधों का पालन नहीं करने के कारण उसके निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है।

संबंधित जानकारी

संबंधित निर्णय

- एस. रंगराजन और अन्य उपराष्ट्रपति जगजीवन राम (1989) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है "अनुच्छेद 19 (1) (ए) के अंतर्गत मौलिक स्वतंत्रता केवल अनुच्छेद 19 (2) में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए ही प्रतिबंधित की जा सकती है और प्रतिबंध को आवश्यकता की

निष्ठा पर उचित ठहराया जाना चाहिए और न कि सुविधा या शीघ्रता के बंधन में होना चाहिए।

- अदालत ने यह भी अवलोकन किया है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाया है कि इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार, एक मौलिक स्वतंत्रता है और शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने का एक उपकरण है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

7. **<u>दिल्ली पुलिस ने एक मोबाइल एप्लिकेशन तत्पर लांच किया है।</u>**

- हाल ही में, दिल्ली पुलिस ने तत्पर मोबाइल एप्लिकेशन जारी किया है जो ऑनलाइन एफ.आई.आर. (ई-एफ.आई.आर.) दर्ज करने में या अपने मोबाइल फोन से आसानी से ट्रैफिक चालान का भुगतान करने में मदद करता है।
- यह ऐप 50 से अधिक नागरिक-केंद्रित सेवाओं तक पहुंचने हेतु वन-स्टॉप गंतव्य है।
- यह ऐप आपकी अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन का पता लगाने और हेल्पलाइन के विभिन्न नंबरों पर कॉल करने में भी मदद करता है।
- इसमें तत्काल पुलिस सहायता हेतु एक एस.ओ.एस. बटन भी शामिल है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

8. **<u>आकांक्षी महिला उद्यमी शिखर सम्मेलन 2019 के लिए अपशिष्ट प्रबंधन एक्सीलिरेटर</u>**

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने नई दिल्ली में आकांक्षी महिला उद्यमी शिखर सम्मेलन 2019 के लिए अपशिष्ट प्रबंधन एक्सीलिरेटर (WAWE शिखर सम्मेलन 2019) के लिए अपशिष्ट प्रबंधन एक्सीकलरेटर का शुभारंभ किया है।
- इसे जयपुर में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) और अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा।
- यह अपशिष्ट प्रबंधन में उद्यमिता को बढ़ावा देने और एकल उपयोग प्लास्टिक कैरी बैग के विकल्प प्रदान करने के लिए युवा महिला छात्रों का सबसे बड़ा जमावड़ा होगा।
- शिखर सम्मेलन की थीम: **अपना खुद का बैग बनाए है- इस रिकॉर्ड से बाहर एक व्यवसाय बनाने के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन में आय सृजन गतिविधि और उद्यमशीलता को अपनाने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना है।**

टॉपिक-जी.एस. पेपर 2 –महिला सशक्तीकरण

स्रोत- पी.आई.बी.

9. **<u>भारत का सबसे पूर्वी गाँव: विजयनगर</u>**

- भारतीय वायु सेना ने देश के पूर्व में बसे हुए इलाके, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के विजयनगर में एक पुनर्जीवित हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है।
- विजयनगर तीन तरफ से म्यांमार से घिरा हुआ है और चौथी तरफ से नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1- भूगोल

स्रोत- टी.ओ.आई

10. **<u>राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी गठबंधन (एन.ई.ए.टी.) योजना</u>**

- इसे हाल ही में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है जो सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित है।
- इसका उद्देश्य शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण को अधिक व्यक्तिगत और अनुकूलित बनाने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना है।
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.), एन.ई.ए.टी. कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन संस्था होगी और इसे

एम.एच.आर.डी. द्वारा गठित एक सर्वोच्च समिति के मार्गदर्शन में प्रशासित किया जाएगा।

- एम.एच.आर.डी. यह सुनिश्चित करने के लिए एक सुविधा के रूप में कार्य करेगा कि समाधान आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों की एक बड़ी संख्या के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं।
- एडटेक कंपनियाँ, समाधान विकसित करने और एन.ई.ए.टी. पोर्टल के माध्यम से शिक्षार्थियों के पंजीकरण का प्रबंधन करने हेतु जिम्मेदार होंगी।
- वे अपनी नीति के अनुसार शुल्क लेने हेतु स्वतंत्र होंगे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

23.09.2019

1. **<u>मोज़ैक मिशन: आर्कटिक जलवायु की जांच करने हेतु इतिहास का सबसे बड़ा ध्रुवीय अभियान है।</u>**

- जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए आर्कटिक समुद्री बर्फ के बड़े टुकड़े का अध्ययन करने हेतु 19 देशों के वैज्ञानिकों का एक दल आर.वी. पोलरस्टर्न जहाज पर वर्षों लंबे माजैक मिशन की शुरूआत करने जा रहा है।

संबंधित जानकारी

मोज़ैक मिशन

- यह मिशन आर्कटिक जलवायु के अध्ययन के लिए बहुआयामी ड्रिफटिंग वेधशाला को दर्शाता है।
- इस मिशन का उद्देश्य आर्कटिक पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और यह किस प्रकार दुनिया के बाकी हिस्सों को प्रभावित कर सकता है, इसका अध्ययन करना है।
- इस मिशन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, ऊर्जा विभाग, राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन और नासा जैसे अमेरिकी संस्थानों से वित्तपोषण प्राप्त हुआ है।
- इस मिशन के अंतर्गत, वैज्ञानिकों ने आर्कटिक महासागर में आर.वी. पोलरस्टर्न जहाज को समुद्र में उतारने की योजना बनाई है, इसे बर्फ के एक बड़े टुकड़े पर लंगर डालने की योजना बनाई है और उसके चारों ओर पानी को इसके चारों ओर जमने की अनुमति दी गई है जिससे कि जिससे कि यह बर्फ की मोटी चादर से प्रभावी रूपसे ढक जाए, जैसा कि हमेशा उत्तरी ध्रुव पर सर्दियों में होता है।

जलवायु परिवर्तन पर भारत की आर्कटिक वेधशाला

हिमाद्री स्टेशन

- हिमाद्री स्टेशन, भारत का पहला आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन है जो स्पिट्सबर्गेन, स्वालबार्ड, नॉर्वे में स्थित है।
- इसका उद्घाटन वर्ष 2008 में पृथ्वी विज्ञान मंत्री द्वारा किया गया था।

इंडआर्क

- यह अगस्त, 2014 में स्थापित किया गया था जो नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव के बीच लगभग आधे रास्ते पर आर्कटिक के कोंग्सफजोर्डन फजॉर्ड में तैनात किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

2. **<u>सर्वोच्च न्यायालय को संविधान पीठ मिलेगी।</u>**

- सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक प्रश्नों से संबंधित मामलों की सुनवाई और निर्णय लेने के लिए अपने लगभग 70-वर्षीय इतिहास में एक स्थायी पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ बनाने का फैसला किया है।

संबंधित जानकारी

संविधान पीठ

- यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बेंचों को दिया गया नाम है जिसमें अदालत के कम से कम पांच न्यायाधीश शामिल होते हैं।

- ये न्यायाधीश भारत के संविधान की व्याख्या या अनुच्छेद 143 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए गए किसी भी संदर्भ की सुनवाई के उद्देश्य से कानून का एक ठोस प्रश्न रखने वाले केस पर निर्णय लेने हेतु बैठते हैं।
- संविधान पीठ के प्रावधान को भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के अंतर्गत अनिवार्य किया गया है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास संविधान पीठ गठित करने और इसे केस संदर्भित करने की शक्ति है।
- संविधान पीठों ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (आधारभूत संरचना सिद्धांत), के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य और अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ (ओ.बी.सी. आरक्षण) जैसे सर्वोच्च न्यायालय सबसे महत्वपूर्ण केसों का फैसला किया है।

नोट:

- इसे वर्ष 1950 में आठ न्यायाधीशों की शक्ति के साथ शुरू किया गया था जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल थे, हाल ही में संसद द्वारा किए गए संशोधन के बाद अब न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

3. **<u>मोची स्वाभिमान पहल</u>**

- केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने मोची स्वाभिमान पहल की शुरुआत की घोषणा की है।
- यह एक राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसमें चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद (एल.एस.एस.सी.), सी.एसआर कोष के साथ चमड़ा आधारित सेवाएं प्रदान करने वाले मोची समुदाय का समर्थन करेगा।
- इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि उन्हें बूथ/ छतरियों के रूप में एक बेहतर काम करने का माहौल देकर उनकी कार्यकुशलता के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए वे प्रतिष्ठित ढंग से काम करें।

सम्बंधित जानकारी

चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद

- यह एन.एस.डी.सी. द्वारा अनुमोदित गैर-लाभकारी संगठन है जो भारत में चमड़ा उद्योग में कुशल कर्मचारियों की मांग को पूरा करने हेतु समर्पित है, जिसे वर्ष 2012 में स्थापित किया गया था।
- यह उद्योग, सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, प्रशिक्षण भागीदारों और मूल्यांकन भागीदारों के सदस्यों के एक मेजबान के साथ काम करता है।
- यह एक राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसमें एल.एस.एस.सी. चमड़े पर आधारित सेवाएं प्रदान करने वाले मोची समुदाय का समर्थन करेगी, इसके साथ ही सी.एस.आर. कोष के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे प्रतिष्ठित ढंग से काम करें।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

4. **<u>अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण</u>**

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (ए.आई.एस.एच.ई.) 2018-19 जारी किया है।
- इस सर्वेक्षण के अंतर्गत, एम.एच.आर.डी. विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य उच्च शैक्षिक संस्थानों पर ऑनलाइन जानकारी एकत्र करता है।

सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं

- भारत में सबसे अधिक कॉलेजों के मामले में शीर्ष आठ राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश हैं।

- उच्च शिक्षा में कुल 37.4 मिलियन नामांकन होने का अनुमान लगाया गया है। कुल नामांकन का 48.6% महिलाएं है।
- पुरुष आबादी के लिए जी.ई.आर. 26.3% और महिलाओं के लिए 26.4% है। अनुसूचित जातियों के लिए 23% और अनुसूचित जनजातियों के लिए जीई.आर., 26.2% के राष्ट्रीय जी.ई.आर. की तुलना में 17.2% है।
- जी.ई.आर. देश के भीतर स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान स्तर के अध्ययन में नामांकित छात्रों की संख्या निर्धारित करने हेतु एक सांख्यिकीय उपाय है।
- जी.ई.आर. को 18-23 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- उत्तर प्रदेश सबसे अधिक छात्रों के नामांकन के साथ पहले स्थान पर आता है इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु के स्थान हैं।
- पिछले पांच वर्षों में लिंग समानता सूचकांक (जी.पी.आई.) बढ़ गया है जो कि 2014-15 में 0.92 से बढ़कर 2018-19 में 1 हो गया है।
- लिंग समानता सूचकांक, उच्च शिक्षा में महिला और पुरुष का अनुपात है जो लिंग समानता की दिशा में प्रगति को मापता है।
- विदेशी छात्रों का सबसे अधिक हिस्सा पड़ोसी देशों से आता है जिसमें नेपाल से कुल छात्रों का 26.88%, इसके बाद अफगानिस्तान (9.8%), बांग्लादेश (4.38%), सूडान (4.02%), भूटान (3.82%) और नाइजीरिया (3.4%) शामिल हैं।
- यदि नियमित मोड नामांकन माना जाता है तो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिष्य-शिक्षक अनुपात (पी.टी.आर.) 29 है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

5. **<u>पेस सेटर फंड कार्यक्रम</u>**

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पेस सेटर फंड कार्यक्रम के दूसरे दौर में चार परियोजनाओं को अनुदान प्रदान किया है।

संबंधित जानकारी

- इस कोष का गठन भारत और अमेरिका ने वर्ष 2015 में किया था।
- यह नवाचार ऑफ-ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा उत्पादों, प्रणालियों और व्यवसाय मॉडल के व्यावसायीकरण में तेजी लाने के लिए प्रारंभिक चरण अनुदान निधि प्रदान करने हेतु एक संयुक्त कोष है।
- इस कोष का मुख्य उद्देश्य ग्रिड से जुड़ी बिजली या सीमित/ आंतरायिक पहुंच (प्रतिदिन 8 घंटे से कम) के बिना व्यक्तियों और समुदायों को छोटे स्तर (1 मेगावॉट के भीतर) की स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियां बेंचने वाले ऑफ ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा व्यापार की व्यवहार्यता को सुधारना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –अर्थशास्त्र

स्रोत- टी.ओ.आई.

6. **<u>लद्दाखी शोंडोल नृत्य</u>**

- लद्दाखी शोंडोल नृत्य ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में फिर से इतिहास बनाया है।
- लद्दाख में 11वीं शताब्दी के विश्व प्रसिद्ध हेमिस मठ के पास चल रहे बौद्ध आनंदोत्सव, वार्षिक नरोपा महोत्सव के अवसर पर पारंपरिक परिधानों में सजी हुई 408 महिला कलाकारों बड़ी सुदरता से नृत्य किया है।

संबंधित जानकारी

- शोंडोल एक प्रसिद्ध नृत्य है, जो लद्दाख के राजा के लिए कलाकारों द्वारा एक विशेष अवसर पर किया जाता था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –कला एवं संस्कृति

स्रोत- ए.आई.आर.

7. **एन.टी.पी.सी., गुजरात में 5 गीगावॉट क्षमता का सौर पार्क बनाने जा रहा है।**

- भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड गुजरात के कच्छ में 5 गीगावॉट (जी.डब्ल्यू.) क्षमता का सौर पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है।
- परियोजना के लिए एक स्थान की पहचान की गई है, जिसकी प्रत्याशित लागत 25.000 करोड़ है और यह वर्ष 2024 तक गतिविधियों को शुरू करेगा।
- यह राष्ट्र का सबसे बड़ा सौर पार्क बनने जा रहा है।
- यह परियोजना एन.टी.पी.सी. के लक्ष्य का हिस्सा है, इसका लक्ष्य वर्ष 2032 तक 32 गीगावॉट (जी.डब्ल्यू.) नवीकरणीय क्षमता का निर्माण करना है, जिससे कि ऊर्जा मिश्रणों में जीवाश्म ईंधन का हिस्सा वर्तमान के 96 प्रतिशत से घटकर 70 प्रतिशत किया जा सके।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –ऊर्जा

स्रोत- ए.आई.आर.

8. **कोडियककराई वन्यजीव अभयारण्य में हिरणों की जनसंख्या के पुनर्वास की कवायद शुरू हो गई है।**

- तमिलनाडु में कोडियककराई वन्यजीव अभयारण्य में हिरणों के पुनर्वास का एक अनूठा प्रयास शुरू किया गया है।
- हिरणों को संरक्षित वातावरण से सिवागंगई पार्क में लाया जा रहा है।

संबंधित जानकारी

कोडियककराई वन्यजीव अभयारण्य

- इसे प्वाइंट कैलिमेयर वन्यजीव एवं पक्षी अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है।
- यह पाल्क जलडमरूमध्य के किनारे तमिलनाडु में एक संरक्षित क्षेत्र है, जहां यह नागापट्टिनम जिले के सिरे पर प्वाइंट कैलिमेयर (कोडियककराई) में बंगाल की खाड़ी से मिलता है।
- इस अभयारण्य को वर्ष 1967 में भारत की एक स्थानिक स्तनपायी संकटग्रस्त प्रजाति, कृष्णमृग हिरण के संरक्षण हेतु बनाया गया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

9. **पूसा यशस्वी**

- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने आगामी रबी की फसल के मौसम में रोपण के लिए एक संभावित ब्लॉकबस्टर किस्म के रूप में पूसा यशस्वी को जारी किया है।
- इसे एच.डी.-3226 भी कहा जाता है।
- गेहूं की अन्य किस्मों की तुलना में यह अधिकतम आनुवांशिक उपज क्षमता वाली है।
- इस किस्म का बीज सभी प्रमुख जंग कवकों जैसे: पीला/ पट्टी, भूरा/ पत्ती और काला/ तना के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –कृषि

स्रोत- डाउन टू अर्थ

10. **मत्स्य सांख्यिकी- 2018**

- केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने मत्स्य पालन सांख्यिकी-2018 पर पुस्तिका के 13वें संस्करण को जारी किया है।

पुस्तिका की मुख्य विशेषताएं

- भारत वर्तमान में विश्व में मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- यह जलीय कृषि उत्पादन के साथ-साथ अंतर्देशीय कैप्चर मत्स्य पालन में भी विश्व में दूसरे स्थान पर है।
- वर्ष 2016-17 (11.43 मिलियन मीट्रिक टन) की तुलना में 2017-18 के दौरान मछली उत्पादन में औसत वृद्धि 10.14% की हुई है।
- वर्ष 1950-51 के दौरान कुल मछली उत्पादन में अंतर्देशीय मछली उत्पादन का 29 प्रतिशत

65TH BPSC
TEST SERIES 2019
CHECK HERE

योगदान वर्ष 2017-18 में बढ़कर 71% हो गया है।

- आंध्र प्रदेश ने अंतर्देशीय मछली का सबसे अधिक उत्पादन दर्ज किया है जब कि गुजरात, देश में समुद्री मछली के संदर्भ में अग्रणी राज्य है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1- भूगोल

स्रोत- पी.आई.बी.

24.09.2019

1. **गंगा डेटा कलेक्टर: गंगा जल, जलीय जीवन के मानचित्रण हेतु एक ऐप है।**

- देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यू.आई.आई.) ने “जैव विविधता और गंगा संरक्षण” के अंतर्गत एक मोबाइल एप्लिकेशन “गंगा डेटा कलेक्टर” लॉन्च किया है।
- केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन.एम.सी.जी.) द्वारा जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण परियोजना की शुरूआत की गई है।

संबंधित जानकारी

गंगा डेटा कलेक्टर

- इस एप्लीकेशन का उद्देश्य गंगा नदी में जलीय आबादी की निगरानी करने के लिए क्षेत्र के शोधकर्ताओं को एक संपूर्ण डेटा प्रविष्टि समाधान प्रदान करना है।
- यह एप्लीकेशन भारतीय वन्यजीव संस्थान, गंगा घाटी के 11 राज्यों में गंगा प्रहरियों और वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा गंगा नदी में पानी की गुणवत्ता और जलीय जीवन से संबंधित प्रामाणिक और सटीक डेटा के तेजी से संग्रहण हेतु उपयोग किया जाएगा।
- गंगा घाटी में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली सहित 11 राज्य शामिल हैं।

भारतीय वन्यजीव संस्थान

- यह भारत सरकार के पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है।
- इसकी स्थापना 1982 में की गई थी जो उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित संस्थान है जो वन्यजीव अनुसंधान एवं प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम, अकादमिक पाठ्यक्रम और सुझाव प्रदान करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- पी.आई.बी.

2. **वर्ष 2022 तक भारत का नया गैर-जीवाश्म ईंधन का लक्ष्य 450 गीगावॉट है।**

- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भारत के अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को 450 गीगावॉट तक बढ़ाया जाएगा जो पहले पेरिस जलवायु समझौते के अंतर्गत 2022 तक 175 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता था।

प्रधानमंत्री के भाषण की मुख्य विशेषताएं

- भारत "अगले कुछ वर्षों में" जल जीवन मिशन पर लगभग 50 बिलियन डॉलर खर्च करेगा जिससे कि जल का संरक्षण, वर्षा जल का संरक्षण किया जा सके और जल संसाधनों का विकास किया जा सके।
- प्रधानमंत्री ने एकल-उपयोग प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, एक भारतीय-नेतृत्व वाली पहल और भारत ने 160 मिलियन परिवारों को गैस कनेक्शन वितरित किए थे, अपने इन कदमों पर प्रकाश डाला था।
- उन्होंने दो अंतर्राष्ट्रीय पहलों की भी घोषणा की थी।

- पहली पहल, उद्योगों के लिए न्यूनतम कार्बन तरीकों को विकसित करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्रों के एक साथ मिलकर काम करने हेतु स्वीडन और अन्य देशों के साथ एक मंच का निर्माण करना है।
- दूसरी पहल, आपदा रोधी संरचना गठबंधन है, जिसे पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसकी तकनीकी सहायता और परियोजनाओं के लिए 480 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं।
- अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिजी और मालदीव जैसे द्वीप राष्ट्र इस गठबंधन का हिस्सा होंगे।

संबंधित जानकारी

आपदा रोधी संरचना गठबंधन

- वर्ष 2017 में हैम्बर्ग में जी20 की बैठक में प्रधानमंत्री ने आपदा रोधी संरचना गठबंधन (सी.डी.आर.आई.) का प्रस्ताव दिया था।
- सी.डी.आर.आई. एक आयोजक निकाय के रूप में कार्य करेगा जो निर्माण, परिवहन, ऊर्जा, दूरसंचार और जल को पुन: आकार देने हेतु दुनिया भर से सर्वोत्तम प्रथाओं और संसाधनों को एकत्र करेगा, जिससे कि प्राकृतिक आपदाओं में इन प्रमुख बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों के कारकों का निर्माण हो सके।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- ए.आई.आर.

3. **<u>एम.एस.एम.ई. ने ज्ञान प्रबंधन पोर्टल "सिद्धी" लॉन्च किया है।</u>**

- केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ने राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता संवर्धन सम्मेलन में ज्ञान प्रबंधन पोर्टल "सिद्धी" लॉन्च किया है।
- इस सम्मेलन का आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किया गया था।

सिद्धी पोर्टल

- इस पोर्टल को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (बी.ई.ई. के एम.एस.एम.ई.) कार्यक्रम के अंतर्गत लॉन्च किया गया है।
- यह पोर्टल ऊर्जा-दक्षता प्रौद्योगिकियों को जल्दी अपनाने के लिए एम.एस.एम.ई. के लिए मल्टीमीडिया ट्यूटोरियल के पचास वीडियो सहित उपयोगी जानकारी की मेजबानी करेगा।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

- यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है।
- यह भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने में सहायता करता है।
- यह नामित उपभोक्ताओं, नामित संस्थाओं और अन्य संगठनों के साथ समन्वय करता है जिससे कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इसे सौंपे गए कार्यों को करने में मौजूदा संसाधनों और बुनियादी ढांचे की पहचान और उपयोग कर सकें।

टॉपिक-जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

4. **<u>उत्सर्जन व्यापार योजना: प्रदूषण नियंत्रण में पहली बार</u>**

- हाल ही में, गुजरात सरकार ने उत्सर्जन व्यापार योजना (ई.टी.एस.) लॉन्च की है, जो कणिका तत्व उत्सर्जन में व्यापार हेतु सूरत में स्थित विश्व का पहला बाजार है।
- कणिका तत्व (जिसे कण प्रदूषण भी कहा जाता है), हवा में पाए जाने वाले ठोस कण और जल की बूंदों का मिश्रण है।
- कुछ कण जैसे कि धूल, गंदगी, कालिख या धुआं, ये इतने बड़े या काले होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है।
- कणिका प्रदूषण में शामिल हैं:

65TH BPSC
TEST SERIES 2019
CHECK HERE

- पी.एम. 10: श्वसन के माध्यम से जाने वाले कण होते हैं, इनका व्यास सामान्यत: 10 माइक्रोमीटर और इससे कम होता हैं।
- पी.एम.2.5: श्वसन के माध्यम से जाने वाले बारीक कण होते हैं, इनका व्यास सामान्यत: 2.5 माइक्रोमीटर और इससे कम होता हैं।

उत्सर्जन व्यापार योजना

- यह एक विनियामक उपकरण है जिसका उद्देश्य किसी क्षेत्र में प्रदूषण भार को कम करना है और इसके साथ ही समान समय में उद्योग के अनुपालन की लागत को भी कम करना है।
- ई.टी.एस. एक ऐसा बाजार है जिसमें व्यापार की जाने वस्तु कणिका तत्व उत्सर्जन होगी।
- राष्ट्रीय वस्तु एवं व्युतपन्न विनिमय ई-मार्केट्स लिमिटेड (एन.ई.एम.एल.) द्वारा आयोजित किए गए ई.टी.एस.-पी.एम. ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने या नीलामी की सुविधा प्रदान की गई है।

नोट:

- यह योजना अद्वितीय है क्यों कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यापार तंत्र दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद हैं लेकिन उनमें से कोई भी कणिका तत्व उत्सर्जन के लिए नहीं है।

उदाहरण:

- क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत सी.डी.एम. (कार्बन विकास तंत्र) कार्बन क्रेडिट में व्यापार करने की अनुमति देता है।
- यूरोपीय संघ की उत्सर्जन व्यापार प्रणाली, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए है।
- भारत के पास ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा संचालित एक योजना है जो ऊर्जा इकाइयों में व्यापार करने में सक्षम है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

5. **<u>'ई-बीट बुक' प्रणाली और "ई-साथी" ऐप</u>**

- केंद्रीय गृह मंत्री ने चंडीगढ़ पुलिस के लिए ई-बीट बुक प्रणाली और 'ई-साथी' ऐप जैसी नागरिक-केंद्रित सेवाएं लॉन्च की हैं।

'ई-बीट बुक'

- यह एक वेब और मोबाइल-आधारित एप्लीकेशन है जो वास्तविक समय में अपराध और अपराधियों से संबंधित जानकारी के संग्रह, अपडेशन और विश्लेषण को आसान बना देगा।
- ई-बीट बुक को अपराध एवं आपराधी निगरानी नेटवर्क और प्रणाली (सी.सी.टी.एन.एस.) के साथ जोड़ा जाएगा, जो अपराध/ आपराधिक डेटा के वास्तविक समय में अपडेशन में मदद करेगा।

'ई-साथी' ऐप

- यह वरिष्ठ नागरिकों सहित आम जनता की पुलिस के संपर्क में बने रहने में मदद करेगा और सहभागी सामुदायिक पुलिसिंग (आपकी पुलिस, आपके दरवाजे पहल') की सुविधा के लिए सुझाव भी देगा।
- बीट अधिकारी, ऐप पर एक बटन पर क्लिक करने के द्वारा पासपोर्ट सत्यापन, किरायेदार सत्यापन, नौकर सत्यापन, चरित्र प्रमाणन आदि जैसी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा, इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट:

सी.सी.टी.एन.एस.

- यह जून, 2009 में शुरू की गई एक परियोजना है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
- इस परियोजना का उद्देश्य पुलिस स्टेशन स्तर पर पुलिसिंग की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने हेतु एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली का निर्माण करना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- टी.ओ.आई.

6. **<u>आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन एवं उपचार के अद्वितीय तरीके (UMMID)</u>**

- केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने UMMID (उम्मीद) (आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन एवं उपचार के अद्वितीय तरीके) पहल की शुरूआत की है।
- नई पहल का उद्देश्य चिकित्सकों के बीच आनुवंशिक विकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना है और अस्पतालों में आणविक इलाज की सुविधा स्थापित करना है जिससे कि चिकित्सा आनुवंशिकी में विकास का लाभ रोगियों तक पहुंच सके।
- इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.), एम./ओ. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित किया जा रहा है।
- UMMID (उम्मीद) पहल के उद्देश्य हैं:

1. सरकारी अस्पतालों में परामर्श, प्रसवपूर्व परीक्षण और निदान, प्रबंधन और बहु-विषयक देखभाल प्रदान करने के लिए निदान केंद्रो की स्थापना करना, जहां रोगी अधिक संख्या में आते हैं।
2. मानव अनुवांशिकी में कुशल चिकित्सकों का सृजन करना और
3. आकांक्षी जिलों के अस्पतालों में विरासत में मिली आनुवांशिक बीमारियों के लिए गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की स्क्रीनिंग करना

नोट:

- राष्ट्रीय अनुवांशिक रोग प्रशासन (NIDAN) केंद्रों को व्यापक नैदानिक देखभाल प्रदान करने के लिए स्थापित किया जाएगा।
- यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.), एम./ओ. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा भी समर्थित है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत- पी.आई.बी.

7. **<u>जनगणना 2021</u>**

- हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की है कि 2021 की जनगणना का आयोजन भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा डिजिटल रूप से किया जाएगा।
- सरकार, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) और जनगणना की तैयारी पर 12,000 करोड़ खर्च करेगी।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर

- यह देश के सामान्य निवासियों का रजिस्टर है।
- यह नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थानीय (ग्राम/ उप-कस्बा), उप-जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है।
- भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए एन.पी.आर. में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- यह राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से संबद्ध नहीं है।
- एक सामान्य निवासी को एन.पी.आर. के उद्देश्यों के लिए ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो पिछले 6 महीने या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में रहता हो या वह व्यक्ति उस क्षेत्र में अगले 6 महीने या उससे अधिक समय तक निवास करने का इरादा रखता हो।
- एन.पी.आर. का उद्देश्य देश में प्रत्येक सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना है।
- डेटाबेस में कुछ निश्चित जनसांख्यिकीय के साथ-साथ बॉयोमीट्रिक विवरण शामिल होंगे।

भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त (आर.जी.सी.सी.)

- भारत के आर.जी.सी.सी. का पद सामान्यत: एक सिविल सेवक के पास होता है जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव का पद धारण करता है।
- वह प्रत्येक दशकीय जनगणना के संचालन हेतु जिम्मेदार होता है, वह जनगणना संगठन (संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 69 में उल्लिखित) का प्रमुख होता है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) के तत्वावधान में कार्य करता है।

नोट:

- केंद्र ने हरियाणा कैडर के 1989 बैच के आई.ए.एस. अधिकारी विवेक जोशी को भारत के नए रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

25.09.2019

1. **भारत-अमेरिका त्रिकोणीय सेवा '' टाइगर ट्राइम्फ युद्धाभ्यास''**

- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, इस वर्ष नवंबर में विशाखापत्तनम और काकीनाडा में "टाइगर ट्राइम्फ" नामक अपना पहला त्रिकोणीय सेवा युद्धाभ्यास आयोजित करने के लिए तैयार हैं।
- एकीकृत रक्षा कर्मचारियों के मुख्यालय के तत्वावधान में भारत-अमेरिका त्रिकोणीय-सेवा ''टाइगर ट्राइम्फ युद्धाभ्यास'' का आयोजन किया जा रहा है।
- भारत-अमेरिका त्रिकोणीय-सेवा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (एच.ए.डी.आर.) के लिए अंतिम योजना सम्मेलन (एफ.पी.सी.) का आयोजन 20 सितंबर को पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय में संपन्न हुआ है।
- पहली बार, अमेरिका और भारत त्रिकोणीय सेवा सैन्य युद्धाभ्यास करेंगे। भारत ने पहले रूस के साथ इस प्रकार का त्रिकोणीय सेवा युद्धाभ्यास किया था।

टॉपिक- जी.एस.-3- रक्षा

स्रोत- एन.डी.टी.वी.

2. **गांधी सौर पार्क**

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य विश्व नेताओं के साथ गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) मुख्यालय में गांधी सौर पार्क का उद्घाटन किया है।
- यह 50 किलोवॉट का रूफ-टॉप सौर पार्क है जिसमें 193 सौर पैनल हैं, इनमें से प्रत्येक बहुपक्षीय निकाय के सदस्य का प्रतिनिधित्व करता है।

संबंधित जानकारी

- हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा "ग्लोबल गोलकीपर" पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

3. **कृषि किसान ऐप**

- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने नई दिल्ली में 'भू टैगिंग' के लिए कृषि किसान ऐप लॉन्च किया है।

ऐप के संदर्भ में जानकारी

- यह किसानों को उनके आस-पास के क्षेत्र में अधिक उपज वाली फसलों और बीजों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की जानकारी प्रदान करेगा।
- यह एप्लिकेशन अन्य किसानों को खेती की सर्वोत्तम प्रथाओं को दिखाने में मदद करता है

जिससे कि यह अन्य किसानों की भी इन तरीकों को अपनाने में मदद करेगा।

- इसके अतिरिक्त यह ऐप फसल की भू-टैगिंग और भू-बाड़ लगाने में भी मदद करेगा और किसानों को मौसम का पूर्वानुमान संदेश देगा।

संबंधित जानकारी

कस्टम हायरिंग केंद्र कृषि मशीनरी एप्लीकेशन

- इस एप्लिकेशन की मदद से किसान 50 किलोमीटर के दायरे में स्थित कस्टम हायरिंग केंद्रों से उनके लिए संभव दरों पर आवश्यक मशीनरी का चयन और ऑर्डर कर सकते हैं।
- बहु-भाषायी मोबाइल ऐप सी.एच.सी. कृषि मशीनरी पहले से ही कस्टम सेवा प्रदाताओं के लिए कृषि मशीनरी कस्टम सेवा केंद्रों की भू-संदर्भित तस्वीरों और इसमें उपलब्ध मशीनरी की तस्वीरों के साथ पंजीकरण और अपलोड करने हेतु उपलब्ध है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

4. **<u>आपदा के बाद (पोस्ट डिजास्टर) आवश्यकता मूल्यांकन</u>**

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) ने आपदा के बाद (पोस्ट डिजास्टर) आवश्यकता मूल्यांकन (पी.डी.एन.ए.) पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था।

संबंधित जानकारी

आपदा के बाद (पोस्ट डिजास्टर) आवश्यकता मूल्यांकन

- पी.डी.एन.ए. उपकरण को संयुक्त राष्ट्र विकास समूह, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ द्वारा अपने वर्ष 2018 के समझौते की प्रमुख प्रतिबद्धताओं के रूप में विकसित किया गया था, यह समझौता संकट के बाद (पोस्ट क्राइसिस) सेटिंग में सामान्य मूल्यांकन एवं बहाली योजना दृष्टिकोण को विकसित करने और प्रयोग करने के संदर्भ में है।
- यह आपदा के परिणामस्वरूप हुई क्षति और नुकसान का मूल्यांकन करने और बहाली की आवश्यक्ताओं और रणनीतियों की सिफारिश करने में मदद करता है।
- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र द्वारा केरल सरकार के नेतृत्व में आयोजित किए गए आपदा के बाद (पोस्ट डिजास्टर) आवश्यक्ता मूल्यांकन (पी.डी.एन.ए.) का अनुमान है कि कुल बहाली लागत 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

- भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.), आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च संवैधानिक निकाय है।
- इसे औपचारिक रूप से 27 सितंबर, 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया था।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के प्रति प्रतिक्रिया का समन्वय करना और आपदा लचीलापन और संकट प्रतिक्रिया में क्षमता निर्माण करना है।
- यह आपदाओं के प्रति समयबद्ध और प्रभावी प्रतिक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन हेतु नीतियों, योजनाओं और दिशानिर्देशों को निर्धारित करने हेतु एक शीर्ष निकाय भी है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- पी.आई.बी.

5. **<u>दुबई में दुनिया का पहला ऊंट अस्पताल, अपनी सुविधाओं का विस्तार करने हेतु तैयार है।</u>**

- दुबई में दुनिया का पहला ऊंट अस्पताल, अपनी सेवाओं की मांग में वृद्धि के जवाब में अपनी सुविधाओं का 50 प्रतिशत अतिरिक्त विस्तार करने हेतु तैयार है।

- यह एक अनोखा अस्पताल है जो विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकसित और बढ़ते हुए ऊंट उद्योग की आवश्यक्ताओं को पूरा कर रहा है।
- ऊंट, संयुक्त अरब अमीरात की विरासत का एक अभिन्न हिस्सा हैं।
- 40 मिलियन दरहम की अनुमानित लागत से निर्मित ऊंट अस्पताल को वर्ष 2017 में खोला गया था, यह अस्पताल ऊंटों के इलाज के लिए समर्पित एक उन्नत चिकित्सा सुविधा की संयुक्त अरब अमीरात में मांग को पूरा करने के लिए खोला गया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- पी.आई.बी.

6. **<u>हिक्का चक्रवात, "बहुत गंभीर तूफान" में बदल गया है।</u>**

- चक्रवात हिक्का अरब सागर में पश्चिम की ओर बढ़ते हुए "बहुत भयंकर तूफान" में बदल गया है और इसके ओमान तट को पार करने की संभावना है।

संबंधित जानकारी

उष्णकटिबंधीय चक्रवात हिक्का

- चक्रवात का नाम हिक्का, मालदीव द्वारा दिया गया है।
- हिक्का तूफान 10 कि.मी. प्रति घंटे की रफ्तार से 90 कि.मी. प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा की गति से आगे बढ़ रहा है।
- भारतीय मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि गुजरात के तट से दूर पूर्व-मध्य और उत्तर-पूर्व में अरब सागर पर एक गहन डिप्रेशन के संभावित निर्माण के कारण सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय जिलों में कई स्थानों पर 'हल्की से मध्यम वर्षा' और 'अलग-थलग स्थानों पर भारी वर्षा' की भविष्यवाणी की है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बहुत तेज हवाओं की विशेषता वाले उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में होने वाली निम्न दबाव की प्रणाली है।
- ये गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न और तीव्र होते हैं।
- ये भयंकर तूफान होते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों पर उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों में हिंसक हवाओं, बहुत भारी वर्षा और तूफान के रूप में आते हैं।

विभिन्न क्षेत्रों में चक्रवातों के नाम

- उन्हें निम्न रूप में जाना जाता है:

1. हिंद महासागर में चक्रवात
2. अटलांटिक में हरीकेन
3. पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में टाइफून
4. पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली-विली

उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण हेतु स्थितियां

- उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान के निर्माण और तीव्रता के पक्ष में स्थितियां निम्न हैं:

1. 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के साथ बड़ी समुद्र सतह
2. कोरिओलिस बल की उपस्थिति
3. ऊर्ध्वाधर हवा की गति में कम अंतर
4. पहले से मौजूद कमजोर-निम्न-दबाव क्षेत्र या निम्न-स्तरीय-चक्रवाती परिसंचरण
5. समुद्र तल प्रणाली के ऊपर ऊपरी विचलन

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –भूगोल

स्रोत- टी.ओ.आई.

7. **<u>ई.सी.आई. ने महाराष्ट्र के लिए दो विशेष व्यय पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया है।</u>**

- हाल ही में, भारतीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा के आगामी चुनावों के लिए दो विशेष व्यय पर्यवेक्षकों को नियुक्ति किया है।

संबंधित जानकारी

विशेष व्यय पर्यवेक्षक

- संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत ई.सी.आई. को प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में विशेष व्यय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाती है।

कार्य

- विशेष पर्यवेक्षक, निर्वाचन मशीनरी द्वारा किए जा रहे कार्यों की निगरानी और निरीक्षण करेंगे।
- वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कठोर और प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है जो नकदी, शराब और मुफ्त के उपहार वितरित करके मतदाताओं को प्रेरित करने की कोशिश करते हैं।
- इनका मुख्य कार्य संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के परामर्श से धन शक्ति के दुरुपयोग को नियंत्रित करने पर विशेष जोर देने के साथ चुनावों के संचालन की निगरानी करना होता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

8. **राष्ट्रीय अनुकूलन फंड**

- विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत का जलवायु अनुकूलन फंड केवल 100 करोड़ रुपये का है और प्रत्येक राज्य में लगभग एक परीक्षण परियोजना बहुत ही अपर्याप्त है।

संबंधित जानकारी

फंड के संदर्भ में जानकारी

- राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन फंड (एन.ए.एफ.सी.सी.), एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे वर्ष 2015-16 में स्थापित किया गया था।
- एन.ए.एफ.सी.सी. का समग्र उद्देश्य उन ठोस अनुकूलन गतिविधियों का समर्थन करना है जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करती हैं।
- इस योजना के अंतर्गत गतिविधियों को एक परियोजना मोड में कार्यान्वित किया जाता है।
- कृषि, पशुपालन, जल, वानिकी, पर्यटन आदि जैसे क्षेत्रों में अनुकूलन से संबंधित परियोजनाएं, एन.ए.एफ.सी.सी. के अंतर्गत वित्त पोषण के योग्य हैं।
- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई (एन.आई.ई.) है।

नोट:

- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन, वर्तमान जलवायु परिवर्तन प्रभावों और अनुमानित प्रभावों के जवाब में पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों में समायोजन के लिए अनुकूलन को परिभाषित करता है।
- "यह सामान्य संभावित नुकसानों अथवा जलवायु परिवर्तन से संबंधित अवसरों से लाभ प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं, प्रथाओं और संरचनाओं में परिवर्तन को संदर्भित करता है।"

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

9. **दादा साहब फाल्के पुरस्कार**

- हाल ही में, अमिताभ बच्चन को देश के सर्वोच्च फिल्म सम्मान, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

संबंधित जानकारी

दादा साहब फाल्के पुरस्कार

- यह सिनेमा जगत में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है जो पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था।
- यह पुरस्कार प्रतिवर्ष फिल्म समारोह निदेशालय (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक संगठन) द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाता है।
- इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल, 10 लाख का नकद पुरस्कार और एक शाल शामिल है।

- इस पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता अभिनेत्री देविका रानी, "भारतीय सिनेमा की पहली महिला" थीं।

नोट:

- दादासाहेब फाल्के, एक भारतीय फिल्म निर्माता थे जिन्होंने भारत की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र (1913) का निर्देशन किया था।
- उन्हें "भारतीय सिनेमा का जनक" माना जाता है।

टॉपिक- पी.सी.एस. परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण

स्रोत-द हिंदू

26.09.2019

1. **<u>माइक्रोहाइला ईओस: एक नई मेंढक प्रजाति</u>**

- वैज्ञानिकों ने नामदाफा टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश में माइक्रोहाइला ईओस नामक मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की है।

संबंधित जानकारी

माइक्रोहाइला ईओस

- वे सकरें मुंह वाले मेंढकों के समूह से संबंधित हैं जो मुख्य रूप से और व्यापक रूप से एशिया में पाए जाते हैं।
- इन्हें सामान्यत: राइस मेंढक या कोरस मेंढक के रूप में जाना जाता है।

नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान:

- नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा संरक्षित क्षेत्र है।
- यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है।
- नामदाफा फ्लाइंग गिलहरी, इस पार्क के लिए स्थानिक है और गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण एवं जैवविविधता

स्रोत- द हिंदू

2. **<u>कश्मीर के प्रसिद्ध केसर को जी.आई. टैग प्रदान किया गया है।</u>**

- कश्मीर के प्रसिद्ध केसर को भौगोलिक संकेत (जी.आई.) टैग प्रदान किया गया है।
- यह एक विशिष्ट प्रकार की मिट्टी में उगता है जो कश्मीर घाटी में पाई जाती है जिसे करेवास मिट्टी कहा जाता है।

संबंधित जानकारी

भौगोलिक संकेत

- यह उन उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेत है, जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उसमें गुण या प्रतिष्ठा उसके मूल क्षेत्र के कारण होती है।
- जी.आई. के रूप में कार्य करने के लिए किसी चिन्ह को किसी दिए गए स्थान पर उत्पन्न होने वाले उत्पाद की पहचान करनी चाहिए।

जी.आई. टैग- ट्रिप्स समझौते की आवश्यकता

- भारत ने विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में भौगोलिक उत्पाद संकेतक (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 को लागू किया है, यह 15 सितंबर, 2003 से प्रभावी हो गया है।
- दार्जिलिंग चाय, पहला भारतीय उत्पाद था जिसे भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया था। वर्ष 2004 में इस प्रसिद्ध पेय को मान्यता प्राप्त हुई थी।

हाल ही में, प्रदान किए गए जी.आई. टैग

- 'ओडिशा रसागोला'
- मरायुर गुड़- केरल
- इरोड हल्दी- तमिलनाडु
- पलानी मंदिर का पंचमीर्थम- तमिलनाडु
- तावल्लोहपुआन- मिज़ोरम
- मिज़ो पुआंची- मिज़ोरम
- तिरूर पान का पत्ता- केरल

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नैंस

स्रोत- द हिंदू

3. **<u>रेडियोएक्टिव सीज़ियम तकनीक: मृदा क्षरण को मापने हेतु विकसित की गई नई विधि</u>**

- देहरादून स्थित आई.सी.ए.आर.- भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के शोधकर्ताओं ने रेडियोएक्टिव सीज़ियम तकनीक विकसित की है।

संबंधित जानकारी

रेडियोधर्मी सीज़ियम प्रौद्योगिकी

- गंभीर रूप से सघन कृषि भूमि में मृदा क्षरण का अध्ययन करने के लिए रेडियोएक्टिव सीज़ियम तकनीक अधिक तेज और कम खर्चीली विधि है।
- यह ऐतिहासिक, तुलनात्मक और दीर्घकालिक मिट्टी और मृदा कार्बनिक कार्बन क्षरण सहित सभी प्रकार के क्षरण के अध्ययनों के लिए अधिक सटीक परिणाम देता है।
- यह मिट्टी में रेडियोधर्मी सीज़ियम के स्तर के साथ इसे सहसंबंधित करके मृदा क्षरण और मिट्टी में कार्बन की मात्रा में कमी की निगरानी करने में मदद करता है।

सीज़ियम

- यह एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Cs और परमाणु संख्या 55 है।
- यह 28.5 डिग्री सेल्सियस के गलनांक के साथ एक नरम, चांदी-सुनहरी क्षार धातु है, जो इसे केवल पांच तत्व धातुओं में से एक बनाता है जो कमरे के तापमान पर या उसके लगभग तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत- डाउन टू अर्थ

4. **<u>प्रखर वैन</u>**

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में प्रखर वैन सड़क अपराध गश्ती वैन का शुभारंभ किया है।

प्रखर

- यह अपराध के स्थल पर गश्त करने के लिए एक सड़क अपराध गश्ती वैन है।
- प्रखर वैन, पी.सी.आर. से अलग हैं क्यों कि ये वैन अधिक मारक क्षमता रखती हैं और यह आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

5. **<u>मालाबार 2019 युद्धाभ्यास</u>**

- त्रिपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास मालाबार के 23वें संस्करण का आयोजन भारत, जापान और अमेरिका की नौसेनाओं के मध्य जापान के तट पर किया जाना निर्धारित किया गया है।

संबंधित जानकारी

युद्धाभ्यास के संदर्भ में जानकारी

- यह भारत-जापान-अमेरिका नौसेनाओं को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा।
- मालाबार युद्धाभ्यास वर्ष 1992 में भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। वर्ष 2015 में जापान को शामिल करने के साथ इसे एक त्रिपक्षीय प्रारूप में विस्तारित किया गया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –रक्षा

स्रोत- पी.आई.बी.

6. **<u>कोयला गैसीकरण, भारत की अपने ऊर्जा आयात को कम करने में मदद कर सकता है।</u>**

- ओडिशा के तलचर उर्वरक संयंत्र को यूरिया और अमोनिया के उत्पादन के लिए कोयला गैसीकरण इकाई शुरू करने हेतु एक अनुबंध से सम्मानित किया गया है।
- यह भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड (एफ.सी.आई.एल.) और हिंदुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड (एच.एफ.सी.एल.) से संबंधित बंद हो चुकें उर्वरक संयंत्रों को पुनर्जीवित करने की सरकार की पहल का हिस्सा था।

संबंधित जानकारी

कोयला गैसीकरण

- यह कोयले को संश्लेषित गैस (जिसे सिनगैस भी कहा जाता है) में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है, जो हाइड्रोजन (H_2), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का मिश्रण है।
- सिनगैस का उपयोग बिजली का उत्पादन करने और उर्वरक जैसे रासायनिक उत्पाद बनाने जैसे विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जा सकता है ।
- कोयला गैसीकरण से प्राप्त हाइड्रोजन का उपयोग अमोनिया बनाने, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को शक्ति देने या जीवाश्म ईंधन को उन्नत करने जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।
- वर्ष 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूमिगत कोयला गैसीकरण प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की थी।
- भूमिगत कोयला गैसीकरण (यू.सी.जी.) एक औद्योगिक प्रक्रिया है, जो कोयले को उत्पाद गैस (प्रमुख उत्पाद गैसें मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड) में परिवर्तित करती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –भूगोल

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

7. **सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार**

- भारत सरकार ने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की स्थापना की है, जो भारत की एकता और अखंडता में योगदान हेतु सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।

पुरस्कार के संदर्भ में जानकारी

- यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के कारणों को बढ़ावा देने वाले योगदान की पहचान करता है।
- यह प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस अर्थात 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर प्रदान किया जाता है।
- यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार प्रस्तुति समारोह के साथ प्रस्तुति समारोह में दिया जाएगा।

पुरस्कार समिति

- एक पुरस्कार समिति का गठन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा, जिसमें सदस्य के रूप में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, राष्ट्रपति के सचिव, गृह सचिव और प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए तीन-चार प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे।

पात्रता

- सभी नागरिक, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उम्र या व्यवसाय के भेदभाव के बिना इस पुरस्कार के पात्र होंगे और कोई भी संस्थान/ संगठन भी इस पुरस्कार के लिए पात्र होगा।
- एक वर्ष में तीन से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे।
- यह बहुत ही दुर्लभ और उच्च योग्य मामलों को छोड़कर मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाएगा।

टॉपिक- यू.पी.एस.सी. और राज्य पी.सी.एस. प्रारंभिक परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण

स्रोत- टी.ओ.आई.

8. **हेड ऑन जनरेशन (एच.ओजी.) तकनीक**

- हाल ही में, रेलवे मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह सभी मौजूदा लिंक हॉफमैन बुश (एल.एच.बी.) कोचों को हेड ऑन जनरेशन (एच.ओ.जी.) तकनीक से अपग्रेड करेगा।

एच.ओ.जी. तकनीक के संदर्भ में जानकारी

- इस तकनीक में बिजली को भूमि के ऊपर की विद्युत आपूर्ति से लिया जाएगा।
- एक फेस में भूमि के ऊपर से तारों से बिजली की आपूर्ति 750 वोल्ट है और एक 945 केवीए की वाइंडिंग का ट्रांसफॉर्मर 3 चरण में 750 वोल्ट 50 हर्ट्ज आउटपुट में परिवर्तित करता है।
- फिर यह बिजली कोचों को प्रदान की जाती है।

- एच.ओजी. प्रणाली वायु और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त है जो वार्षिक CO2 और NOx उत्सर्जन को लगभग शून्य तक कम कर देगा है।

संबंधित जानकारी

एल.एच.बी. कोच के संदर्भ में जानकारी

- लिंक हॉफमैन बुश कोच, भारतीय रेलवे के यात्री कोच हैं जिन्हें जर्मनी के लिंक-हॉफमैन-बुश द्वारा विकसित किया गया है।
- ये कोच पंजाब के कपूरथला में रेल कोच फैक्टरी में बनाए जाते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत- टी.ओ.आई.

9. **<u>राइट लाइवलीहुड पुरस्कार</u>**

- स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, राइट लाइवलीहुड अवार्ड के विजेता के रूप में नामित चार लोगों में से एक हैं, जिसे 'वैकल्पिक नोबेल' के रूप में भी जाना जाता है।
- वैज्ञानिक तथ्यों को प्रतिबिंबित करने वाली तत्काल जलवायु कार्रवाई के लिए राजनीतिक मांगों को प्रेरित करने और बढ़ाने के लिए थनबर्ग को मान्यता दी जा रही है।

संबंधित जानकारी

राइट लाइवलीहुड अवार्ड

- यह आज दुनिया के सामने आने वाली सबसे जरूरी चुनौतियों के लिए व्यावहारिक और अनुकरणीय जवाब देने वालों का सम्मान और समर्थन करने हेतु एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है।
- इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1980 में जर्मन-स्वीडिश परोपकारी जैकब वॉन उक्सकुल द्वारा की गई थी और इसे प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
- यह पुरस्कार, नोबेल फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय विकास के क्षेत्र में सम्मानजनक प्रयासों को पुरस्कार देने से इनकार करने के बाद बनाया गया था।

टॉपिक- यू.पी.एस.सी. और राज्य पी.सी.एस. प्रारंभिक परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण

स्रोत- द हिंदू

10. **<u>सरकार ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है।</u>**

- भारत सरकार ने दो वर्षों के लिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है, जो 26 सितंबर, 2019 से प्रभावी हो गई है।
- बिबेक देबरॉय और रतन पी. वाटल पुनर्गठित ई.ए.सी.-पी.एम. के क्रमशः अध्यक्ष और सदस्य सचिव बने रहेंगे।

संबंधित जानकारी

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद

- यह भारत सरकार को विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देने हेतु एक स्वतंत्र निकाय है।

कार्य

- प्रधानमंत्री द्वारा संदर्भित किसी भी मुद्दे का विश्लेषण करना, चाहे वह आर्थिक मुद्दा हो अथवा कोई अन्य मुद्दा हो।
- मैक्रो इकानॉमी के महत्व को संबोधित करना, यह स्व-प्रेरक अथवा प्रधानमंत्री द्वारा संदर्भित अथवा किसी अन्य द्वारा संदर्भित हो सकता है।
- समय-समय पर प्रधानमंत्री द्वारा वांछित किसी अन्य कार्य में भाग लेना

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

11. **<u>प्रधानमंत्री ने कैरिबियन में विकासात्मक परियोजनाओं के लिए $14 मिलियन के अनुदान की घोषणा की है।</u>**

- प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सीमांतों पर कैरेबियाई समुदाय और

कॉमन मार्केट (CARICOM) के सदस्य राज्यों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की है।

- बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने कैरिबियाई समुदाय और कॉमन मार्केट (CARICOM) में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 14 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान और सौर, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिए 150 मिलियन अमरीकी डालर ऋण व्यवस्था की घोषणा की है।

संबंधित जानकारी

- CARICOM कैरेबियन में 20 विकासशील देशों का एक समूह है जो एक आर्थिक और राजनीतिक समुदाय बनाने के लिए एक साथ आए हैं जो इस क्षेत्र के लिए नीतियों को आकार देने और आर्थिक विकास और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए मिलकर काम करते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –भारत एवं विश्व

स्रोत- इंडिया टुडे

27.09.2019

1. **<u>इंडिया टी.बी. रिपोर्ट 2019</u>**

- केंद्र ने इंडिया टी.बी. रिपोर्ट 2019 जारी की है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018 में मामलों की संख्या में 16% की वृद्धि हुई है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 लाख टी.बी. के मामलों को संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) 2018 में अधिसूचित किया गया है, भारत, इस वर्ष 27 लाख नए मामलों के अनुमानित आंकड़े के साथ वैश्विक टी.बी. मामलों के एक-चौथाई हेतु जिम्मेदार है।
- प्रभावित व्यक्तियों में से अधिकांश व्यक्ति (89%) 15-69 वर्ष आयु वर्ग के थे।
- उत्तर प्रदेश ने देश की 17% आबादी के साथ 4.2 लाख मामलों को दर्ज किया है, जो सभी अधिसूचनाओं के 20 प्रतिशत हेतु जिम्मेदार है।
- ओडिशा ने अधिसूचित मामलों की संख्या में वर्ष 2017 में 67,000 की तुलना में वर्ष 2018 में 50,244 मामले दर्ज किए हैं अर्थात 25 प्रतिशत की कमी दर्ज की है। ओडिशा, एकमात्र ऐसा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेशों लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ने भी गिरावट दर्ज की है।
- दिल्ली और चंडीगढ़ के दो संघ शासित प्रदेशों में प्रति लाख आबादी पर सबसे अधिक अधिसूचित मरीज क्रमशः 417 और 468 थे।

संबंधित जानकारी

- भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एच.आई.वी. मामलों वाला देश है, जिसमें वयस्कों का प्रतिशत 22% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एच.आई.वी. से पीड़ित मरीजों में टी.बी. होने का खतरा 21 गुना अधिक होता है। एच.आई.वी. से पीड़ित व्यक्तियों में होने वाली सभी मौतों में से लगभग 25 प्रतिशत मौते टी.बी. के कारण होने का अनुमान है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –स्वास्थ्य मुद्दे

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

2. **<u>पहली स्वदेशी ईंधन सेल प्रणाली</u>**

- भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय उद्योगों के साथ साझेदारी में सी.एस.आई.आर. द्वारा विकसित पहली स्वदेशी उच्च तापमान ईंधन सेल प्रणाली का अनावरण किया है।
- इसे भारत के प्रमुख कार्यक्रम "नई सहस्त्राब्द भारतीय प्रौद्योगिकी लीडरशिप पहल" (NMITLI) के अंतर्गत विकसित किया गया है।
- यह एक 0 किलोवॉट की ईंधन सेल प्रणाली है जो भविष्य में उपयोग करने हेतु मेथनॉल/ जैव-मीथेन का उपोत्पाद के रूप में ऊष्मा और जल

के साथ उपयोग करके हरित ढंग से बिजली उत्पन्न करती है, जो 70 प्रतिशत दक्षता हेतु उत्तरदायी है, जो किसी अन्य ऊर्जा स्रोत द्वारा संभव नहीं है।

- विकसित किया गया ईंधन सेल, उच्च तापमान प्रोटॉन विनिमय झिल्ली (एच.टी.पी.ई.एम.) प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं।
- यह विकास डीजल जनरेटिंग (डी.जी.) सेटों को प्रतिस्थापित करेगा और कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा।
- ईंधन सेल प्रौद्योगिकी का विकास स्वदेशी है और गैर-ग्रिड ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय महत्व रखता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

3. **<u>प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के समूह हेतु ऋण</u>**

- हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने सौर, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु से संबंधित परियोजनाओं के उपक्रम के लिए प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के समूह को 150 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण देने की घोषणा की है।
- उन्होंने आपदा तन्यक ढांचा गठबंधन में शामिल होने के लिए भारत-प्रशांत द्वीप विकासशील देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है।

संबंधित जानकारी

प्रशांत छोटा द्वीप विकासशील राज्य (पी.एस.आई.डी.एस.)

- पी.एस.आई.डी.एस., 14 प्रशांत द्वीप देशों अर्थात द कुक द्वीप, माइक्रोनेशिया संघीय राज्य, फिजी, किरिबाती नाउरू, नीयू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, मार्शल द्वीप, समोआ, सोलोमन द्वीप, टोंगा, तुवालु और वनुआतु से मिलकर बना है।

भारत और पी.एस.आई.डी.एस. के संबंध

- प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध अधिनियम पूर्व नीति के विकास के साथ घनिष्ठ हो गए है, जिसके परिणामस्वरूप कार्रवाई उन्मुख भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग (एफ.आई.पी.आई.सी.) फोरम की स्थापना हुई है।
- भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम, भारत और 14 प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के बीच सहयोग के लिए वर्ष 2014 में विकसित एक बहुराष्ट्रीय समूह है।

ऋण व्यवस्था (लाइन ऑफ क्रेडिट)

- यह एक बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा सरकार, व्यवसाय या एक व्यक्तिगत ग्राहक को दी जाने वाली एक ऋण सुविधा है, जो ग्राहक को अधिकतम ऋण राशि प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- उधारकर्ता किसी भी समय लाइन ऑफ क्रेडिट से निधि प्राप्त कर सकते हैं, उधारकर्ता तब तक ही धन प्राप्त कर सकते हैं जब तक कि उन्होंने समझौते में उल्लेखित अधिकतम धनराशि (अथवा ऋण सीमा) को प्राप्त नहीं किया है और समय पर न्यूनतम भुगतान करने जैसी किसी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नैंस

स्रोत- पी.आई.बी.

4. **<u>वैश्विक आतंकवाद निपटान इंटरनेट फोरम (जी.आई.एफ.सी.टी.), एक स्वतंत्र निकाय होना चाहिए।</u>**

- वैश्विक आतंकवाद निपटान इंटरनेट फोरम, अब एक कार्यकारी निदेशक के नेतृत्व में एक स्वतंत्र संगठन बन जाएगा।
- यह फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर और यूट्यूब द्वारा स्थापित किया गया है।
- इस फोरम का मुख्य उद्देश्य आतंकवादियों और हिंसक चरमपंथियों को उनके संबंधित प्लेटफार्मों पर आतंकवादी दुरुपयोग को बाधित करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म का शोषण करने से रोकना है और यह समर्पित प्रौद्योगिकी, आतंकवाद और संचालन टीमों द्वारा समर्थित है।

- इसे वर्ष 2017 में सरकारों की एक श्रृंखला के साथ काम करने के लिए स्थापित किया गया था, विशेष रूप से यूरोपीय संघ इंटरनेट फोरम के तत्वावधान में काम करने हेतु स्थापित किया गया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3–विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत- टी.ओ.आई.

5. **परागण अभ्यारण्य: कनाडा का एक नया स्थायी समाधान मॉडल है।**

- हाल ही में, कनाडा के प्रांत के फार्मिंग स्मार्टर नामक एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान संगठन ने परागण अभयारण्य नामक एक अवधारणा पेश की है।
- एक परागण अभयारण्य, परागण कीट संरक्षण के क्षेत्र में एक शक्तिशाली तकनीक साबित हो सकती है, जिसमें मधुमक्खियों और देशी मधुमक्खियों पर विशेष जोर दिया जाता है।
- इस परागण अभ्यारण्य परियोजना को मधुमक्खी संरक्षण के लिए एक नए स्थायी और अभिनव प्रौद्योगिकी मंच की जांच करने के लिए कैनेडियन एग्रीकल्चर पार्टनरशिप नामक सुप्रसिद्ध प्रांतीय वित्त पोषण कार्यक्रम द्वारा वित्त पोषित किया गया है।

संबंधित जानकारी

परागण कीट

- परागण कीट, फसलों और पौधों की एक विस्तृत विविधता में क्रॉस परागण को प्राप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं जो मानव पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- कृषि, वानिकी और मधुमक्खीपालन जैसे तीन अलग-अलग वैश्विक उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जैविक एजेंटों या वैक्टर जैसे कि कीटों, मोलस्क (जैसे घोंघे और स्लग), पक्षियों (चिड़ियों की तरह प्रजातियों) और स्तनधारियों (जैसे: चमगादड़) द्वारा प्रदान की जाने वाली परागण सेवाओं पर निर्भर होते हैं।
- मधुमक्खियों, पतंगों और तितलियों जैसे कीड़े, मक्खियों, झींगुर, ततैया और चींटियों की कुछ प्रजातियां विभिन्न महत्वपूर्ण फसलों और पौधों की प्रजातियों में क्रॉस परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- कीटों में मधुमक्खियां पौधों की व्यापक विविधता को परागण सेवाएं प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- डाउन टू अर्थ

6. **हाथी एंडोथीलियोट्रॉपिक हर्पसवायरस (ई.ई.एच.वी.)**

- हाल ही में, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क (ओडिशा) में हाथी एंडोथिलियोट्रॉपिक हर्पसवायरस के कारण चार हाथियों की मृत्यु हो गई हैं।

संबंधित जानकारी

हाथी एंडोथिलियोट्रॉपिक हर्पसवायरस

- इसे एलिफेंटिड बीटाहर्पसवायरस 1 (ई.आई.एच.वी.-1) के रूप में भी जाना जाता है।
- यह एक प्रकार का हर्पसवायरस होता है, जो युवा एशियाई हाथियों में प्रेषित होने पर अत्यधिक घातक रक्तस्रावी बीमारी का कारण बन सकता है।
- ई.ई.एच.वी. से निपटने के लिए कोई दवा विकसित नहीं की हुई है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत- द हिंदू

7. **112, भारत का नया सर्वउद्देशीय आपातकालीन नंबर है।**

- पुदुचेरी, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बाद दिल्ली पांचवा केंद्रशासित प्रदेश बन गया है

जिसने फरवरी, 2019 को आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली (ई.आर.एस.एस.) के उद्घाटन बाद इसे लागू किया है।

- नवंबर, 2018 में हिमाचल प्रदेश ई.आर.एस.एस. को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया था, जिसके अंतर्गत पूरे देश में एकल आपातकालीन रिसपांस नंबर-112 है।
- मौजूदा आपातकालीन नंबरों जैसे पुलिस के लिए 100, आग के लिए 101, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 108, महिलाओं के हेल्पलाइन 1091 और 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 आदि को धीरे-धीरे 112 के अंतर्गत एकीकृत किया जाएगा।
- एक "112 भारत" ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता पंजीकरण करने के बाद पुलिस, स्वास्थ्य, अग्नि और अन्य सेवाओं तक पहुंच सकते हैं।
- 112, यूरोप के अधिकांश देशों सहित कई अन्य देशों में भी सामान्य आपातकालीन नंबर है।

संबंधित जानकारी

- गृह मंत्रालय ने दिसंबर, 2012 में निर्भया की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पृष्ठभूमि में न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और 'आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली' के नाम से एक राष्ट्रीय परियोजना को मंजूरी प्रदान की है, जिसे पहले राष्ट्रव्यापी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के रूप में संदर्भित किया जाता था। सभी प्रकार की आपातकालीन कॉल जैसे पुलिस, आग और एम्बुलेंस आदि को संबोधित करने के लिए एक पैन-इंडिया सिंगल इमरजेंसी रिस्पांस नंबर जारी करने के दृष्टिकोण से '112' को जारी किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

8. **<u>2I/ बोरिसोव: दूसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है।</u>**

- अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (आई.ए.यू.) के अनुसार, हमारे सौर मंडल में आधिकारिक तौर पर दूसरे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का पता चला है।

संबंधित जानकारी

2I/बोरिसोव

- 2आई./ बोरिसोव में, I "इंटरस्टेलर" को और 2, अभी तक खोजे गए दूसरे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को दर्शाता है, जिसे 'ओउमुआमुआ' के बाद खोजा गया था, जिसका पता अक्टूबर, 2017 में चला था।
- यह 'ओउमुआमुआ' के बाद पहला देखा गया धूमकेतु और दूसरा देखा गया इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है।
- यह 2 और 16 किलोमीटर व्यास के बीच है, जिसकी रासायनिक संरचना सौर प्रणाली के लंबे अवधि के धूमकेतु के समान है जो कि दूर स्थित ऊर्ट बादल में उत्पन्न होती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत- हिंदूस्तान टाइम्स

9. **<u>भागीदारी गारंटी योजना</u>**

- भारत के खाद्य सुरक्षा विनियामक के प्रमुख ने कहा है कि वह केंद्रीय कृषि मंत्रालय की भागीदारी गारंटी योजना (पी.जी.एस.) से अपेक्षा करती हैं कि यह किसानों को अधिक अधिक जैविक खाद्य उगाने हेतु प्रोत्साहित करेगी।

संबंधित जानकारी

योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने की एक प्रक्रिया है, जो सुनिश्चित करता है कि उनका उत्पादन निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार हो रहा है।
- यह प्रमाणन एक प्रलेखित लोगो या एक कथन के रूप में है।
- यह योजना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू जैविक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली भी है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

30.09.2019

1. **शोधकर्ताओं ने यूरोप के अंतर्गत खोए हुए 8वें महाद्वीप "ग्रेटर एड्रिया" की खोज की है।**

- भूवैज्ञानिकों ने पिछले 10 वर्षों से स्पेन से ईरान तक सभी पर्वत श्रृंखलाओं का विश्लेषण करने के बाद भूमध्यसागरीय क्षेत्र में छिपे एक नए महाद्वीप की खोज की है।
- गोंडवाना रिसर्च नामक पत्रिका में प्रकाशित इस शोध में ज्ञात हुआ है कि किस प्रकार ग्रीनलैंड के आकार का महाद्वीपीय भूपटल, एक बार उत्तरी अफ्रीका से अलग होकर दक्षिणी यूरोप के अंतर्गत पृथ्वी के मेंटल में समा गया था।
- इससे पृथ्वी पर आठवें महाद्वीप का निर्माण हुआ था, महाद्वीपीय भूपटल के इस टुकड़े को ग्रेटर एड्रिया कहा जाता है।
- अधिकांश पर्वत श्रृंखलाएं जिनकी हमने जांच की है, वे एक ही महाद्वीप से उत्पन्न हुई हैं जो 200 मिलियन वर्ष पहले उत्तरी अफ्रीका से अलग हुई थीं।
- इस महाद्वीप का एकमात्र शेष हिस्सा एक पट्टी है जो ट्यूरिन से एड्रियाटिक सागर से होते हुए इटली का निर्माण करने वाले हील ऑफ द बूट जाती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1- प्राकृतिक भूगोल

स्रोत- पी.आई.बी.

2. **काजिंद युद्धाभ्यास- 2019**

- यह भारत और कजाकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का चौथा संस्करण है जो पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा।
- यह एक वार्षिक कार्यक्रम भी है जो कजाकिस्तान और भारत में एकांतर रूप से आयोजित किया जाता है।
- इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद-रोधी अभियानों पर जोर देने के साथ कंपनी स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण का संचालन करना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 – रक्षा

स्रोत- पी.आई.बी.

3. **10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति (2019-2029) का राष्ट्रीय शुभारंभ**

- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डी.डी.डब्ल्यू.एस.), भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने 10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति (2019-2029) लांच की है।

संबंधित जानकारी

ग्रामीण स्वच्छता रणनीति के संदर्भ में जानकारी

- यह रणनीति राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के परामर्श से जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा तैयार की गई है।
- यह स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एस.बी.एम.-जी.) के अंतर्गत से हासिल किए गए स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन को क्षमता सुदृढ़ीकरण, सूचना, शिक्षा और संचार, जैविक अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रेवाटर प्रबंधन और काला पानी प्रबंधन के माध्यम से स्थायी बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- इसने खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) प्लस के लिए अपनी योजना में स्थानीय सरकारों, नीति निर्धारकों, कार्यान्वयनकर्ताओं और अन्य संबंधित हितधारकों का मार्गदर्शन करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है।

स्वच्छ भारत मिशन

- स्वच्छ भारत मिशन को अक्टूबर, 2014 में लांच किया गया था, यह दो उप-मिशनों से मिलकर बना हैं-
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एस.बी.एम.-जी.), जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाएगा
- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), जिसे शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा
- एस.बी.एम.-जी., स्वच्छता तक पहुंच में सुधार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2019 तक खुले में शौच को समाप्त करना चाहता है।
- यह समुदायों को स्थायी स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करने और स्वच्छता के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु जागरूक करने का प्रयास भी करता है।

एस.बी.एम.-जी. के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:

1. स्वच्छता को बढ़ावा देने और वर्ष 2019 तक खुले में शौच को समाप्त करने के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना
2. स्थायी स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने के लिए समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रेरित करना

खुले में शौच के संदर्भ में जानकारी

- यह उन प्रथाओं को संदर्भित करता है जिसके अंतर्गत लोग शौच करने के लिए शौचालय का उपयोग करने के बजाय खेतों, झाड़ियों, जंगलों, पानी के खुले निकायों या अन्य खुले स्थानों में जाते हैं।
- किसी शहर या वार्ड को खुले में शौच मुक्त के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है यदि दिन के किसी भी समय, एक भी व्यक्ति खुले में शौच करते हुए नहीं पाया जाता है।
- ओ.डी.एफ.+ रणनीति उनकी कार्यक्षमता, स्वच्छता और रखरखाव को सुनिश्चित करके सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालय के उपयोग को बनाए रखने पर केंद्रित है।
- इसके अतिरिक्त ओ.डी.एफ.++ प्रोटोकॉल में व्यक्तिगत शौचालय तक पहुँच में सुधार, समुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव, कार्यक्षमता और तरल अपशिष्ट/ मल अपशिष्ट और सेप्टेज प्रबंधन तक बेहतर पहुंच सहित सतत पहलू शामिल हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

4. **<u>नौसेना का पहला नया स्टील्थ युद्धपोत: आई.एन.एस. नीलगिरि</u>**

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में नौसेना का पहला नया स्टील्थ युद्धपोत, आई.एन.एस. नीलगिरि लॉन्च किया है।

संबंधित जानकारी

आई.एन.एस. 'नीलगिरि'

- यह प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत नौसेना के सात नए स्टील्थ युद्धपोतों में से पहला है।
- प्रोजेक्ट 17A युद्धपोत, शिवालिक वर्ग के स्टील्थ युद्धपोत का डिजाइन व्युत्पन्न है, जिसमें बहुत अधिक उन्नत स्टील्थ विशेषताएं और स्वदेशी हथियार और सेंसर हैं।
- ये युद्धापोत एकीकृत निर्माण पद्धति का उपयोग करके बनाए जा रहे हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –रक्षा

स्रोत- ए.आई.आर.

5. **<u>छात्र ने एक हीरे के अंदर एक नए खनिज "गोल्ड्समिडटाइट" की खोज की है।</u>**

- अल्बर्टा विश्वविद्यालय के पी.एच.डी. छात्र निकोल मेयर द्वारा एक नए और जिज्ञासु खनिज की खोज की गई है। इस खनिज का नाम, आधुनिक भू-रसायन विज्ञान के संस्थापक विक्टर मोरिट्ज गोल्डस्मिड के नाम पर

गोल्ड्समिडटाइट रखा गया है, जिसके पृथ्वी के मेंटल से खनिज के लिए एक असामान्य रासायनिक हस्ताक्षर है।

- गोल्ड्समिडटाइट में नीकोबियम, पोटेशियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों लैंथेनम और सीरियम की उच्च सांद्रता है, जबकि शेष मेंटल में मैग्नीशियम और लोहे जैसे अन्य तत्वों का प्रभुत्व है।
- क्योंकि मेंटल तक पहुंचना अत्यंत मुश्किल है, इसलिए वैज्ञानिकों ने सतह के नीचे पृथ्वी के रासायनिक संघटन के बारे में अधिक जानने के लिए हीरे के भीतर छोटे खनिज समावेशन पर भरोसा किया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत- scitechdaily.com

6. **<u>मामूली ग्रह का नाम, पंडित जसराज के नाम पर रखा गया है।</u>**

- हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल और बृहस्पति के मध्य एक मामूली ग्रह का नाम 'पंडित जसराज' के नाम पर रखा है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख गायक हैं।
- वह यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय संगीतकार हैं।
- पंडित जसराज ग्रह को दी गई संख्या 300128 थी, जो कि उनकी जन्मतिथि 28/01/30 का उल्टा क्रम है।

संबंधित जानकारी

ग्रह के संदर्भ में जानकारी

- इस ग्रह की खोज 11 नवंबर, 2006 को की गई थी।
- यह क्षुद्रग्रह है, जिसे औपचारिक रूप से मामूली ग्रह के रूप में जाना जाता है जिसे एरिजोना आधारित दूरदर्शी से कैटेलिना स्काई सर्वेक्षण द्वारा खोजा गया था।

अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ

- इसे वर्ष 1919 में स्थापित किया गया था, इस संगठन का उद्देश्य हर पहलू में खगोलीय विज्ञान को बढ़ावा देना और सुरक्षित करना था।
- यह संगठन खगोलीय पिंडो को नाम और पद देने वाले प्राधिकरणों की पहचान करता है।
- आई.ए.यू. महासभा का आयोजन 3 वर्षों में एक बार होता है।
- पिछली आई.ए.यू. महासभा का आयोजन वर्ष 2018 में ऑस्ट्रिया के वियना में किया गया था।
- अगली आई.ए.यू. महासभा का आयोजन वर्ष 2021 में दक्षिण कोरिया के बुसान में किया जाएगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –कला एवं संस्कृति

स्रोत- पी.आई.बी.

7. **<u>ओडिशा ने बच्चों, महिलाओं में कुपोषण से लड़ने के लिए 'टिक्की मौसी' का अनावरण किया है।</u>**

- संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के सहयोग से ओडिशा सरकार ने 'टिक्की मौसी' नाम के एक शुभंकर का अनावरण किया है।

शुभंकर के संदर्भ में जानकारी

- इस शुभंकर का उद्देश्य सामान्य लोगों के व्यवहार को बदलना और उन्हें प्रत्येक घर में बच्चों और महिलाओं के पोषण और विकास के बारे में जागरूक करना है।
- बच्चे की दूसरी माँ के संदर्भ में शुभंकर को 'टिक्की मौसी' नाम दिया गया है। यह बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य की देखभाल और उनके विकास के लिए जागरूकता फैलाने हेतु प्रस्तावित है।
- यह राज्य में बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए प्रत्येक घर में महिलाओं और बच्चों के लिए सरकारी परियोजनाओं के बारे में सही जानकारी प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

सम्बंधित जानकारी

संयुक्त राष्ट्र अंतराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष

- यह कोष वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बनाया गया था।
- यह संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) का एक विशेष कार्यक्रम है जो बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामान्य कल्याण में सुधार के लिए राष्ट्रीय प्रयासों को सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

8. **वाई.एस.आर. रायथु भरोसा योजना**

- आंध्र प्रदेश सरकार, किसानों के लिए एक योजना शुरू करने जा रही है जिसका नाम वाई.एस.आर. रायथु भरोसा योजना है।

संबंधित जानकारी

योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार की 9 नवरत्न कल्याण योजनाओं में से एक है।
- इस योजना का उद्देश्य किसानों को मौद्रिक सहायता प्रदान करना है जिसमें वे भूमिहीन और किरायेदार किसान शामिल होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.-किसान) योजना से बाहर रखा गया था।
- इस योजना के अंतर्गत, पाँच एकड़ तक की जमीन रखने वाले प्रत्येक किसान को 12500 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस राशि में केंद्र द्वारा अपनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को प्रदान की जाने वाली 6,000 रुपये प्रति वर्ष की धनराशि भी शामिल है।
- यह योजना, तेलंगाना की रायथु बंधु योजना पर आधारित है, जिसके अंतर्गत भूमि मालिकों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये मिलते हैं लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार ने किरायेदार किसानों को भी शामिल करने का फैसला किया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- न्यूज 18

9. **'उद्योग 4.0' की शुरूआत करने हेतु रायबरेली की कोच फैक्ट्री में परीक्षण परियोजना**

- हाल ही में, देश में उद्योग 4.0 की शुरुआत करने के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में आधुनिक कोच फैक्ट्री में रेलवे द्वारा एक परीक्षण परियोजना को शुरू किया गया है।
- यह परियोजना "भारतीय रेलवे प्रौद्योगिकी मिशन" के तत्वावधान में शुरू की जाएगी।
- इसे रेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक संघ द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

संबंधित जानकारी

उद्योग 4.0

- इसे सामान्यत: चौथी औद्योगिक क्रांति के रूप में संदर्भित किया जाता है, यह उत्पादकता बढ़ाने के लिए विनिर्माण प्रौद्योगिकियों में डाटा विनिमय, इंटरकनेक्टिविटी और स्वचालन की वर्तमान प्रवृत्ति को दिया गया एक नाम है।
- उद्योग 4.0, एक जटिल साइबर-भौतिक प्रणाली है जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा, विश्लेषण, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ उत्पादन को समन्वित करती है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –ढांचा

स्रोत- हिंदुस्तान टाइम्स

10. **विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2019**

- विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2019 अंतर्राष्ट्रीय विश्व प्रतिस्पर्धात्मक प्रबंधन विकास केंद्र संस्थान द्वारा जारी की गई है।
- यह व्यापार, सरकार और व्यापक समाज में आर्थिक परिवर्तन के लिए एक प्रमुख चालकों के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने और तलाशने के लिए 63 देशों की क्षमता और तत्परता को मापती है।

- देशों को तीन कारकों के आधार पर स्थान प्रदान किया जाता है जो हैं:
- ज्ञान- नई तकनीकों को समझने और सीखने की क्षमता
- प्रौद्योगिकी- नए डिजिटल नवाचारों को विकसित करने की क्षमता
- भविष्य की तत्परता- आने वाले घटनाक्रमों की तैयारी

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- भारत वर्ष 2018 में 48वें स्थान से घटकर 2019 में 44वें स्थान पर पहुंचा है क्यों कि देश ने पिछले वर्ष की रैंकिंग की तुलना में सभी कारकों अर्थात ज्ञान, प्रौद्योगिकी और भविष्य की तत्परता में समग्र सुधार किया है।
- दूरसंचार निवेश में पहला स्थान प्राप्त करने वाले प्रौद्योगिकी उप-कारक स्तर में सबसे अधिक सुधार हुआ है।
- अमेरिका को दुनिया की सबसे डिजिटल प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान प्रदान किया गया है, इसके बाद सिंगापुर दूसरे स्थान पर है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –महत्वपूर्ण रैंकिंग

स्रोत- टी.ओ.आई.

11. **<u>महासागरों और क्रायोस्फेयर पर आई.पी.सी.सी. रिपोर्ट</u>**

- जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ने बदलती जलवायु के संदर्भ में महासागर और क्रायोस्फेयर पर विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
- यह तीन रिपोर्टों की एक श्रृंखला में अंतिम रिपोर्ट है जिसे विशिष्ट विषयों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए आई.पी.सी.सी. को तैयार करने के लिए कहा गया था।
- इनमें से पहला, पूर्व-औद्योगिक समय से 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर तापमान में वैश्विक वृद्धि को प्रतिबंधित करने की व्यवहार्यता की जांच करना है जिसे पिछले वर्ष अक्टूबर में सौंपा गया था।

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- वर्ष 1902 और 2015 के बीच वैश्विक औसत समुद्र स्तर 16 सेमी बढ़ गया था और पिछले दशक में वृद्धि की दर दोगुनी हो गई थी।
- तापमान बढ़ने के साथ ही ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ के पिघलने के कारण समुद्री जल के ऊष्मीय विस्तार से समुद्री स्तर में वृद्धि हो रही है।
- वर्ष 2006 और 2015 के बीच, ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर प्रत्येक वर्ष औसतन 278 बिलियन टन की बर्फ-द्रव्यमान पिघल रहा है, जब कि अंटार्कटिक की बर्फ की चादर प्रत्येक वर्ष औसतन 155 बिलियन टन का द्रव्यमान पिघल रहा है।
- इन दो क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में बर्फ, हिमालय के हिमनदों की तरह प्रत्येक वर्ष औसतन 220 बिलियन टन बर्फ पिघल जाती है।

अन्य रिपोर्ट

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने सितंबर, 2019 को एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2015-19 की अवधि आंकड़ों सबसे गर्म पांच साल की अवधि थी और इस वर्ष जुलाई, विश्व स्तर रिकॉर्ड पर सबसे गर्म महीना था।
- इस वर्ष 11 मई को वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वैश्विक सांद्रता को पहली पी.पी.एम में मापा गया था जो कि 415 पार्टस प्रति मिलियन (पी.पी.एम.) के चिन्ह से भी आगे निकल गई थी।

संबंधित जानकारी

क्रायोस्फ़ेयर

- यह पृथ्वी की सतह के उन हिस्सों के लिए एक सर्वव्यापी शब्द है जहां पानी ठोस रूप में होता है, जिसमें समुद्री बर्फ, झील की बर्फ, नदी की बर्फ, बर्फ का आवरण, ग्लेशियर, बर्फ की चादरें और जमी हुई जमीन (जिसमें पर्माफ्रॉस्ट शामिल हैं) शामिल हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

***

gradeup

65th BPSC
Test Series 2019

1. Based on the Latest Exam Pattern
2. All India Rank & Performance Analysis
3. Detailed Explanation of Solutions
4. Available on Mobile & Desktop

GET IT ON
Google Play

www.gradeup.co